संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 15 फरवरी 2025

मतभेदों के बीच मैत्री

बातचीत से तय होगा टैरिफ, ट्रेड का फ्रेमवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय अमेरिका यात्रा को विशेष माने जाने के एक नहीं, कई कारण रहे। यह दो 'बहुत अच्छे दोस्तों' की 'बेहद टफ नेगोशिएटर' को मुमकिन में देखने का एक दिलचस्प मौका तो थी ही, प्रतिकूल लगते हालात को अनुकूल नतीजों की ओर मोड़ने का कौशल भी इस यात्रा में बेहतरीन अंदाज में नजर आया।

संदेह की परतें | दोनों नेता न केवल पहले से एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते रहे हैं बल्कि उनके बीच की पसंनल केमेस्ट्री भी चर्चित रही है। दोनों देशों के लगातार बेहतर होते रिश्तों की पृष्ठभूमि इस तथ्य को और महत्वपूर्ण बना रही थी। फिर भी यात्रा से पहले के घटनाक्रम ने इसकी कामयाबी पर संदेह की परतें चढ़ा दी थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार टैरिफ का सवाल उठा रहे थे। यात्रा से ठीक पहले जिस तरह से भारत के इलीगल माइग्रेंट्स को सैनिक विमान में स्वदेश भेजा गया, उसने भी माहौल को बिगाड़ने में कम बड़ी भूमिका नहीं निभाई।

मोदी-ट्रंप: वही गर्मजोशी

आखिरी पलों में ऐलान | जो थोड़ी-बहुत कसर बाकी थी, वह भी आपसी मुलाकात से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान से पूरी हो गई कि अमेरिका समान टैरिफ की पॉलिसी पर चलेगा। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यह भारत को परोक्ष लेकिन सीधी चेतावनी थी।

'MAGA' का जवाब 'MIGA' से | इस माहौल में तनाव को हावी होने दिए बगैर पीएम मोदी अपने अजेंडे पर केंद्रित रहे। उन्होंने न केवल ट्रंप की तारीफ की बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रिय नारे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) की तर्ज पर अपना नारा पेश किया- 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' (MIGA), और यह भी कहा कि जब MAGA और MIGA साथ आते हैं तो बन जाता है MEGA जो दोनों देशों की शानदार साझेदारी की कहानी कहता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वह भी अपने राष्ट्रहित का अनुसरण करेंगे।

यूं बनी बात | इस कूटनीतिक कौशल का ही नतीजा था कि जो माहौल टकराव की ओर जाता दिख रहा था, वह सहयोग बढ़ाने के प्रयासों की ओर केंद्रित हो गया। न केवल टैरिफ जैसे मसलों पर फ्रेमवर्क बनाने की बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी बल्कि अंतरिक्ष यात्रा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर नजरें जम गईं। मुंबई टेरर अटैक के एक साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का राष्ट्रपति ट्रंप ने वही ऐलान भी कर दिया। निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच के कई समीकरण आने वाले दिनों में नया आकार लेंगे, लेकिन पीएम मोदी की यात्रा ने इस उम्मीद को ठोस आधार दे दिया है कि सहयोग के स्वरूप में जो भी बदलाव हो रिश्ता बेहतर ही होता जाएगा।

दो दूनी चार

SIP सही है, पर...

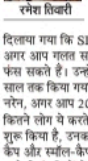

रमेश तिवारी

म्यूचुअल फंड में इन दिनों एक हॉट टॉपिक है, सिस्टैमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP कितना जोखिम भरा है। खास तौर से मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स से जुड़े फंड्स में। इस चर्चा को शुरू करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं एस. नरेन, जो एक प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने हाल ही में एक सम्मेलन में जो बयान दिया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें यह याद दिलाया गया कि SIP के जरिये भी पैसा बाजार में ही जा रहा है। इसलिए अगर आप गलत समय में गलत प्रॉडक्ट में पैसा लगाते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। उन्होंने इस बारे में इतिहास का भी हवाला दिया कि सात साल तक किया गया नियमित निवेश भी नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। बकौल नरेन, अगर आप 20 साल तक SIP करते हैं तो मुझे समस्या नहीं, लेकिन कितने लोग ये करते हैं। जिन लोगों ने 2023 में इन फंड्स में पैसा लगाना शुरू किया है, उनका अनुभव बुरा हो सकता है। हमारा मानना है कि मिड-कैप और स्मॉल-कैप अभी बेहद महंगे हैं। समय आ गया है कि छोटी और मझोली कंपनियों से पूरी तरह से निकल जाना चाहिए।

नरेन के बयान ने फंड इंडस्ट्री में काफी हलचल मचा दी है। कुछ लोगों ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से लिया है और स्मॉल-कैप और मिड-कैप में निवेश को कम करने का फैसला किया है। हालांकि, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह एक अवसर है, जिसे निवेशकों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना है कि लंबी अवधि में ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बशर्ते निवेशक धैर्य रखें और बाजार की अस्थिरता को समझें। शेयर बाजार में इन दिनों गिरावट का दौर है। खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ये दिख रहा है। ये समय SIP कर रहे लोगों के धैर्य की भी परीक्षा ले रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जनवरी में इस मोड वाले खातों के बंद होने की संख्या नए खुले खातों से ज्यादा हो गई। इस दौरान 61 लाख एसआईपी खाते बंद हुए जबकि 56 लाख नए खाते जुड़े। एसआईपी खातों में शुद्ध रूप से कमी का यह लगातार छठा महीना है।

लोग अक्सर अनुमान लगाते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन रिस्क का मतलब ही है नुकसान की आशंका। जरूरी नहीं कि लंबी अवधि का निवेश हमेशा मुनाफा ही दे। जापान के स्टॉक मार्केट ने 1989 में निम्न उंचाई को छुआ, उसके बाद गिरावट का दौर दशकों तक चला। क्या हमारे देश में निवेशक इतनी लंबी अवधि तक इंतजार करने के लिए तैयार होंगे। SIP कोई ऐसी भी चीज नहीं कि आखिर में सब कुछ अच्छा होने की गारंटी है।

स्मॉल-कैप और मिड-कैप में SIP के जोखिम को समझना चाहिए और अपने निवेश को संतुलित रखना चाहिए। निवेशकों को जबरन नहीं रोका जा सकता। खुद उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्यों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ये बेहतर माना जाता है कि वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। आम निवेशक सिर्फ स्मॉल-कैप और मिड-कैप में ही निवेश न करें, बल्कि लार्ज-कैप, डेट फंड्स, और अन्य निवेश विकल्पों को भी शामिल करें। अपने निवेश की नियमित समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करें।

ऑफ़ दि ट्रैक

मेमरी पर हमला

दिलीप लाल

अमेरिका के टेक्सस के एक वैज्ञानिक Adrian Ward गाड़ी लेकर निकले थे कहीं के लिए और पहुंच गए कहीं और। हुआ यूं कि रास्ते में उनका फोन खराब हो गया। उन्होंने उसी पर मैप सेट कर रखा था। फोन बंद हुआ तो वह रास्ता ही भटक गए। इस अनुभव ने उन्हें एहसास दिलाया कि लोग तकनीक पर कितना निर्भर हो गए हैं। यह अनुभव Digital amnesia की आम समस्या को दर्शाता है। कई सर्वे में पाया गया है कि लोग चीजों को इसलिए भी भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्मार्टफोन या किसी अन्य डिजिटल उपकरण में उसे सेव करके रखा हुआ है। कुछ अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने हमें उन पर अति निर्भर बना दिया है। GPS का इस्तेमाल करने वाले इसी के भरोसे हो जाते हैं और रास्तों को याद नहीं रख पाते। हालांकि अब भी ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि टेक्नॉलजी हमारी याददाश्त को नुकसान पहुंचा रही है। 2011 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक Betsy Sparrow ने एक अध्ययन में पाया कि जब लोगों को कठिन प्रश्न दिए गए, तो वे तुरंत इंटरनेट के बारे में सोचने लगे। इससे 'गूगल इफेक्ट' शब्द सामने आया, जिसमें लोग जानकारी को याद रखने के बजाय इंटरनेट पर भरोसा करते हैं। AI टूल्स लोगों को मानसिक रूप से आलसी बना सकते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

अमेरिका ने जो ताज़ा संकेत दिए हैं, उनमें यूक्रेन के हितों की अनदेखी हुई

यूक्रेन के साथ ट्रंप का धोखा

मृत्युंजय राय

तीन दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए वार्ता जल्द शुरू होगी। लेकिन पूतिन से किन बिंदुओं पर बात होगी, इस बारे में ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की से कोई चर्चा नहीं की।

जेलेस्की से धोखा | यूक्रेन इस पूरे प्रकरण से इसलिए हैरान था क्योंकि बाइडन सरकार के वक्त युद्ध पर अमेरिका की जो नीति थी, ट्रंप के दौर में वह बिल्कुल बदल गई। बाइडन सरकार की नीति थी, 'यूक्रेन पर अगर कोई बातचीत होगी तो उसमें वह भी शामिल होगा।' लेकिन ट्रंप ने पहले पूतिन से बात की और फिर जेलेस्की से चर्चा।

शांति की कीमत | ट्रंप-पूतिन की बातचीत से ऐन पहले जेलेस्की ने कहा था, 'अगर यूक्रेन युद्ध पर रूस और अमेरिका बात करें तो अमेरिका को सही सूचनाएं नहीं मिलेंगी।' अगर सही बात ही नहीं पहुंचेगी तो सही फैसला कैसे होगा। असल में, शांति की इच्छा पूतिन और जेलेस्की दोनों जाहिर करते रहे हैं। लेकिन शांति किस कीमत पर होनी चाहिए, इसे लेकर दोनों की राय अलग है। पूतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उनका कब्जा हो चुका है, वे वापस न लिए जाएं। जेलेस्की चाहते हैं कि रूस वे इलाके यूक्रेन को वापस करे।

वजूद की लड़ाई | पूतिन की मुश्किल यह है कि अगर वह जीते गए इलाके वापस करते हैं तो एक तरह से युद्ध में उनकी हार मानी जाएगी और इससे उनकी साख कमजोर होगी। जेलेस्की अगर यूक्रेन के इलाके वापस लिए बगैर युद्ध रोकते हैं तो उनके लिए अपना राजनीतिक वजूद बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। वैसे, भी उनका आधिकारिक कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। फिलहाल, युद्ध की वजह से वहां चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।

यूरोपीय देशों का रुख | ट्रंप के सत्ता में आने से पहले इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी खड़े थे। यूरोपीय देश चाहते हैं कि अगर अमेरिका युद्ध रुकवाने के लिए रूस से कोई बातचीत करता है तो उन्हें भी उसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इन देशों का मानना है कि वार्ता में जो भी हल निकले, उसमें यूक्रेन को मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर ट्रंप की चली तो शायद ही ऐसा हो।

यूक्रेन के लिए बुरी खबरें | इसके संकेत भी मिल रहे हैं। ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का कहना है कि 2014 और 2022 में जो इलाके रूस ने हासिल किए हैं, अगर यूक्रेन उन्हें वापस हासिल करने की उम्मीद कर रहा है तो वह आशा 'अवास्तविक (unrealistic)' है। यही नहीं, यूक्रेन के लिए और भी बुरी खबरें हैं। उसे नैटो में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, अगर कोई शांति समझौता रूस और यूक्रेन के बीच होता है तो उस पर अमल के लिए अमेरिका वहां फौज भी नहीं भेजेगा। अगर यूरोपीय देश अपनी तरफ से यूक्रेन में फौज भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा का दायित्व नैटो पर नहीं होगा। ट्रंप सरकार की इन बातों से अगर कोई सबसे खुश होगा तो वह है पूतिन।

लोकतंत्र को झटका | जब बाइडन राष्ट्रपति थे, तब यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से दी जा रही मदद लोकतंत्र को बचाने की जंग थी। उन्हें इस बात का अहसास था कि अगर पूतिन की मनमानी को नहीं रोका गया तो वह विस्तारवादी नीतियों पर आगे बढ़ते रहेंगे। पूतिन के बारे में माना जाता रहा है कि सोवियत संघ के दौर के साम्राज्यवाद को वह फिर से स्थापित करना चाहते हैं। 2014 में उन्होंने यूक्रेन से क्राइमिया को छीना था। 2022 के युद्ध में भी पूतिन यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। यूक्रेन के सहयोगी यूरोपीय देश चाहते हैं कि युद्ध खत्म करवाने की एवज में रूसी राष्ट्रपति से भी रियायतें हासिल करनी चाहिए। युद्ध पूतिन की शर्तों पर खत्म नहीं करना चाहिए। यह न सिर्फ दुनिया में लोकतंत्र के लिए झटका होगा बल्कि इससे दूसरी ताकतों को मनमानी करने का मौका मिलेगा।

विस्तारवादी लीडर्स | इसके संकेत भी पहले से दिख रहे हैं। इस बात की आशंका बढ़ी हुई है कि चीन भी ताइवान को अपने में मिलाने के लिए जंग छेड़ सकता है। हाल ही में शी चिनफिंग ने कहा कि ताइवान मसले को वह आने वाली पीढ़ियों की खातिर नहीं छोड़ना चाहते यानी वह अपने कार्यकाल में उसका विलय चीन में करना चाहते हैं। लेकिन पहले जहां ऐसी विस्तारवादी नीतियों की बातें सिर्फ पूतिन और चिनफिंग कर रहे थे, वहीं राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने भी ऐसे संकेत दिए। पहले तो उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां सूबा बनाने की बात कही। फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की। उसके बाद गाजा को फलस्तीनियों से खाली करवाने की। ट्रंप कटप्टरांग बातें करके भले अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच यह है कि इसकी कीमत समूची दुनिया को चुकानी पड़ेगी।

आईफ़ोन सिटी

चीन के झेंगझोऊ शहर के यूकांग को आईफोन सिटी भी कहा जाता है। यहीं पर Foxconn Technologies का सबसे बड़ा प्लांट है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा असेंबलिंग हब रहा यह उपनगर अब रौनक खो रहा है।

AI Image

नए ठिकाने

पश्चिमी देशों के साथ चीन का तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रेड वॉर को देखते हुए Foxconn और ऐपल ने भारत, वियतनाम व दूसरे देशों में प्रॉडक्शन बढ़ा दिया है। इन देशों में विदेशी कंपनियों को ज्यादा आजादी भी मिल रही है।

कोविड का असर

कोविड के दौरान Foxconn के हजारों कर्मचारियों ने तब इस डर से काम छोड़ दिया था कि फैक्ट्री कैंपस में ही फंसकर रह जाएंगे। उसके बाद से ही 'आईफोन सिटी' लड़खड़ाने लगी।

5 पॉइंट

रोजगार में कटौती

साल 2023 में, चीन में विदेशी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार में 15% की कमी दर्ज की गई। Foxconn की बात करें तो वहां अब अस्थायी श्रमिक रखे जा रहे, जिनकी मजदूरी अगस्त 2023 के मुकाबले 2024 में प्रति घंटा करीब 17% कम हो गई। इस वजह से दोतरफा मार पड़ी है, न रोजगार मिल रहा और न काम करने वाले।

उत्पादन में गिरावट

2023 में 19% आईफोन चीन से दुनियाभर में भेजे जाते थे, 2024 में यह आंकड़ा 15% हो गया। झेंगझोऊ जिस Henan प्रांत में है, वहां स्मार्टफोन निर्यात 2024 में 8.7% घट गया। स्थानीय कस्टम्स के डेटा के मुताबिक, शिपमेंट की मात्रा 14.5% गिर गई है।

इकॉनमी पर असर

झेंगझोऊ के विदेशी कारोबार में अकेले आईफोन सिटी की हिस्सेदारी करीब 80% थी। यह लगातार घट रही है। इसका असर Henan प्रांत की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

प्रस्तुति : शैलेंद्र पांडेय

www.nbt.in

रुमाल में छुपा सोने का हार

कुछ महीने पहले हमारे घर-परिवार के सहायक छोटू का नेपाल के उनके गांव में देहांत हो गया। कायदे-नियम के धनी थे वह, और न थकने वाले भी। उनका नाम असल में मन प्रसाद गुरुंग था, लेकिन हम प्यार से उन्हें छोटू बुलाते थे। 1984 में वह हमारे घर काम करने आए। एक-दो साल बाद ही एक दफा कुछ गिले-शिकवे हुए, तो बैग उठा राम- राम कह कर चल दिए। लेकिन दसेक दिन बाद हमारे घर के बाहर चक्कर लगाने लगे। मैंने पूछा, तो बोले, 'अल्पना सिनेमा के मालिक के यहां काम पर लग गया हूं। लेकिन वहां नौकर-चाकर बहुत हैं, मेरे हिस्से काम ही नहीं आता। वहां खाली बैठे-बैठे थक गया। यहां अकेला था, सुबह-सवेरे से देर रात तक काम ही काम था, सेहत ठीक रहती थी।' मैं उनका मन भांप गया। बोला, 'जाने के लिए बोला ही किसने था तुम्हें। आ जाओ।' और वह रात को ही अपना बैग ले कर आ गए। इस बार जो आए तो फिर जैसे यहीं के होकर रह गए।

कुछ साल बाद का वाकया है। सर्दियों की एक रात मुझे एक विवाह समारोह में जाना था। मैंने अलमारी से अपना सूट निकाल कर छोटू को दिया और कहा, 'शाम को प्रेस कर देना। मुझे रात एक शादी में पहन कर जाना है।' रात को मैं लौटा, तो सूट प्रेस हो कर मेरी अलमारी में टंगा था। कुछ देर सुस्ताने के बाद मैं तैयार होने लगा, तो मुझे कमरे में अकेला देख छोटू आ गया। वह कुछ कहते, उससे पहले ही मैंने कह दिया, 'शुक्रिया भाई, मिल गया सूट, अलमारी में ही था।' मेरी बात सुनकर भी छोटू वहीं खड़े रहे। उनके आने का मकसद तो कुछ और ही था। मैंने जिज्ञासा से उनकी ओर तो देखा तो उन्होंने रुमाल में बंधी एक पोटली मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या? वह बोले, 'आपके कोट की जेब से निकला है, तो मैंने मेम साहब को देने के बजाय आपको ही देना बेहतर समझा।'

खुद अपनी आंख से

अमिताभ स.

वह पोटली भगा कर कमरे से बाहर चला गया। मैंने पहचान लिया कि रुमाल तो मेरा ही था। लेकिन पोटली में क्या है? मैंने गांठ खोली तो हैरानी से भर उठा। उस पोटली में मेरी पत्नी का सोने का हार और कंगन थे। मुझे तो याद ही नहीं था कि पत्नी के गहने कब मैंने रुमाल में बांध कर यूं कोट की जेब में रखे होंगे। पत्नी को आवाज लगाई। गहने दिखाए तो उन्हें याद आया कि दो महीने पहले एक समारोह से लौटते वक्त कार में उन्होंने अपने गहने उतारे थे, और मैंने अपने रुमाल में बांध कर कोट की जेब में संभाल लिए थे। घर आ कर हम दोनों भूल गए, और मैंने सूट हमेशा की तरह हैंगर में लगाकर अलमारी में रख दिया। अगर छोटू की नीयत खराब होती, तो वह गहने गायब भी कर सकते थे। उन पर तो हमारा शक ही कहां जाना था। हम दोनों तो उस घटना को पूरी तरह से भूल चुके थे।

हमने मन ही मन छोटू की ईमानदारी को दाद दी। काम में भी वह उतने ही सधे हुए थे। हमारे घर में काम करते-देखते वह एक तरह से ऑल राउंडर बन चुके थे। सफाई-धुलाई से ले कर कुकिंग और कार ड्राइविंग तक शायद ही कोई काम ऐसा हो, जो छोटू को नहीं आता हो। और किसी काम में वह हमें शिकायत का मौका भी नहीं देते थे। 2020 के लॉकडाउन में वह अपने घर ऐसे गए कि लौट कर आए ही नहीं। शायद लंबा आराम उन्हें रास नहीं आया। और फिर मिली उन्हें हमेशा के लिए चले जाने की दुखद खबर। कहां मिलते हैं इतने लंबे टिकने वाले साथी? जिनकी इतनी मीठी बातें हों, जिनके ईमान की इतनी मिसालें हों।

चलते-चलते...

गर्भावस्था के दौरान वेजिनिटिस आम समस्या है। पहले इसके लिए मनोवैज्ञानिक कारण, हॉर्मोन, संक्रमण, उच्च थायरॉइड को जिम्मेदार माना जाता था। पर Los Angeles के Keck School of Medicine के शोधकर्ताओं ने अपनी नई शोध में पाया कि शरीर में पहले से GDF15 प्रोटीन का स्तर ज्यादा रहने से यह दिक्कत होती है।

अयोध्या से है सम्राट अशोक का संबंध

पिछले दिनों आगरा में बिल्डरों ने एक ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचाया तो तमिलनाडु का लौह युग भी चर्चा में रहा। डॉ. बी. आर. मणि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के महानिदेशक हैं और भारतीय विरासत संस्थान के कुलपति भी। डॉ. मणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे हैं, जिनके निर्देशन में अयोध्या, कपिलवस्तु, राजघाट और सारनाथ सहित 19 जगहों पर उत्खनन कार्य हुआ है। इतिहास, विरासत और उत्खनन पर उनसे ***अर्चना शर्मा*** *ने विस्तार से बात की। पेश है बातचीत के अहम अंश :*

■ भारत में बिल्डरों ने ऐतिहासिक महत्व की चीजों को कितना और कैसे-कैसे नुकसान पहुंचाया है?

ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के अतिक्रमण या नुकसान की बात करें तो उसमें ना सिर्फ बिल्डर आते हैं, बल्कि अन्य अतिक्रमण करने वालों का भी समावेश है। ऐसे बहुत से असंरक्षित स्थल हैं जिनको बिल्डरों, अतिक्रमण करने वालों या वैसे लोगों ने, जिन्हें उनके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी नहीं है, काफी नुकसान पहुंचाया है। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरे देश की स्थिति ऐसी ही है। ऐसे लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए ऐसा काम करते हैं जिससे उस स्थल में अस्थिरता पैदा हो जाए और उनका उल्लू सीधा हो सके। वे यह नहीं समझ पाते कि इससे हमारी विरासत को कितना नुकसान होता है।

■ तमिलनाडु के नए लौह युग पर आप क्या कहना चाहेंगे?

अभी हाल में एक स्थान पर खुदाई से कुछ अति प्राचीन रेडियोमेट्रिक तिथियों का पता चल रहा है जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही है। किंतु बिना पूरी जांच पड़ताल के अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तक 1200 ईसा पूर्व के लगभग लौह युग माना जाता रहा है।

■ आप अयोध्या की खुदाई में भी रहे। ऐसी कोई खास बात जो आपने वहां देखी और जो लोगों को भी जाननी चाहिए?

अयोध्या की उत्खनन रिपोर्ट जिस पर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए, कितने ही साल बीत चुके हैं, उसको अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रकाशित नहीं किया है। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो आम लोगों के भीतर जो भावना बैठी हुई है कि जाने वहां खुदाई में क्या निकला, उसका समाधान हो जाएगा। वहां मंदिर था या कोई अन्य ऐतिहासिक इमारत थी, या फिर उस क्षेत्र में 12 मीटर के दायरे में अलग-अलग काल खंडों की जो सतहें मिलती हैं वे क्या संकेत देती हैं, इस इसे स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे। इस विषय पर भारतीय पुरातत्व परिषद की पत्रिका, पुरा प्रवाह में मेरा एक आलेख प्रकाशित हुआ है जो इस विषय पर पूर्ण जानकारी देता है।

डॉ. बी. आर. मणि

उत्खनन में जो संरचनाएं और पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें इस्लामिक ढांचे के नीचे एक विशाल निर्माण जो नागर शैली में है, मिला है। दीवारों और स्तंभ के आधार भी दिखे हैं।

■ कई ग्रंथों में हम पाते हैं कि साकेत एक बौद्ध विहार भी था। इसके बारे में आपको कभी कोई खास जानकारी मिली?

अयोध्या की कार्बन डेटिंग का समय 1700-1540 ईसा पूर्व का है। बुद्ध साकेत के आसपास के क्षेत्र में आते-जाते रहे हैं, खासकर कोसल उनको बहुत प्रिय था, इसलिए इस तरह की बात कही जाती है। साकेत में बौद्ध विहार भी रहे होंगे। साकेत में एक नागेश्वरनाथ का मंदिर भी है जहां अशोक स्तंभ की चौकी अभी भी मौजूद है। उस चौकी को उलटा करके उसमें शिवलिंग स्थापित है, पर वह निश्चित तौर पर अशोक स्तंभ का ही हिस्सा है। इस तरह इस इलाके से अशोक का भी संबंध रहा है। बौद्ध, जैन तीर्थंकर का भी इस क्षेत्र में आना-जाना लगा रहता था। लेकिन राम जन्मभूमि की जगह पर बौद्ध धर्म से संबंधित कोई बात नहीं मिलती।

■ पुरातत्वशास्त्र में बुद्ध का विस्तार आप कहां तक पाते हैं?

छठी से पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व जब बुद्ध का जन्म हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय तक बुद्ध जिन स्थानों पर गए, उन स्थानों के उत्खनन से बुद्ध काल की कई वस्तुएं मिली हैं। बहुत से स्थानों पर अभी भी काम होना बाकी है। कई ऐसे पुरातत्व स्थल हैं जैसे सांची, अमरावती या फिर नागार्जुनी कुंड जो बौद्ध स्थल तो हैं लेकिन शायद वहां बुद्ध का पदार्पण नहीं हुआ था। धीरे-धीरे जब बौद्ध विहारों का उदय हुआ, वहां

> अयोध्या की कार्बन डेटिंग का समय 1700-1540 ईसा पूर्व का है। बुद्ध साकेत के आसपास के क्षेत्र में आते-जाते रहे हैं। साकेत में बौद्ध विहार भी रहे होंगे। साकेत में एक नागेश्वरनाथ का मंदिर भी है, जहां अशोक स्तंभ की चौकी अभी भी मौजूद है। उसमें शिवलिंग स्थापित है, मगर वह है अशोक स्तंभ का ही हिस्सा

उनकी आराधना हेतु उनके मूर्ति स्वरूपों का, स्तूपों का निर्माण हुआ, जिससे लोगों को इस विषय में पता चलता है। इस तरह के बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्व इलाके में कई बौद्ध स्थल मौजूद हैं, जैसे वियतनाम, लाओस, थाईलैंड।

■ प्राचीन मूर्तियों में हम हर किसी को कमल पर खड़ा, बैठा या लेटा पाते हैं। कमल को किन-किन संस्कृतियों और धर्मों का प्रमाण माना जाना चाहिए?

कमल का महत्व सभी इंडिक धर्मों, चाहे सनातन हो या बौद्ध या जैन धर्म, में बहुत रहा है। कमल का प्रस्फुटन उस अलौकिक प्रेरणा का प्रतीक है जहां किसी व्यक्ति या प्रकृति का जन्म संभव होता है। कई स्थानों में आपको मूर्तियों में कमल के ऊपर या तो शयन मुद्रा में या स्थानक मुद्रा में या फिर खड़े हुए स्वरूप दिखते हैं। कमल के अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण भी कई देवी-देवताओं जैसे ब्रह्मा, सरस्वती से इसका संबंध है। अन्य संस्कृतियों में कमल का श्रृंगारिक महत्व है, पर आध्यात्मिक आयाम भारतीय संदर्भ में ही है।

■ पुरातत्व की दृष्टि से अब तक मिली सबसे पुरानी लिखित भाषा कौन सी है?

यह कहना बड़ा मुश्किल है। भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता में मिले टैबलेट सबसे प्राचीन लिखित भाषा के आवशेष के तौर पर मिले हैं, पर इन्हें पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। हाल के शोध बताते हैं कि ये संस्कृत भाषा का ही एक रूप है, जिसे पढ़ने का प्रयास चित्रात्मक लिपि से किया जा सकता है क्योंकि संभवतः इस भाषा को वर्णमाला के हिसाब से नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरी तरफ जब हम चौथी-पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिले पत्थर के अभिलेखों को देखते हैं, तो पाते हैं कि वे वर्णमाला के अनुसार लिखे गए हैं।

■ AI से पुरातत्व में क्या उम्मीद है?

AI का प्रयोग तब होता है जब हमें समुचित प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। तब हम अपनी बुद्धि से आकलन करते हैं। यह व्यवस्था किसी भी पुरातात्विक या इतिहासकार की अपनी सोच से होती है, जिसे आज हम AI कहते हैं।

रीडर्स मेल

▸ NTA की जिम्मेदारी

14 जनवरी को लिखे 'NTA की गलतियों की सजा छात्रों को क्यों' पढ़ा। JEE Main 2025 में हुई गड़बड़ियों ने एक बार फिर NTA की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गलत प्रश्न, सिलेबस से बाहर के सवाल और अनुवाद की त्रुटियों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यह NTA की लापरवाही को उजागर करता है। गलत प्रश्नों को ड्रॉप कर नंबर देना एक समाधान हो सकता है, लेकिन इससे उन मेहनती छात्रों के साथ अन्याय होता है जिन्होंने बहुमूल्य समय गंवाया। डमी स्कूलों पर सवाल उठाने के साथ-साथ जरूरी है कि JEE का सिलेबस NCERT के अनुरूप बनाया जाए। पिछले सालों के विवादों के बाद भी NTA ने अपनी प्रक्रिया में सुधार नहीं किया। अब वक्त है कि एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम में आमूलचूल बदलाव हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाली एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी से बचने की छूट नहीं होनी चाहिए।

तृप्ति सिन्हा, नोएडा

▸ संबंधों में संतुलन

अमेरिका की आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से उठाए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कदम वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। WHO को आर्थिक सहायता रोकना, पेरिस जलवायु समझौते से हटना और मेक्सिको की सीमा पर आपातकाल लगाना उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को दर्शाता है। लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही, चीन, मेक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने से वैश्विक व्यापार में टकराव बढ़ सकता है। इससे अमेरिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। हालांकि, व्यापारिक नीतियों के बदलते परिदृश्य में भारत को सतर्क रहना होगा। उसे अपनी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाते हुए व्यापारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए।

वी. एल. शर्मा, ईमेल से

प्रकाशक एवं मुद्रक : एस.एन.एस. नारायणन मुद्रित। ऐडिटर : ऐडिटर-इन-चीफ़ के लिए संपादक एवं अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी : नवभारत टाइम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग अपनी विभिन्न के लिए राजीव चंद्रा द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **राहुल जोश द्विवेदी के लिए, पाइज़ 1 ए, ऑलोफिट ग्रेटर नोएडाबाद** सी-मार्ग 1

हिन्दुस्तान
1936

समन्वय का संतोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वह सुखद और संतोषजनक है। व्हाइट हाउस में हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले एक तनाव देखा जा रहा था और आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, पर कुल मिलाकर, दोनों नेताओं के बीच बातचीत संतुलित और सकारात्मक रही है। दोनों देशों ने अपनी-अपनी चिंताओं के बीच से एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और इससे भारत के बढ़ते महत्व का ही पता चलता है। दोनों देशों के बीच टैरिफ का तनाव कायम है, लेकिन इतना संकेत जरूर मिल गया है कि दोनों के बीच व्यापार का बढ़ना तय है। यह भी संकेत मिल गया है कि दोनों देश एक-दूसरे को रियायत देने के लिए कदम उठाएंगे। साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की जरूरत पर बल दिया है। गौर करने की बात एक यह भी है कि 10 साल की रक्षा सहयोग योजना के तहत अमेरिका भारत को एफ-35 लड़ाकू जेट की बिक्री कर सकता है।

अव्वल तो दोनों शीर्ष नेताओं के बीच जो सहजता दिखी है, उसे रेखांकित करना चाहिए। दोनों शासनाध्यक्षों ने एक-दूसरे के प्रति अनौपचारिक रूप से भी लगाव का प्रदर्शन किया है। ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को बहुत बेहतर वार्ताकार बताया, तो ट्रंप की नीतियों और नारों के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री का लगाव भी उल्लेखनीय रहा। 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' का जयघोष किया है। यह घोषणा दरअसल ट्रंप की नीतियों की प्रशंसा ही है। अगर अमेरिका की महानता सही दिशा में निर्मित हो, तो इससे विकसित भारत का भी निर्माण जुड़ा हुआ है। आज दुनिया में जिस तरह की राजनीति या कूटनीति चल रही है, उसमें भारत का अमेरिका के साथ खड़े होना और उससे यथासंभव आर्थिक सहयोग लेना अचरज की बात नहीं। भारत अनेक अमेरिकी उत्पादों के आयात पर तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक शुल्क लगाता है और ऐसा करना बहुत हद तक जरूरी है। हां, अंतर केवल इतना आएगा कि भारत को कुछ उत्पादों पर शुल्क घटाना पड़ेगा। जहां भारत के स्थानीय उत्पादकों या किसानों पर ज्यादा आर्थिक चोट की आशंका होगी, वहां भारत को समन्वय से रास्ता निकालना होगा। अमेरिका विरोधी रुख पालने के बजाय मिलकर चलने का इरादा बरकरार रहना चाहिए। लड़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर यहां भारत को ज्यादा सावधान रहना होगा।

अमेरिका विरोधी रुख पालने के बजाय मिलकर चलने का इरादा बरकरार रहना चाहिए। लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, पर यहां भारत को ज्यादा सावधान रहना होगा।

भारत को बस इतना सुनिश्चित रखना चाहिए कि वह सदैव विकास के साथ खड़ा रहे, किसी के विनाश की योजना के साथ नहीं। युद्धरोकने के लिए ट्रंप प्रयासरत हैं, इस पर भारत कुछ ज्यादा बात कर सकता था। युद्ध, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ भारत की मजबूती बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यावहारिक आश्वासन दिया है कि भारत अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है। साथ ही, प्रधानमंत्री ने मानव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों का भी आह्वान किया। बांग्लादेश और आतंकी तहव्वुर राणा पर भी चर्चा स्वागतयोग्य है। दक्षिण एशिया में ट्रंप भारत के महत्व को समझते हैं और भारत को अपना महत्व बढ़ाने के और प्रयास करने चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 15 फरवरी, 1950

पशु धन की उन्नति

मानव समाज की सुख-सुविधाओं और समृद्धि में विभिन्न पशुओं का योग कम महत्व नहीं रखता। इसीलिए आज दुनिया के सभी प्रगतिशील देश अपने पशु-धन को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। जो देश मुख्यतः कृषि-प्रधान हैं, उनका काम तो पशुओं के बिना चल ही नहीं सकता। अवश्य ही खेती के लिए यंत्रों का प्रयोग होने लगा है और बोझ ढोने का काम भी यंत्र-गाड़ियों से लिया जाता है, किन्तु ये यंत्र अभी तक पशुओं का स्थान लेने में न तो सफल हुए हैं और न हो सकते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रखने में पशुओं से जितनी सहायता मिल सकती है, उतनी यंत्रों से नहीं मिलती। पशु हमको स्वाभाविक खाद प्रदान करते हैं और उनकी मदद से जो हल चलाया जाता है, वह धरती के पेट को आवश्यकता से अधिक नहीं चीरता। फिर मनुष्यों को पशुओं के जरिए दूध, घी आदि के रूप में जो पौष्टिक आहार प्राप्त होता है, वह अन्य यूत्र से सुलभ नहीं हो सकता। भारत के लिए, जो कि मुख्यतः कृषि-प्रधान देश है, बहुत समय तक पशुओं की उपयोगिता अनिवार्य रहेगी। भारत में यांत्रिक खेती आसानी से नहीं अपनायी जा सकती। खेती की उपज और अन्य बोझ ढोने के लिए पशुओं की सहायता लेना आवश्यक होगा, क्योंकि न तो हमारे देहात सड़कों और रेलों द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध हुए हैं और न यांत्रिक वाहनों का ही हमारे पास बाहुल्य है। हम चाहे जिस दृष्टि से विचार करें; चाहे कृषि और भारवहन की दृष्टि से और चाहे अपने देश की अधिकांश शाकाहारी जनता के लिए पौष्टिक आहार सुलभ करने की दृष्टि से, पशु-धन की उन्नति किये बिना हमारा निस्तार नहीं है। हमारे देश की विशेष परिस्थितियों में पशुओं में गोवंश का विशेष महत्व है और इसी कारण राष्ट्रपिता गांधीजी ने गो-सेवा को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य अंग बनाया था।

जहां तक भारत में उपयोगी पशुओं की संख्या का ताल्लुक है, यह काफी अधिक है। इस विषय में सम्भवतः भारत दुनिया के अधिकतर देशों से आगे है। किन्तु जहां तक पशुओं की अच्छी और सुधरी हुई किस्मों का सम्बन्ध है, भारत पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी देशों ने पशुपालन की कला का खूब विकास किया है और उनके अनुभवों की मदद से भारत को भी लाभ उठाना चाहिए।

आज भारत और अमेरिका के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर हैं, पर एक समय था, जब दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध के बावजूद अविश्वास था। साल 1987 में 6 मई को लोकसभा में दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर जताई गई चिंताएं और उम्मीदें आज बहुत प्रासंगिक हो गई हैं।

हम अमेरिकी नीतियों से क्या उम्मीद रखें

यहां स्कैन करें

गीता मुखर्जी | तत्कालीन सांसद

- तेंदुआ कभी अपना रंग नहीं बदलता और इसे समझा जाना चाहिए था।
- पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा सहायता दे रहा अमेरिका।
- अमेरिकी व्यवहार से हमें कुछ सबक सीखने की जरूरत है।

मैं हमारे युवा प्रधानमंत्री के 23 माह पहले काफी सुख भ्रांति के साथ किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे का स्मरण कराऊंगी। वास्तव में दो महान प्रजातंत्रों के अनुभवों का साझा करने के बारे में वहां काफी बातें की गई थीं और काफी धन खर्च करके भारत उत्सव का आयोजन कर अमेरिका पर प्रभाव डालने के लिए काफी प्रयास किए गए थे। वहां ऐसा वातावरण था कि हमारी सरकार वास्तव में यह आशा कर रही है कि भारत के प्रति अमेरिकी रवैये में बहुत बदलाव होगा, पर महोदय, मुझे यह कहना चाहिए कि तेंदुआ कभी अपना रंग नहीं बदलता और यह एक कहावत है, जिसे समझा जाना चाहिए था। मेरी राय में उस मामले में भारत सरकार की कमजोरी है और संभवतः विपक्ष के काफी सदस्यों को भी इसकी जानकारी है। दौरे के बाद क्या मिला, यह हर व्यक्ति जानता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे अन्य साथियों ने भी इसका जिक्र किया है।

मैं इन सभी सुख भ्रांतियों की निम्नलिखित घटनाओं का शीघ्रता से जिक्र करूंगी। पाकिस्तान को एफ-16, भारी टैंक, भारी हेलिक्प्टर, हरपून मिसाइल्स, प्लेसर गाइडेड कॉपर हैड आर्टीलरी, अवाक्स, ई-2-सी वायुयान, इलेक्ट्रॉनिकी आसूचना देख-रेख (इंटिलिजेंस मॉनिटरिंग) का पुनर्ग्रहण और ...40,010 लाख डॉलर की मिलटरी सहायता और वास्तव में पाकिस्तान को परमाणु के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना और तत्पश्चात भारत पर एनपीटी हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालना। संक्षेप में मैंने इन परिणामों का विवरण दिया है, जो हमें दो महान प्रजातंत्रों के अनुभवों का लाभ उठाने से प्राप्त हुए हैं।

...पाकिस्तान को दिए गए इन सभी बड़े हथियारों तथा भारी सैनिक सहायता, यद्यपि ये अफगानिस्तान में रूस की कथित गतिविधियों को समाप्त करने के नाम पर दिए गए हैं, पर इनका उपयोग समय आने पर भारत के विरुद्ध किया जा सकता है और किया जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अतः हमें इस बारे में हमेशा के लिए स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद से क्या आशा करते हैं। तदनुसार ही कार्य करना चाहिए।

...हमारे प्रथम प्रधानमंत्री अक्तूबर 1949 में अमेरिका गए थे। वहां हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव तथा सीनेट को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा था कि आपको ध्यान देना चाहिए कि उस यात्रा को भी खोज यात्रा की संज्ञा दी गई थी। इसमें पंडित नेहरू ने कहा था, 'मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का महान प्रजातंत्र समान समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को समझेगा।' ...वहां से आने के बाद और वहां जो कुछ हो रहा था, उसका पता लगने के बाद उन्होंने उसी वर्ष 1949 में कहा था, 'उन्होंने हर प्रकार से मेरा स्वागत किया, परंतु वे मुझसे कृतज्ञता और सद्भावना से कुछ ज्यादा की आशा करते थे और मैं उन्हें और ज्यादा क्या दे सकता था?' ...हमारे प्रधानमंत्री क्या नहीं दे सकते थे, यह बाद की घटनाओं से बिल्कुल स्पष्ट है। ...

सन् 1951 में (राष्ट्रपति) ट्रूमैन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, 'पाकिस्तान पूर्व में अपने पड़ोसी देशों में स्थिरता प्रदान करने में शक्तिशाली और प्रगतिशील तथा एक महत्वपूर्ण कारक है।' ...इसी विश्वव्यापी नीति के साथ वे कश्मीर के प्रश्न पर बर्ताव कर रहे हैं। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये सभी आम जानकारी की बातें हैं, किंतु इससे कुछ सबक सीखने की भी जरूरत है। प्रश्न यह है कि क्या वह सब संयोग मात्र था। जी नहीं, यह अमेरिकी साम्राज्यवाद की विश्वव्यापी नीति का एक अंश है। ...जहां तक भारत का सवाल है, मुस्कराते चेहरे या अन्य लोकतांत्रिक देश के साथ हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार हमारे लिए सहायक नहीं होगा। हमें सख्त रवैया अपनाना होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

संतुलित नजरिये के साथ चल रहा भारत

यहां स्कैन करें

के नटवर सिंह | तत्कालीन केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री

- व्यवहार कुशलता तरीका है, जिससे संघर्ष को कम किया जा सकता है।
- अमेरिका की क्षेत्रीय मजबूरी और चिंताओं को हमें समझना चाहिए।
- हम सभी देशों के प्रति दोस्ताना और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखेंगे।

महोदय, यह चर्चा काफी व्यापक रही है। अब हमारे लिए स्वतंत्रता पूर्व के दिनों, 1947 की तरफ लौटकर समय-समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों का जायजा लेना संभव है। हम अपने को हाल के अतीत, वर्तमान तथा सन्निकट भविष्य तक ही सीमित करते हैं। माननीय सदस्यों ने, जो बोले हैं, दोनों मार्गों को अपनाया है। कुछ तो बिल्कुल पीछे चले गए। श्रीमती गीता मुखर्जी ने पंडित नेहरू को उद्धृत किया है। मेरे पास यहां पंडित जी का भाषण है और मैं भी इससे भिन्न संदर्भ में उद्धृत करने का इरादा रखता हूं।

अमेरिका के साथ हमारे संबंधों के बारे में, यदि हमें समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है, तब ...वह व्यवहार कुशलता का एक तरीका है, जिससे संघर्ष के क्षेत्रों को कम किया जा सकता है और तनाव को कम करने हेतु समझौते के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है। वही कुछ हमने पंडित नेहरू के दिनों से सीखा है। इसी उद्देश्य से वह 1949 में अमेरिका की खोज की अपनी महान यात्रा पर गए थे, तुरंत लाभ की दृष्टि से इसे देखते हुए हमें भारत के प्रति अमेरिकी नीति का विश्लेषण करना होगा। मैं यह बात कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता हूं, किंतु किसी भी माननीय सदस्य ने एशिया सोसायटी में पॉलिटिकल अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, माइकल एच आर्मकोस्ट द्वारा 29 अप्रैल को दिए गए भाषण का उल्लेख नहीं किया है। इसका विषय था कि अमेरिका और दक्षिण एशिया संबंध। ...यह बहुत ही प्रासंगिक है और मेरे विचार में उनके भाषण का हवाला दिए बिना अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की चर्चा करना कुछ अवास्तविक ही होगा। ... आर्मकोस्ट ने कहा है कि 'भारत की चिंता बनी हुई है कि पाकिस्तान का इरादा अमेरिकी हथियारों द्वारा भारत के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का है। हमारा पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग का उद्देश्य अफगानिस्तान में सोवियत दबाव के संदर्भ में उसकी रक्षा व तकनीक के क्षेत्र में हुई चर्चा के भी काफी गहरे निहितार्थ हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूरगामी बदलाव लाने के लिए एक नई पहल '21वीं सदी के लिए अमेरिका-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, वाणिज्यिक और तकनीकी सहयोग के लिए नए अवसरों को आगे बढ़ाना)' की शुरुआत जहां काफी महत्वपूर्ण है, वहीं भारत का यह नजरिया भी अहम है कि भारत-अमेरिका रक्षा संबंध को क्रेता-विक्रेता के रूप में आगे बढ़ाने के बजाय साझा-निर्माण की दिशा में बढ़ाना चाहिए। 'जेवलिन' और 'स्ट्राइकर' की खरीद पर सहमति तो बनी ही, सह-उत्पादन पर भी दोनों देश राजी हुए। यह उस तथ्य की पुष्टि है, जिसमें कहा जाता था कि भारत और अमेरिका अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा के मोर्चे पर आपसी संबंध पारस्परिक रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाने कहा है।'

अमेरिका हमारा व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। पांच लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं और वे वहां बहुत ही अच्छी प्रकार से रह रहे हैं। अमेरिका के लिए यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारे लोग वहां जाना चाहते हैं।...

जी हां, अमेरिका के साथ हमारे संबंध निस्संदेह परिपक्व, स्वस्थ और विकासोन्मुख हैं। यहां पर हमारी चिंता का विषय सुरक्षा वातावरण है। ...अमेरिका के साथ और अधिक जनसंपर्क किया जाना चाहिए। अगले ही सप्ताह भारत-अमेरिका व्यापार परिषद की बैठक हो रही है। विभिन्न उप-आयोगों की बैठकें हो रही हैं। अमेरिका से अनेक प्रतिनिधिमंडल भारत आते हैं और मेरे पास उन लोगों की सूची है, जो वहां से आए हैं। मैं वहां से अमेरिका जाता हूं। यहां से भी कई लोग शिक्षा के लिए, कई लोग सांस्कृतिक कारणों से, कई लोग व्याख्यान देने के लिए अमेरिका जाते हैं। समाचारपत्रों और साहित्यिक रचनाओं का आदान-प्रदान होता है।...

श्रीमती गीता मुखर्जी की टिप्पणियां और जो उद्धरण उन्होंने पंडित जी के भाषण से दिए हैं, का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, परंतु अब उन्होंने यह कहा कि अमेरिका की विदेश नीति भारत को कुदृष्टि के साथ जकड़े रखने की है। मैंने उन कारणों को स्पष्ट किया था, जिस कारण वह विश्व के इस हिस्से पर नजर रखते हैं। ...उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच सामान्य बोध बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें हम द्विपक्षीय आधार पर कार्य करते हैं और वे हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं।

अमेरिकियों के साथ लगभग 2,000 सहयोग समझौते किए गए हैं। ...पंडित नेहरू के दिनों से हमारी विदेश नीति जातिवाद तथा अलगाववाद को छोड़कर सभी के प्रति दोस्ताना तथा सद्भावनापूर्ण रही है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

मजबूत रिश्तों की नई मंजिल की ओर बढ़े मोदी-ट्रंप

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन के अगले चार वर्षों में नई दिल्ली और वाशिंगटन के रिश्तों में काफी स्थिरता देखने को मिल सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 'ट्रंप-2.0' के दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्तों का रोडमैप तैयार करता दिखा। इस यात्रा में उन तमाम मुद्दों पर सार्थक बातें हुईं, जिनसे द्विपक्षीय रिश्तों को गति मिलेगी। चाहे सबसे अहम आर्थिक मसला हो या रक्षा व तकनीक से जुड़े मुद्दे या फिर ऊर्जा सुरक्षा। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने व बहुपक्षीय सहयोग पर भी जोर दिया। साझा बयान में आतंकवाद की निंदा करते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा गया कि मुंबई व पठानकोट हमलों के गुनहगारों को न्याय के कठघरे में खड़ा करने के साथ-साथ इस्लामाबाद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं हो। स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी का यह सफल दौरा रहा है। इसका संकेत मोदी-ट्रंप प्रेस वार्ता से भी मिला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में ट्रंप की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर भारत आने का न्योता दिया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुले दिल से स्वीकार किया।

ट्रंप ने इस बात पर खुशी जताई है कि भारत ने आम बजट में उन कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसको लेकर अमेरिका की चिंता रही है। पिछले दिनों टैरिफ बढ़ाने की कवायद इसलिए भी की गई थी, क्योंकि व्यापार घाटा भारत की तरफ झुका हुआ है। माना जा रहा है कि मोदी-ट्रंप मुलाकात के बाद दोनों देश एक नई आर्थिक संरचना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें दोनों के हितों की पूर्ति हो सकेगी। हालांकि, ऐसा करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी हितों को लेकर गंभीर है, तो भारतीय हितों की रक्षा को लेकर वह भी प्रतिबद्ध हैं। इसका मतलब है कि मोल-भाव की जो प्रक्रिया आगे शुरू होने वाली है, वह दिलचस्प रहेगी। अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना। यह बताता है कि दोनों पक्ष आर्थिक रिश्ते को मजबूती देने को लेकर संकल्पित हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा यह सोचने के बावजूद कि भारत में सीमा शुल्क ज्यादा है, वाशिंगटन आशान्वित है कि भारत के साथ रिश्ते और प्रगाढ़ बनने चाहिए।

रक्षा व तकनीक के क्षेत्र में हुई चर्चा के भी काफी गहरे निहितार्थ हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूरगामी बदलाव लाने के लिए एक नई पहल '21वीं सदी के लिए अमेरिका-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, वाणिज्यिक और तकनीकी सहयोग के लिए नए अवसरों को आगे बढ़ाना)' की शुरुआत जहां काफी महत्वपूर्ण है, वहीं भारत का यह नजरिया भी अहम है कि भारत-अमेरिका रक्षा संबंध को क्रेता-विक्रेता के रूप में आगे बढ़ाने के बजाय साझा-निर्माण की दिशा में बढ़ाना चाहिए। 'जेवलिन' और 'स्ट्राइकर' की खरीद पर सहमति तो बनी ही, सह-उत्पादन पर भी दोनों देश राजी हुए। यह उस तथ्य की पुष्टि है, जिसमें कहा जाता था कि भारत और अमेरिका अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा के मोर्चे पर आपसी संबंध को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। अमेरिका इस बात से भी खुश दिखा कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों में उसकी अहमियत समझी है। शेल गैस, एलएनजी में अमेरिका हमारा अहम सहयोगी बन सकता है।

सामरिक मुद्दों की बात करें, तो दोनों ही पक्ष पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत में नए फ्रेमवर्क की तलाश करते दिखे। इस बात पर भी सहमति बनी कि वैश्विक सहयोग के रूप में इस ढांचे को आगे बढ़ाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका हिंद-प्रशांत में भारत की भूमिका बखूबी समझता है। क्वाड को पुनर्जीवित इसलिए भी किया गया है, ताकि हिंद-प्रशांत में चीन की दखलंदाजी से पार पाया जा सके। पश्चिम एशिया में भी कुछ मामलों में भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए अमेरिका वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है।

साफ है, इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों शासनाध्यक्षों ने नए मानक तय किए हैं, जिन पर भारतीय और अमेरिकी नौकरशाहों को अब आगे बढ़ना होगा। वे किस तरह से एक-दूसरे को समझौतों के लिए तैयार कर पाते हैं, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन के अगले चार वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में काफी स्थिरता देखने को मिल सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अहंका पिघल जाना

संपर्क तीन प्रकार से होता है- दिमाग से दिमाग का संपर्क बातचीत द्वारा होता है; दिल से दिल का संपर्क गाकर होता है और आत्मा से आत्मा का संपर्क मौन में होता है। अक्सर जब तुम लोगों के साथ होते हो, बातें करते रहते हो, तब संपर्क केवल दिमाग के स्तर पर रखते हो। जब तुम प्रकृति के साथ होते हो, तो तुम गाने लगते हो। प्रकृति के साथ संपर्क तुम दिल से करते हो। और जब तुम गुरु के साथ होते हो, तुम खाली हो जाते हो, सभी प्रश्न भूल जाते हो, तब संपर्क आत्मा द्वारा होता है मौन में।

जब तक कि कोई आयोजित कार्यक्रम न हो, तुम शायद ही लोगों के साथ गाते हो। तुम्हारा अहं तुम्हें गाने से रोकता है। जब तुम लोगों के साथ गाते हो, तब तुम दिल, भावना के स्तर पर उतर आते हो। कुछ व्यक्ति केवल संगीत सुनने में सहजता अनुभव करते हैं, कुछ केवल एकांत में गाना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति दूसरों का ध्यान आकर्षित करने या दूसरों को लुभाने के लिए गाते हैं। कुछ व्यक्ति केवल तभी गाना चाहते हैं, जब और लोग भी गा रहे हों। ये सभी गायन अहं से हैं।

'भजन' का अर्थ है बांटना। सत्ता के अंतरतम स्तर पर सहभागी होना। भजन ही वास्तविक भागीदारी है। यदि तुम लोगों के साथ गा सको, तो तुम्हारा अहं खत्म हो जाता है। बच्चे सबके साथ गा सकते हैं, क्योंकि उनमें अहं नहीं होता। अनजान व्यक्ति के साथ गाने के लिए तुम्हें अहं से मुक्त होना है। दिमाग के स्तर पर अहं सुरक्षित है। दिल के स्तर पर अहं टूटता है। आत्मा के स्तर पर वह पिघल जाता है। संपर्क करने की अयोग्यता केवल अहं के कारण होती है।

श्री श्री रविशंकर

आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण | सनातन धर्मगुरु

धर्म को कौतुकपरायणता के बाहर होना चाहिए, तभी यह ज्यादा दिनों तक ज्यादा लोगों के लिए हितकारी बना रह पाएगा। नहीं तो यह उन्माद का कारक बन जाएगा, हमारे सामने अवांछित स्थितियां आने लगेंगी।

पुस्तक मेला धरती का सबसे सुंदर दृश्य

आखिरी तीन दिन लगातार पुस्तक मेले में गया। खूब बढ़िया भीड़ रही। निहारता रहा पाठकों को अपनी पसंद की किताबें खरीदते हुए। यह धरती का सबसे सुंदर दृश्य था। बारह-पंद्रह साल से कोई पुस्तक मेला नहीं छूटा। लेखक-पाठक-प्रकाशक, हर भूमिका में रहा हूं और इससे प्यार किया है। खलता बस इतना है कि बहुत से सचमुच के बड़े लेखक सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो लोग भूल गए हैं। याद रखना चाहिए, उन्होंने हमारी भाषा को बनाया है, संवारा है। वे हमारे पुरखे हैं। पहले मिलने वाले कहते थे- आपको पढ़ा है। अब 'आपको देखा है' कहने वाले भी खूब मिलते हैं। चमकते परदे की माया अपरंपार है। दुनिया अपनी बड़ी होती है, तो सुंदर लगता है। बिकती रहें किताबें। चमकते रहें मेले। जुड़ते रहें लेखक और बढ़ता रहे शब्दों का कबीला।

अशोक कुमार पांडेय, टिप्पणीकार

पढ़ने की बढ़ी रुचि

इस वर्ष का विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित हुआ। मुझे हिंदी, अंग्रेजी और बच्चों के पवेलियन में ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। बच्चों के लिए आयोजित कहानी सत्र, वर्कशॉप और इंटरैक्टिव गतिविधियां देखकर आश्वस्त हुआ कि युवा पीढ़ी में पढ़ने की रुचि धीरे-धीरे बढ़ ही रही है। मेले में ई-बुक्स और ऑडियो-बुक्स के स्टॉल भी थे, परंतु देखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग गंभीर चर्चाएं छपी हुई किताबों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। हाल ही में खबर भी आई थी कि किसी देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए डिजिटल बुक के बजाय पारंपरिक किताबों से ही पढ़ाने की मांग हो रही है। बहरहाल, पिछले कुछ वर्षों से अनुपस्थित रहे छोटे प्रकाशकों ने इस बार फिर से अपने स्टॉल लगाए, जो बढ़िया निर्णय है। किताबों पर छूट के मामले में भी बड़े प्रकाशनों ने 10-15 प्रतिशत से ज्यादा की छूट नहीं दी, जबकि छोटे प्रकाशकों ने खूब उदारता दिखाई। किताबों की कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी हुई थीं और कुछ प्रकाशकों ने मेले के लिए विशेष संस्करण भी महंगे दामों पर निकाले। प्रेमचंद, निराला, टैगोर, बंकिम चंद्र और स्वामी विवेकानंद आदि की क्लासिक रचनाएं सबसे अधिक बिकती नजर आईं। यह दर्शाता है कि पाठकों का झुकाव समय-परीक्षित साहित्य की ओर अब भी बना हुआ है। कई प्रकाशनों के स्टॉल पर गंभीर चर्चाएं भी देखने-सुनने को मिलीं, जिनके अपने मायने हैं। कुल मिलाकर, यह सिर्फ किताबों का मेला नहीं, बल्कि एक साहित्यिक उत्सव था। इसलिए, 'खूब किताबें पढ़िए, खूब बढ़िए।'

अंशु कुमार चौधरी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पुस्तक मेला

इसे पुस्तक नहीं, लोकार्पण मेला कहिए

पुस्तक मेला हमारे समाज की एक बड़ी घटना है। इसमें बड़ी संख्या में लेखक, प्रोफेसर, हिंदी अधिकारी और कई अन्य पुस्तक प्रेमी आते हैं। वे एक-दूसरे से आनंदपूर्वक मिलते हैं, जो अच्छी बात है, पर क्या वे पुस्तकें खरीदते भी हैं? आमतौर पर हिंदी स्टॉलों पर भीड़ तभी दिखती है, जब वहां किसी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा होता है, मानो यह पुस्तक मेला न होकर लोकार्पण मेला हो। यह भी गौर किया जा सकता है कि अंग्रेजी पुस्तकों के स्टाल पर लोकार्पण नहीं होते, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। फेसबुक पर जिसे देखो, एक किताब हाथ में लेकर प्रदर्शित कर रहा है। अब कुछ ही ऐसे दुर्लभ क्षण मिलते हैं, जब कोई लेखक अपने हाथ में खरीदी गई हिंदी किताबों का थैला लिए दिख जाए।

कुछ वर्षों से पुस्तक मेले के कंटेंट में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसी नई पुस्तकें ज्यादा दिख रही हैं, जो जल्दबाजी में लिखी गई हैं। ऊपर से राजनीति ने विषयों को काफी सीमित और एकरूप कर दिया है। शब्द पर शोर हावी है। प्रकाशन इस दरिद्रता की क्षतिपूर्ति बड़े पैमाने पर पुरानी चर्चित पुस्तकें छापकर कर रहे हैं। अब 'न्यू अराइवल्स' में पुरानी पुस्तकें भी दिख जाती हैं! पुस्तक मेले के कंटेंट में इस गिरावट की एक बड़ी वजह यह है कि हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी के बड़े प्रकाशकों को भी पैसे देकर अब किताबें छपवाई जा रही हैं। प्रकाशन संसार में लेखक के पैसे का प्रवेश इस संसार में भारी गिरावट ला रहा है, जो इस साल के पुस्तक मेले में भी साफ-साफ दिखा।

वर्तमान पुस्तक मेलों के चरित्र में एक खास बदलाव यह आया है कि राष्ट्रीय स्वरूप खोकर ये अधिक स्थानीय होते जा रहे हैं। दिल्ली में पुस्तक मेला हो, तो दिल्ली के लेखकों की जय-जयकार, लखनऊ में हो तो लखनऊ वालों की और पटना में हो, तो पटना के लेखकों की। फिर, पिछले कुछ वर्षों से पढ़ने का संकट भी बढ़ा है। भले ही बड़े-बड़े लिटरेचर फेस्टिवल या पुस्तक मेले हो रहे हों, 20-30 साल के नौजवानों की जेब में कलम और हाथ में किताब शायद ही दिखेगी। समाज में 'क्रिटिकल थिंकिंग' का भी ह्रास हो रहा है। समझना होगा कि यदि पुस्तक मेला के फूड स्टॉलों पर बुक स्टॉलों से ज्यादा भीड़ होती है और हर तरफ केवल रीनक, चहल-पहल और पुस्तकों का प्रदर्शन और 'तुम मेरी गाओ, मैं तुम्हारी गाऊं' है, तो इसका अर्थ है विश्व पुस्तक मेला अपना चरित्र खोता जा रहा है। इसका अनिवार्य सबक यही है कि हम पढ़ने के संकट को पर्यावरण के संकट की तरह गंभीरता से लें और पढ़ने की आदत बनाएं।

शंभुनाथ, शिक्षाविद

16.4 करोड़ टन भंडार है वोल्फ्रेम का भारत के पास, जबकि कोबाल्ट अयस्क का भंडार 4.49 करोड़ टन है। इन दोनों के प्रभावी तरीके से उपयोग किए जाने की दशा में इनके विश्वस्तरीय आपूर्ति को गति प्रदान की जा सकती है।

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

आजकल

यूजीसी के नए नियम व शैक्षणिक स्वतंत्रता

उच्च शिक्षा का लक्ष्य केवल उपाधियां प्रदान करना नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए ऐसे मेधावी और सुसंस्कृत नागरिकों का निर्माण करना है, जो समाज की दिशा और गति को सुगठित कर सकें। अतः यदि यूजीसी कुलपति नियुक्तिप्रक्रिया को अधिक संगठित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कोई नियम निर्धारित करता है, तो उसका विरोध करना वस्तुतः शिक्षा की शुचिता से विमुख होना है। यदि राज्यपालों की भूमिका विश्वविद्यालयों के संरक्षक के रूप में अधिक प्रभावी होती है, तो यह उच्च शिक्षा की स्थिरता और उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा

प्रतीकात्मक

संसद के वर्तमान सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों में कुलपति पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में तय नियमों को बदले जाने का संकेत दिया है। उनके अनुसार, यूजीसी के प्रस्तावित नियम न केवल इस अनुचित परंपरा पर रोक लगाएंगे, बल्कि शैक्षिक संस्थानों की निष्पक्षता एवं गरिमा को भी सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह मसौदा विश्वविद्यालयों को निजी संपत्ति बनने से रोकने का एक दृढ़ प्रयास है, जो शिक्षाजगत के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों का मानना है कि यह मसौदा सुधार की आड़ में केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है, जिससे राज्य सरकारों की भूमिका सीमित हो जाएगी और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में असंतुलन पैदा होगा।

देश के कई राज्यों में कुलपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं। विश्वविद्यालयों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होती रही है, जिनका चयन केवल उनके पारिवारिक या राजनीतिक संबंधों के कारण हुआ, न कि उनकी विद्वता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर। इससे शिक्षा का स्तर गिरा, विद्वानों का अपमान हुआ और योग्य व्यक्तियों के अवसर छिन गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई कुलपति अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिजनों को स्थापित करने के प्रयास में लगे रहे, जिससे विश्वविद्यालय निजी जागीर बनते जा रहे थे।

यदि शिक्षा को समाज का स्तंभ बनाना है, तो इसके संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है। यूजीसी का नया प्रारूप इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कुलपति का पद केवल यौग्य और कर्मठ शिक्षकों को ही प्राप्त हो। इससे न केवल विवि की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि छात्रों और शिक्षकों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि ज्ञान के मंदिरों में निष्ठावान और प्रबुद्ध नेतृत्व स्थापित करना भी है।

बौद्धिक और प्रशासनिक दायित्व : कोई भी बड़ा सुधार बिना विरोध के नहीं आता। कुछ राज्यों ने इस प्रारूप का विरोध किया है, क्योंकि यह उनकी परंपरागत नियुक्ति प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाता। परंतु, क्या परंपरा को बनाए रखने के लिए अन्याय को भी सहन किया जाए? शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह मसौदा राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं करता, बल्कि विश्वविद्यालयों को भाई-भतीजावाद से मुक्त करने का प्रयास करता है। विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि कुलपति पद किसी राजनीतिक दल या वंश की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक और प्रशासनिक दायित्व है। यदि विश्वविद्यालयों में निष्पक्षता नहीं होगी, तो वहां से निकलने वाले छात्र भी समाज में भेदभाव और भ्रष्टाचार की भावना लेकर आएंगे। कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने से ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। जिस प्रकार किसी भी राष्ट्र का आत्मा उसकी न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था में होता है, उसी प्रकार शिक्षा संस्थानों का आत्मा उनके नेतृत्व में निहित होता है। यदि विश्वविद्यालयों में पारिवारिक और राजनीतिक दबाव से कुलपतियों की नियुक्ति होती रही, तो शिक्षा प्रणाली नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस मसौदे का समर्थन करना केवल सरकारी नीति का समर्थन नहीं, बल्कि शिक्षा की अस्मिता की रक्षा करना भी है।

देख विस्मय होता है कि कुछ तत्व इस प्रगतिशील प्रयास को राजनीतिक रंग देकर अपनी विचारधारा के अनुरूप मोड़ने में लगे हैं। उनकी दृष्टि में सुधार का अर्थ बिकृति हो गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि इन बिनियमों के माध्यम से शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को बल मिलेगा, उनकी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और वे शैक्षणिक गुणवत्ता में एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर होंगे। जो लोग इन सुधारों का केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, वे शिक्षा को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटकाने का कार्य कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा न केवल ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र होती है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी को तैयार करती है। ऐसे में यदि इसकी आधारशिला को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन की चर्चा होती है, तो वह केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसकी गूंज दूरगामी प्रभाव डालने वाली सिद्ध होती है। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का विषय भी इसी कोटि का है, जिसका प्रभाव मात्र विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समूची शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा।

इस प्रस्ताव को लेकर मंतव्य भले ही शिक्षा प्रशासन को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने का हो, किंतु इसमें संदिग्ध नहीं कि इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकारों की भूमिका न्यून होगी और राज्यपालों की शक्ति में वृद्धि होगी। यह वह प्रश्न है, जो केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के मूलभूत ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। यदि विवि किसी राष्ट्र की बौद्धिक संपदा होते हैं, तो उनका नेतृत्व अकादमिक दृष्टि से योग्यतम व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, न कि प्रशासनिक समीकरणों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

किसी भी नीतिगत परिवर्तन का मूल्यांकन उसके दूरगामी प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि उच्च शिक्षा को केवल प्रशासनिक सुविधा के रूप में देखा जाएगा, तो वह अपने मौलिक उद्देश्य से दूर हो जाएगी। सत्ता-संतुलन के लिए उठाए गए कदम कभी भी शिक्षा को सशक्त नहीं बना सकते, अपितु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा नीति का निर्माण अकादमिक मूल्यों को केंद्र में रखकर किया जाए।

अतः आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें टकराव के स्थान पर संवाद का मार्ग अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि उच्च शिक्षा केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित न हो जाए। यदि विवि को एक जीवंत और स्वतंत्र संस्थान के रूप में बनाए रखना है, तो उनकी स्वायत्तता को सुरक्षित रखना होगा। शिक्षा को केवल सत्ता-संतुलन के खेल में परिवर्तित कर देने से देश की बौद्धिक संपदा को कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रस्ताव का पुनरावलोकन किया जाए और इसे अधिक संतुलित एवं सम्भावेशी रूप प्रदान किया जाए।

उच्च शिक्षा प्रणाली में स्वायत्तता पर जोर

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अपने विस्तार और विविधता में अद्वितीय है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति है, जिसमें करोड़ों युवा अपने भविष्य की तलाश में कदम रखते हैं। लेकिन यह दुखद विडंबना है कि इतने विशाल तंत्र के बावजूद गुणवत्ता की चुनौती बनी हुई है। दशकों से सुधार की कोशिशें हो रही हैं, परंतु वे वांछित सफलता नहीं दिला सकी हैं। अब समय आ गया है कि उच्च शिक्षा को मात्र संख्या का खेल न बनाकर इसे गुणवत्ता का केंद्र बनाया जाए। सरकार को चाहिए कि नीति-निर्धारण में विविधता और विस्तार दोनों का समुचित ध्यान रखे। राज्य की भूमिका केवल संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तक सीमित रहनी चाहिए, न कि उनके प्रशासन में दखल देने तक। विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया, नियुक्तियों और डिग्री प्रदान करने के मामलों में अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकें। राज्य सरकारों के अधीन चलने वाले विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए अनिवार्य मूल्यांकन और प्रमाणन कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इससे पारदर्शिता आएगी और संस्थानों की कार्यशैली में उत्तरदायित्व बढ़ेगा।

शोध कार्य किसी भी उच्च शिक्षा प्रणाली का आत्मा होते हैं। लेकिन भारत में शोध के लिए मिलने वाली फंडिंग अभी भी सीमित है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे नवाचार और खोज को बढ़ावा मिल सके। वित्तीय पारदर्शिता के लिए सरकारी संस्थानों में एक लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है, जिससे धन के सही उपयोग की निगरानी सुनिश्चित हो। धीरे-धीरे व्यावसायिक संस्थानों के परियालन खर्च के लिए सरकारी सहायता कम की जाए और केवल पूंजीगत व्यय के लिए समर्थन दिया जाए। इससे ये संस्थान आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित होंगे।

आइआइटी, आइआइएम, आइआइएससी जैसे संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि शिक्षा और शोध केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक सीमित न रहें, बल्कि मानविकी और समाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को भी उतना ही महत्व दिया जाए। कोई भी सभ्यता केवल तकनीकी प्रगति से आगे नहीं बढ़ सकती, उसके लिए इतिहास, दर्शन, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों का विकास भी अनिवार्य होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शिक्षा व्यवस्था का संचालन कौन करे? आज उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का जिम्मा नेताओं एवं शीर्ष अधिकारियों के हाथ में है, जिनकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं, बल्कि राजनीति होती है। इस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को इन संस्थानों का नेतृत्व देना चाहिए, ताकि वे ज्ञान-आधारित नीतियों पर कार्य कर सकें और छात्रों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि वास्तविक बौद्धिक संपदा प्रदान कर सकें।

उच्च शिक्षा केवल किसी व्यक्ति के करियर का साधन नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समाज की बौद्धिक संसम्पदा का आधार होती है। यदि भारत को ज्ञान-प्रधान राष्ट्र बनना है, तो उसे अपने उच्च शिक्षा तंत्र को केवल संख्या के बोझ से नहीं, बल्कि गुणवत्ता की कसौटी पर परखना होगा। अन्यथा, हम केवल डिग्रीधारकों की भीड़ बढ़ाते रहेंगे, जिनके पास न तो समुचित ज्ञान होगा और न ही नवाचार की दृष्टि।

(कैलाश बिश्नोई)

खरी-खरी

अपना अपना वसंत

दिनेश विजयवर्गीय

स्कूल के आसपास न हरियाली, न बाग बगीचा और न कहीं फूल थे। मास्टर रामसुख जी अपने स्कूल के बच्चों को प्रकृति के बीच वसंत का महत्व बताने के लिए कुछ दूरी पर बने एक बड़े फार्म पर ले गए। प्रकृति की कृपा से वहां के बगीचे में पूरा वसंती माहौल गुनगुना रहा रहा था। सारा बगीचा सुहानी धूप से तरोताजा लग रहा था। वहां अनेक किस्म के फूल खिले थे। आम के पेड़ पर कोयल अपना गीत सुना रही थी। फूलों पर तितलियां और भंवरे मंडरा रहे थे। फूलों से लदी डालियां अपनी मस्ती में झूम रही थीं। पास ही में सरसों के पीले खेत अपना मनभावन रूप बिखेर रहे थे। बच्चे ऐसे वातावरण को देख खुश हो गए।

मास्टर रामसुख जी ने बच्चों को बगीचे की हरी दूब में बिठाकर मां सरस्वती की तस्वीर लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। फिर वसंत ऋतु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मां सरस्वती के गुणगान किए। बच्चों ने गीत, कविता आदि सुनाई और कार्यक्रम के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इतने में कुछ युवक युवती ढोल की थाप पर थिरकते हुए बगीचे में आ गए, जो जय-जय वसंत, जय-जय वेलेंटाइन डे के नारे लगाते रहे। सभी लोग वहां संगीत बजाकर डांस करने लगे। बच्चे डांस का माहौल देखकर खुश हो गए और वे भी डांस करने लगे। युवक युवती भी उन्हें देख ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करने लगे। मास्टर रामसुख जी बच्चों से कहने लगे कि यह हमारी संस्कृति नहीं है, वह बच्चों को स्कूल की पगडंडी की ओर ले आगे बढ़ गए। अब भी कई बच्चे पीछे मुड़-मुड़कर युवाओं के डांस को देख रहे थे।

इधर युवक युवती लगातार डांस कर रहे थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर... सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था... कुछ कुछ होता है.....

डांस के बाद युवाओं ने खाया पिया और फिर वसंत की पीठ पर सवार हो वेलेंटाइन डे मनाते रहे। अब वे युवा प्रकृति की सुंदरता को निहारते सरसों के पीले खेत की ओर बढ़ चले। वहां अलग-अलग पोज बना कर रसीले फोटो ले बसंत और वेलेंटाइन डे को खुशियां में डूबते रहे। अब भी दूर तक ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी।

X पोस्ट

वक्फ कानून मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। उसे संविधान में शामिल किया जाना बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान है।
साकेत@saket71

देश तेजी से केशलेस हो रहा है और अगर कास्टलेस यानी जाति से भी मुक्त हो जाए तो देश की 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान संभव है।
कुसुमांजलि सिंह@kusumanjalising

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पीएम मोदी के पीछे खड़े रहे, उसी तरह मोदी अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष के पीछे खड़े रहते तो देश में अब तक बवाल मच जाता। मीम की बाढ़ आ जाती। ट्रोल्स की भीड़ आ जाती।
शुभम शुक्ला@ShubhamShuklaMP

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी, जेडी वेंस और एलन मस्क सभी ने अपने परिवार के साथ उनसे मुलाकात की। नेताओं के साथ मुलाकातों के दौरान अक्सर ऐसा नहीं दिखता। यह प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और आत्मीयता के स्तर को भी दर्शाता है।
अद्वैता काला@AdvaitaKala

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा का चयन सही है?

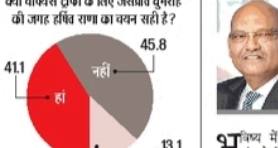

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या बांग्लादेश को लेकर ट्रंप के बयान से वहां की अंतरिम सरकार के रवैये में सुधार होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

एक बहाना चाहिए करने हेतु बवाल,
लिये वक्फ बिल हाथ में करने लगे सवाल!
करने लगे सवाल सदन में शोर मचाए,
ज्यों मौका मिल जाय देश में आग लगाए।
खरगे जी ने सेंड दिया बेसुर में राग,
उन्हें मिल गया तुष्टिकरण का एक बहाना!!
- ओमप्रकाश तिवारी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार डायरी

बजट और प्रगति यात्रा से विकास की आस

बिहार में बाढ़ और सूखे से भले ही हर फसल तबाह होती हो, परंतु राजनीति की फसल कभी तबाह नहीं होती है। यह हमेशा लहलहाती रहती है। यह अलग बात है कि उत्पादन अक्सर मन लायक नहीं होता है। किसान की तरह राजनीति से जुड़े लोग भी निराश नहीं होते हैं। इस आशा में जीने लगते हैं कि अगली फसल जरूर अच्छी होगी। ऐसा होता भी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को केवल एक सीट मिली तो सत्तारूढ़ एनडीए इतराने लगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसकी ऐसी ही जीत होगी। करीब डेढ़ साल के अंतराल पर विधानसभा के चुनाव हुए तो एनडीए कठिनाई से बहुमत के आंकड़े जुटा पाया। निर्दलीय विधायक के समर्थन के अलावा लोजपा और बसपा के एक-एक विधायक को जदयू में शामिल कराकर सरकार का गठन किया गया। समय-समय पर विधायकों का प्रबंधन भी करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया, जब एनडीए से अलग होकर जदयू मुख्य विपक्षी दल राजद के साथ चला गया।

यह विधायकों की कम संख्या का ही प्रभाव था कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़े रहने में असहज महसूस करने लगे थे। राजद के साथ भी वैसी ही असहजता महसूस हुई तो फिर से एनडीए में आ गए। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के पक्ष में गया। लेकिन, परिणाम 2019 की तरह उत्साहजनक नहीं था। नौ जीती हुई सीटें हाथ से निकल गईं। इस झटके ने एनडीए के सभी घटक दलों को एक दूसरे का सम्मान करने का संदेश दिया। वर्तमान में एनडीए के सभी घटक दल एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। कुछ नेता आदतन ऐसा वक्तव्य दे देते हैं, जिससे गठबंधन में अनबन का भ्रम होने लगता है। इस सबके बावजूद एनडीए 243 में 225 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। यह लोकसभा चुनाव के उस दावे से थोड़ा कम है, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा की सभी 40 सीटों पर उसकी जीत होगी। इस दावे में जनता ने 25 प्रतिशत की कटौती कर दी। विधानसभा चुनाव में इसी दर पर कटौती हुई, तब भी एनडीए अगली सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त हो सकता है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन बहुमत चाहिए।

राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों के बीच यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है क्या विधानसभा चुनाव में जदयू को कम सीटें आने पर भी भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेगी? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार का कोई विकल्प उभर के सामने नहीं आया है। विधानसभा में भाजपा और राजद की तुलना में नीतीश कुमार को भले ही कम सीटें मिली हों, लेकिन बीते पांच वर्षों में कोई ऐसा चेहरा उभर कर नहीं आया है, जो नीतीश कुमार के समानांतर तो क्या, उनके आसपास भी खड़ा हो सके। ले देकर उनकी उम्र का हवाला देकर विकल्प की जरूरत बताई जा रही है। उम्र या स्वास्थ्य से सरकार का निर्णय प्रभावित हो रहा है, यह उदाहरण सामने नहीं है। अभी नीतीश प्रगति यात्रा पर हैं। उत्तर बिहार की प्रगति यात्रा के बीच में ही उन्होंने उस क्षेत्र के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के अधिक की योजनाओं की घोषणा की। उन्हें लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में करीब 20 हजार किमी लंबी ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इस पर व्यय के लिए 17 हजार करोड़ से अधिक के व्यय के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पारित किया। 22 फरवरी को प्रगति यात्रा समाप्त हो रही है। माना जा रहा है कि इस तिथि के आसपास दक्षिण बिहार के लिए भी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

इसके अलावा केंद्रीय बजट में राज्य के लिए किए गए आर्थिक प्रविधान को भी नीतीश एनडीए की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल जिलों में सम्मेलन कर रहे हैं। अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। राज्य के 2025-24 के सालाना बजट में भी चुनाव को ध्यान में रख कर लोकलुभावन घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से दोनों गठबंधन का उत्साह बढ़ा हुआ है। एनडीए के घटक दल इसे भाजपा की जीत मान रहे हैं। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का उत्साह यह सोच कर बढ़ा हुआ है कि बीटों के बिखराव को रोकने के लिए उन्हें मुँहमांगी सीटें दी जा सकती हैं। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के विश्लेषण का एक हिस्सा अगर सत्ता विरोधी रुझान की पुष्टि करता है तो इसका दूसरा हिस्सा भाजपा की जीत का श्रेय उसके विरोधी वोटों के बिखराव को देता है। वैसे, चुनाव की तैयारियों को देखें तो महागठबंधन की तुलना में एनडीए बहुत आगे चल रहा है। इसके घटक दलों ने अपनी बुनियादी इकाइयों को सक्रिय कर दिया है।

जहानाबाद में शुक्रवार को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

मंथन

अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता समूह

भारत में खनिज उत्पादन

विश्व में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग निरंतर बढ़ रही है। भारत में यह क्षमता है जो इस मांग को पूरा कर सके। आवश्यकता इस दिशा में समुचित प्रयास किए जाने की है

प्रतीकात्मक

भविष्य में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ेगी। इनके उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था अपनाए जाने पर भी जोर दिया जाएगा। स्थायी आपूर्ति शृंखला को सुनिश्चित करना, पहले विश्वस्तरीय समुदायों के लिए अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण विषय नहीं था। अपने अमृयुक्त संसाधनों के साथ भारत कम कार्बन की विश्वस्तरीय अर्थव्यवस्था की ओर मजबूती से बढ़ने की स्थिति में है। कापर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, जिंक आदि की आपूर्ति को सुलभ बनाना कार्बन के न्यूनतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अतः देशों के लिए अपने ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों के तहत घरेलू स्तर पर इन भंडारों को सुनिश्चित करना और इन्हें सुलभ बनाना आवश्यक है।

मैक्सिको की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी दशक में सभी महत्वपूर्ण खनिजों की मांग ऐतिहासिक रूप से बढ़ जाएगी, जिसमें विशेष रूप से कापर की मांग सबसे अधिक रहेगी। इन रुझानों को देखते हुए अल्पकालिक उपायों की लोकप्रियता बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसका हल संभवतः उन देशों के बीच आपसी सहयोग में निहित है, जो एक साथ मिलकर काम करने और इन संसाधनों को सुरक्षित रूप से सहृपयोग करने में सक्षम हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आइईए) के अनुसार, मुख्य ऊर्जा रूपांतरण खनिजों के मार्केट का संयुक्त आकार 2040 तक दोगुना होकर 770 अरब डालर तक पहुंच जाएगा। वहीं ब्लूमबर्ग एनईएफ (बीएनईएफ) के अनुसार दुनिया को 2024 एवं 2050 के बीच कम कार्बन के समाधानों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन और इलेक्ट्रीलाइजर बनने तथा भावी पीढ़ियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने तीन अरब मीट्रिक टन धातुओं और खनिजों की आवश्यकता होगा। यह संख्या 2050 तक छह अरब टन तक पहुंच जाएगी।

आपूर्ति एवं मांग : हम मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत से लोगों के लिए यह एक चुनौती है, परंतु यह हमारे लिए बड़ा अवसर है। हमें इस सेक्टर में प्रत्यक्ष निवेश को सुनिश्चित करना होगा। दुनिया के विकसित देश, महत्वपूर्ण खनिजों व प्राकृतिक संसाधनों की मजबूती के चलते ही विकास के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस संदर्भ में अमेरिका, यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया या आस्ट्रेलिया पर विचार किया जा सकता है। इस सेक्टर में बड़े निवेश किए गए हैं, हालांकि कच्चे माल के लिए शुद्ध-शून्य मांग को पूरा करने हेतु विश्वस्तरीय खनन उद्योग को 2050 तक लगभग 2.1 लाख करोड़ डालर का नया निवेश करना होगा। इस निवेश के लिए प्रगतिशील नीतियों एवं अनुकूल विनियमों की भी आवश्यकता है, जो जमीन एवं लाइसेंस को सुलभ बना सकें, विश्वस्तरीय तकनीकों के उपयोग, स्थायी खनन प्रथाओं, संचालन के सेल्फ-सर्टिफिकेशन तथा रिटर्न के एक समान वितरण को बढ़ावा दे सकें।

दूसरा, सशक्त एवं भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला के विकास के लिए भी सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। दुनिया भर में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में ट्रांसनेशनल मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (एमएसपी), जो महत्वपूर्ण खनिज सेक्टर के जिम्मेदाराना विकास को बढ़ावा देते हैं। एमएसपी पहले से आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, यूके और ईयू सहित 23 पार्टनर्स को सहयोग प्रदान करता है। इसने कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जो इन संसाधनों को सुलभ बनाते हैं।

अप्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिज : भारत के पास खनिजों का विशाल भंडार है, लेकिन अब तक भारत को 20 प्रतिशत भूवैज्ञानिक संपदा का अन्वेषण किया गया है। ऐसे में विश्वस्तरीय निवेशकों और साझेदार देशों के लिए भारत में अपार संभावनाएं हैं। सिर्फ दो महत्वपूर्ण खनिजों की बात करें तो भारत के पास कापर का 16.39 करोड़ टन भंडार है तथा कोबाल्ट अयस्क का 4.49 करोड़ टन भंडार है। अगर इन दोनों का उपयोग सही समय पर, प्रभावी और स्थायी तरीके से किया जाए तो विश्वस्तरीय आपूर्ति को गति प्रदान की जा सकती है। भारत पहले से धातुओं को रीसाइकल करने में अग्रणी है। सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027-28 के बाद से सभी नए नान-फेरस उत्पाद में पांच प्रतिशत रीसाइक्ल्ड कंटेंट होना अनिवार्य है।

भारत के खान मंत्रालय ने इसी साल यह घोषणा की है कि मंत्रालय ने अपनी आधी नियोजित घरेलू अन्वेषण परियोजनाओं को महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे ग्रेफाइट, मालिब्डेनम, निकल, कोबाल्ट, लिथियम और पोटाश) के लिए निर्धारित करने की योजना बनाई है। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है 2024 में लांच किया गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जिसका उद्देश्य अन्वेषण से लेकर खनन, प्रसंस्करण और दोबारा उपयोग लायक बनाने के लिए हर चरण में भारत को महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला को बढ़ावा देना है। यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों के लिए औद्योगिक मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से की गई है।

****

दैनिक जागरण
आलोचना व्यक्तित्व को निखारने वाला सावुन है

भारत-अमेरिका की दोस्ती

भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात पर देश ही नहीं, दुनिया की भी निगाहें थीं। एक तो इसलिए कि मोदी उन चुनिंदा शासनाध्यक्षों में से एक हैं, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रारंभिक दौर में ही मुलाकात करना बेहतर समझा और दूसरे इसलिए कि भारत अब एक बड़ी ताकत बन चुका है और वैश्विक मामलों में उसका रुख-रवैया मायने रखता है। इस मुलाकात को लेकर जिज्ञासा का एक कारण यह भी था कि बाइडन प्रशासन के समय अमेरिका और भारत के संबंधों में एक खिंचाव आ गया था। एक अर्से से यह महसूस किया जा रहा था कि बाइडन प्रशासन भारतीय हितों की वैसी चिंता नहीं कर रहा है, जैसी करनी चाहिए। मोदी और ट्रंप की मुलाकात ने यह तो रेखांकित किया कि दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी लौट आई है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका भारत की समस्त चिंताओं का समाधान करने जा रहा है। इसका संकेत इससे मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के मामले में भी पारस्परिक टैरिफ की नीति पर चलने की घोषणा कर दी। यदि ट्रंप प्रशासन इस घोषणा पर वास्तव में अमल करता है तो जापान, यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में हो सकता है। पारस्परिक टैरिफ से भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में स्थान बनाना कठिन हो सकता है। इसके नतीजे में अमेरिका में भारतीय निर्यात घट सकता है। इससे भारत के आर्थिक हितों को नुकसान होगा, क्योंकि जीडीपी में निर्यात की अहम भूमिका है और अमेरिका हमारा प्रमुख व्यापारिक सहयोगी देश है।

यह ठीक है कि ट्रंप ने बांग्लादेश के मामले में भारत के मन मुताबिक बात कही, सीमा पार यानी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से मिलकर लड़ने का वादा किया और मुंबई हमले की साजिश में शामिल रहे पाकिस्तान मूल के कनाडाई आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की, लेकिन अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों पर कुछ नहीं कहा। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान ऊर्जा, तकनीक के साथ अन्य कई क्षेत्रों में जो अनेक समझौते हुए, उनसे यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के संबंधों में और प्रगाढ़ता आने जा रही है। इसका पता इससे भी चलता है कि विकसित भारत के लक्ष्य में सहायक बनने वाले विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका से सहयोग की यह प्रशस्त होती दिख रही है और अब भारत अमेरिका से कच्चा तेल और गैस खरीदने के साथ आधुनिक रक्षा उपकरण एवं तकनीक हासिल करने में भी समर्थ होगा, लेकिन क्या लड़ाकू विमान एफ-35 की खरीद हमारी प्राथमिकता सूची में शामिल है? इसमें संदेह नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात ने मैत्री संबंधों को मजबूत करने का माहौल बनाया, लेकिन यह समय बताएगा कि ट्रंप भारत की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं या नहीं?

बजट की दिशा

संभावना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार खड़े हो रहे आधारभूत ढांचे और विकास को गति देने के लिए आगामी बजट में 84 हजार करोड़ रुपये ऋण लेने की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें बुराई नहीं, लेकिन अब इसका उपयोग छोटे शहरों, कस्बों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाए। तेज विकास के लिए कर्ज की आवश्यकता पड़ती ही है। महत्वपूर्ण यह है कि उसका उपयोग किस मद में किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सड़कों का संजाल बिछाने, बिजली-पानी और सीवर जैसी सुविधाएं खड़ी करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के लिए संसाधन बढ़ाने और तीर्थ-पर्यटन को विस्तार देने के लिए अधिकाधिक राशि व्यय की गई है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार में दिख रहा है, किंतु गत सात-आठ वर्षों में नगरीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है। महानगरों की भांति छोटे नगरों-जनपदों में भी नागरिक सुविधाओं की आकांक्षा बढ़ी है। एक जिला एक उत्पाद जैसे प्रयोगों और इन्वेस्टर समिट के माध्यम से छोटे जनपदों के लिए योजनाएं तैयार हैं। छोटे शहरों में विकास की योजनाएं तभी सिरे चढ़ेंगी जब यहां भी बड़े नगरों जैसी आधारभूत और नागरिक सुविधाएं दी जाएं। आशा की जानी चाहिए कि आकांक्षात्मक जिलों एवं विकास खंडों की भांति बजट में छोटे जिलों व नगरों पर इस बार पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

> छोटे शहरों में विकास की योजनाएं तभी सिरे चढ़ेंगी जब यहां भी बड़े नगरों जैसी आधारभूत और नागरिक सुविधाएं दी जाएं

तैयार हुआ भविष्य के संबंधों का खाका

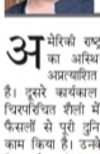

हर्ष वी. पंत

भारत-अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर जरूर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन परस्पर हितों की गहरी समझ और मोदी-ट्रंप की आत्मीयता के चलते भविष्य में उनके भी सुलझने की उम्मीद है

अवधेश राजपूत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अस्थिर, अनपेक्षित एवं अप्रत्याशित स्वभाव सर्वविदित है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अपनी चिरपरिचित शैली में एक के बाद एक फैसलों से पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया है। उनके रुख से स्पष्ट है कि पहले कार्यकाल की तुलना में राष्ट्रपति के रूप में अपनी दूसरी पारी में उनका रवैया और आक्रामक रहने वाला है। वह अमेरिका की प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देशों को भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों की नई रूपरेखा बनानी पड़ रही है। ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। दोनों नेताओं की बातचीत में कई उलझाऊ मुद्दों के सुलझने के आसार बनते दिखे तो अगले चार साल के लिए द्विपक्षीय संबंधों का खाका भी खिंचा।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बैठक में निजी आत्मीयता के भी दर्शन हुए। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 'उन्हें उनकी कमी महसूस हो रही थी।' इजरायली प्रधानमंत्री, जापानी प्रधानमंत्री और जार्डन के राजा के बाद मोदी चौथे वैश्विक नेता हैं, जिनकी ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में मेजबानी की। इस तरह सांकेतिक तौर पर भी इस दौरे की महत्ता सहज ही समझी जा सकती है। ट्रंप का जैसा व्यक्तित्व है उसे देखते हुए उनके साथ समीकरण दुरुस्त रखने में निजी संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री को ट्रंप ने मित्र के रूप में संबोधित करते हुए उन्हें 'टफ नेगोशिएटर' यानी सौदेबाजी में सख्त और दक्ष भी बताया। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के विजन 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' और अपनी संकल्पना 'विकसित भारत' के बीच समानता दर्शाते हुए साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

दुनिया भर के देश जिस तरह अमेरिका के साथ अपने संबंधों के पुनर्संयोजन में लगे हैं, उसे देखते हुए भारत को भी देर-सबेर यह काम करना था। प्रधानमंत्री के दौरे के साथ यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू भी हो गई। ट्रंप प्रशासन इस समय टैरिफ को लेकर बहुत आक्रामक है और पीएम मोदी के साथ बैठक से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने जवाबी टैरिफ को लेकर कदम बढ़ाने की घोषणा भी की। स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी टैरिफ का एलान जरूर किया है, लेकिन अभी उसके लिए आकलन एवं अन्य पहलुओं को तय किया जाना शेष है। ऐसे में कहीं न कहीं भारत के लिए अपने हितों को सुरक्षित बनाए रखने की गुंजाइश बनी हुई है। अब यह वार्ताकारों पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे तय है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और इस राह में संभावित अवरोधों को समय रहते दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा। हिंद प्रशांत से लेकर पश्चिम एशिया में परस्पर हितों के लिए दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को सैन्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से और मजबूती मिलेगी। जहां तेल एवं गैस की बिक्री से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं हाइड्रोकार्बन खरीद में विविधीकरण बढ़ेगा और कुछ पश्चिमी देश निर्भरता घटेगी। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ जैसे नए उभरते हुए क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच बढ़ता हुआ सहयोग न केवल द्विपक्षीय, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को भी लाभ पहुंचाएगा।

रूस-यूक्रेन के बीच तनाव घटाने को लेकर ट्रंप जिस तरह सक्रिय एवं प्रतिबद्ध हैं, उससे भी भारत के लिए वैश्विक व्यापार में सुगमता बढ़ेगी, क्योंकि बाइडन प्रशासन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए थे। इसी तरह चाबहार बंदरगाह का मामला ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर छोड़ दिया है कि वही तय करें कि क्या करना है। इससे यही संकेत मिलता है कि भारत को छूट जारी रहेगी।

सामरिक मोर्चे पर भी दोनों देशों की जुगलबंदी और बेहतर हो रही है। पश्चिम एशिया से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों देशों ने अपने प्रयासों की प्रतिबद्धताओं को पुनः व्यक्त किया है। पश्चिमी एशिया में जहां आइटूयूटू को व्यापकता दी जाएगी वहीं हिंद-प्रशांत के लिए हिंद महासागर पहल की घोषणा की गई है। अमेरिका बार-बार स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बात दोहराता है और यह सुनिश्चित करने में भारत की साझेदारी को अहमियत देता रहा है। चीन की बढ़ती हुई चुनौती और प्रमुख वैश्विक व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के ऐसे प्रयास बहुत आकर्षक भी हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों की साझा चिंता सामने आई। अमेरिका ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं से भी अमेरिका ने सहमति जताई है। भारत के लिए परेशानी बढ़ा रहे बांग्लादेश के मामले में तो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस पड़ोसी देश के मामले में जो करना है वह प्रधानमंत्री मोदी ही तय करें। इसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए कड़ा संदेश समझा जाए, जिसके बारे में माना जाता है कि बाइडन प्रशासन की मेहरबानी से ही वह अस्तित्व में आ सकी।

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में आर्थिक, सामरिक एवं रणनीतिक संबंधों पर व्यापक सहमति बनी है। दोनों देश 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधों को आकार देने की दिशा में आगे बढ़े हैं। कुछ मुद्दों पर जरूर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन मोदी-ट्रंप की आत्मीयता और परस्पर हितों की गहरी समझ को देखते हुए आने वाले समय में उनके भी सुलझने की उम्मीद बढ़ी है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

सांस्कृतिक विविधता का अनूठा उत्सव

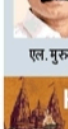

एल. मुरुगन

काशी तमिल संगमम आयोजन एक उत्सव मात्र नहीं है, वरन यह हमारी सामूहिक पहचान की पुनः पुष्टि है

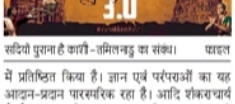

सदियों पुराना है काशी-तमिलनाडु का संबंध। फाइल

काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। यह भारत की विविधता में एकता का एक और प्रमाण है। 15 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह अनूठा सांस्कृतिक संगम देश के दो सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों-काशी और तमिलनाडु को एक साथ लाता है। यह अनूठा सांस्कृतिक संगम भूगोल से परे प्रगाढ़ सभ्यतागत बंधन को बढ़ावा देता है। काशी तमिल संगमम का उद्घाटन 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण है। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंग के रूप में आरंभ की गई भारत सरकार की यह पहल एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को कायम रखती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि इस कार्यक्रम का तीसरा संस्करण भारत के सबसे सम्मानित संतों में से एक महर्षि अगस्त्यर (अगस्त्य) की स्मृति में मनाया जाएगा। महर्षि अगस्त्यर की बौद्धिक क्षमता तमिल भाषा और साहित्य, साझा मूल्यों, ज्ञान परंपराओं और विरासत की नींव के रूप में कार्य करती है। इस वर्ष काशी तमिल संगमम का विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी आयोजन अवधि महाकुंभ के साथ मेल खाती है और अयोध्या में श्रीरामलला की 'प्राण प्रतिष्ठा' के बाद यह पहला संगम है। महाकुंभ और श्री अयोध्या धाम की पृष्ठभूमि और महर्षि अगस्त्यर पर मुख्य फोकस के साथ काशी तमिल संगमम उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा। यह भारत के दो प्राचीन शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध को इतना प्रगाढ़ करेगा, जितने पहले कभी नहीं हुए। काशी तमिल संगमम 3.0 के लिए सरकार ने तमिलनाडु से 1,000 प्रतिनिधियों को लाने की योजना बनाई है। इसमें युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। काशी तमिल संगमम के दौरान उपस्थित लोगों को काशी एवं तमिलनाडु, दोनों की उत्कृष्ट कला का अनुभव होगा।

सदियों से तमिल संतों, ऋषियों और विद्वानों ने काशी की यात्रा की है, जिसने इसके आध्यात्मिक और शैक्षणिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। तमिल समुदाय ने काशी को पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ज्ञान एवं परंपराओं का यह आदान-प्रदान पारस्परिक रहा है। आदि शंकराचार्य से लेकर महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार तक, काशी में तमिल सांस्कृतिक पदचिह्न गहरे और स्थायी रहे हैं। सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक महाकवि भरतियार का घर काशी में हनुमान घाट के तट पर स्थित तीर्थ स्थल है। काशी-तमिलनाडु का संबंध सदियों पुराना है। तमिल संत कुमारगुरुपरा देशीकर ने 17वीं शताब्दी में हनुमान घाट पर कुमारस्वामी मठ की स्थापना की, जिससे काशी में तमिल उपस्थिति स्थापित हुई। श्रीकाशी नतुकोट्टई नगरथर सतराम ने 200 वर्षों से अधिक समय से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद की सुविधा प्रदान की है। कुछ विज्ञानकारी ताकतों ने हमारे सामाजिक तानेबाने को बिगाड़ने का प्रयास किया है और इसी सिलसिले में एक क्षेत्र को दूसरे के खिलाफ, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एकता, विकास और समावेशिता के मार्ग पर दृढ़ता से काम किया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने वाला मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो हर समुदाय और क्षेत्र के लिए समान प्रगति सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाई और सांस्कृतिक सद्भाव का लगातार समर्थन किया है। उनके भाषण प्रायः तमिल साहित्य, भाषा और परंपराओं की समृद्ध विरासत को उजागर करते हैं। उन्होंने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। तमिल इतिहास के संरक्षण और सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना और जकार्ता के मुरुगन मंदिर में महाकुंभाभिषेकम समारोह में उनकी भागीदारी से प्रदर्शित हुई। वाराणसी में काशी तमिल संगमम-2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी-वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई और अन्य क्लासिक तमिल साहित्यिक कृतियों के बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद का शुभारंभ किया था। उन्होंने भारतीय विचार और संस्कृति को इस दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत राष्ट्र के लोगों के करीब लाने के लिए गुजराती और पापुआ न्यू गिनी की भाषा टोक पिसिन में तिरुक्कुरल जारी किया। यह पहल तमिलनाडु के साथ उनके गहरे संबंध को मजबूत करती है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत की व्यापक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

काशी-तमिल संगमम के तीसरे पड़ाव में तमिलनाडु के हजारों प्रतिभागी राष्ट्र को एकजुट करने वाले शाश्वत संबंधों के साक्षी बनेंगे। यह आयोजन उत्सव मात्र नहीं, वरन हमारी सामूहिक पहचान की पुनः पुष्टि है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक समावेशिता के मार्ग पर चल रहा है, ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक परंपरा और प्रत्येक समुदाय को हमारे राष्ट्रीय आख्यान में उचित मान्यता मिले। आज जब हम काशी तमिल संगमम 2025 का उत्सव मना रहे हैं, तब यह याद रखें कि हमारी विविधता कोई चुनौती नहीं है, वरन यह संजोने के लिए एक खजाना है। काशी और तमिलनाडु की एकता ही भारत की एकता है। हमें सदैव इसका उत्सव मनाना चाहिए।

(लेखक सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्यमंत्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

एकांत और अकेलापन

अकेलापन नकारात्मक तथा एकांत सकारात्मक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य के शरीर में पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्य अपनी इंद्रियों को तृप्त करता है। किसी वस्तु को देखने पर मनुष्य को उसकी प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। फिर वह उसे पाने का प्रयास करता है। यदि प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसमें क्रोध जागृत होने लगता है, जिसकी परिणति अकेलेपन और निराश में होती है, लेकिन जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है वह हर समय और हर स्थान पर शांति और एकांत का अनुभव करता है।

बहुत से बुजुर्ग जीवन के अंत में अकेला महसूस करते हैं। यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है तो वे जहां पर भी हैं वहां पर एकांत का अनुभव करते हुए शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उनमें क्रोध जागृत होता है तथा इसी क्रोध, लोभ और मोह की स्थिति में दुखी होकर अकेला महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। वे दोबारा भवसागर में फंसकर संसार की विभिन्न योनियों में कर्म अनुसार जन्म लेते हैं।

आज के युग में संन्यास के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए परिवार के साथ रहकर भी एक संन्यासी का जीवन जी सकता है, परंतु अक्सर मनुष्य अपनी इंद्रियों के जाल में फंसकर उनको तृप्त करने में ही लगा रहता है। जब ये इंद्रियां तृप्ति नहीं होती हैं तो वह स्वयं को अकेला और निराश महसूस करता है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए स्वयं को अकेले के स्थान पर एकांत महसूस करना चाहिए। ईश्वरभक्ति में लीन होते हुए संतुष्टि का अनुभव करते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।

कर्नल शिवदत्त सिंह

अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में नई संभावनाएं

प्रदीप

चिकित्सकों ने सुअर की किडनी का एक इंसान में प्रत्यारोपण कर चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

अंग प्रत्यारोपण चिकित्सा विज्ञान का वह क्षेत्र है, जिसने लाखों जिंदगियों को नई दिशा दी है, लेकिन अंगदान की कमी और प्रत्यारोपण के बाद अंग अस्वीकृति जैसी चुनौतियां हमेशा इस क्षेत्र के विकास में बाधा रही हैं। हाल में चिकित्सकों ने सुअर की किडनी का एक इंसान में सफल प्रत्यारोपण कर चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता उन लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, जो किडनी फेल्योर की समस्या से जूझ रहे हैं। सुअर के अंगों का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। सुअरों की शारीरिक संरचना इंसानों से काफी हद तक मिलती-जुलती है, जो उन्हें अंगों के संभावित स्रोत के रूप में उभरने में मदद करती है। यह तकनीक न केवल किडनी, बल्कि हृदय, जिगर और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के प्रत्यारोपण में भी उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा जैव-इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग तकनीकों के जरिये सुअर के अंगों को इंसानी शरीर के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है।

यह अवधारणा नई नहीं है। 1996 में स्काटलैंड के शोधकर्ताओं ने 'हाली' नामक भेड़ को क्लोनिंग तकनीक से बनाया था। इसके बाद से विज्ञानी प्रयोगशालाओं में इंसानी अंगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पेट्री डिश में स्टेम कोशिकाओं से अंग विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहा है, क्योंकि इन कोशिकाओं को सही तरीके से परिपक्व अंगों में बदलना मुश्किल है। यही कारण है कि विज्ञानी अब जानवरों के भ्रूण में मानव स्टेम कोशिकाओं को विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सुअरों के अलावा गाय, भैंस, चूहे और भेड़ जैसे जानवरों में भी मानव अंगों को विकसित करने के प्रयास जारी हैं। इस तकनीक से अंगदान की भारी कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही 3डी प्रिंटिंग और स्टेम सेल तकनीक जैसी नई विधियां भी अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। भविष्य में इन तकनीकों के व्यापक उपयोग से अंग प्रत्यारोपण न केवल सुलभ और सुरक्षित होगा, बल्कि यह अधिक किफायती भी हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी हैं। नैतिक और कानूनी प्रश्न, संक्रमण का खतरा और ऊंची लागत जैसे मुद्दों को सुलझाना अभी बाकी है। कुछ समाजशास्त्री और पर्यावरणविद् इन तकनीकों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानते हैं। इसके बावजूद, विज्ञानी इन चुनौतियों का समाधान खोजने में जुटे हैं। बहरहाल इस दिशा में प्रगति जारी रही, तो अंग प्रत्यारोपण चिकित्सा विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे न केवल लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि यह तकनीक भविष्य में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने में भी सक्षम होगी।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

मेलबाक्स

सराहनीय प्रयास

'सरल आयकर' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। केंद्र सरकार का यह अच्छा प्रयास है कि वह आयकर व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने क्यों पुराने आयकर कानून को बदलने के लिए एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह भी जरूरी नहीं कि परिवर्तन से हर किसी को फायदा हो। उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इससे किसी वर्ग को परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। हमारे देश में आयकर को लेकर बहुत सी भ्रांतियां और गलतफहमियां हैं। इस कारण बहुत से लोग आयकर देने से कतराते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम आयकर देंगे तो आयकर विभाग हमें परेशान करेगा। हमसे बहुत तरह के सवाल पूछेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। हां, अगर कोई कर के दायरे में होने पर भी आयकर नहीं देता है तो ऐसे लोगों को भविष्य में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आयकर विभाग के पास हमारी आय का रिकार्ड होता है। इसलिए जिनका भी आय पर कर बनता है वे अपना आयकर जरूर दें। सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सभी आयकर छुपाने वालों की पहचान हो सके और आयकर की भ्रांतियां दूर हो सकें। कर लगाकर खजाने भरने की परंपरा तो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। यह अलग बात है कि आज कर जुटाने की प्रक्रिया में अंतर आ गया है। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में टैक्स प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए कर व्यवस्था में जनभागीदारी बढ़ाने, टैक्स के प्रति जन-जन को जागरूक करने और लोगों के दिल-दिमाग से कर के प्रति खौफ को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास सराहनीय है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सफल अमेरिकी यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थीं। जिसपर भारत तो बहुत ही उत्सुकता से इस दौरे से होने वाले लाभ पर नजर टिकाए हुए थे। मोदी अपने प्रत्येक कार्यक्रम एवं विदेशी दौरे को इस तरह से नियोजित करते हैं कि उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भेंट होने के पूर्व उन्होंने उनकी सरकार के प्रमुख अधिकारियों अमेरिका की नेशनल इंटेलीजेंस की नव्निगुक्त प्रमुख तुलसी गबार्ड, एनएसए माइकल वाल्टज एवं सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एवं टेस्ला सीईओ एलन मस्क से भेंट की। इसके अतिरिक्त उन्होंने रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी से भी भेंट की। गबार्ड सनातनी हैं और पूर्व में कई बार भारत के समर्थन में दिखती रही हैं। उनकी एवं मोदी की मुलाकात में खुफिया जानकारी को लेकर सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान पर सहमति बनी। मुंबई बम ब्लास्ट के कुख्यात अपराधी तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत भारत लाया जाएगा। इस दौरे में अमेरिका से उच्च शिक्षा, रक्षा, आर्थिक, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। कांग्रेसी नेता शशि थरूर तक ने मोदी की इस यात्रा को अत्यधिक सफल बतलाया है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

दूर हों खामियां

देश में प्रतिष्ठित परीक्षाएं आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए अब सवालों के घेरे में आ गई है। जेईई मेन के प्रश्न पत्र में आए 12 गलत प्रश्नों सहित सिलेबस से बाहर के भी प्रश्न पूछे गए। साथ ही इस परीक्षा में अनुबंद से संबंधित अनेकों गलतियां भी की गईं। एनटीए पर देश में बहुआयामी, प्रतिष्ठित परीक्षाओं को आयोजित कराने का जिम्मा है। ऐसी स्थिति में उससे गलती करने की अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन इस एजेंसी पर बार-बार गलतियां करने का ठप्पा लग रहा है। जिसकी वजह से इसकी साख में भी गिरावट हो रही है। एनटीए पर लाखों विद्यार्थियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की एक बहुत बड़ी चुनौती है।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

चिंतन

अपने हितों की रक्षा के साथ अमेरिका से गहरे हों रिश्ते

अवैध प्रवासियों की वापसी के तरीके को लेकर भारत में अमेरिकी रवैये की हो रही आलोचना और मोदी और ट्रंप की वार्ता से ठीक चंद घंटे पूर्व टैरिफ पर अमेरिका के जैसे को तैसा फैसले के बीच भारत और अमेरिका ने कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए तनावपूर्ण भूराजनीतिक स्थिति में अपनी ट्रेड व सामरिक हित को अपने द्विपक्षीय रिश्ते के केंद्र में रखा है। शायद पहली बार अमेरिका ने खुलकर भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए तेल व गैस के निर्यात व अपने खास फाइटर प्लेन देने की इच्छा जताई है। भारत और अमेरिकी सरकार की तरफ से आई खबरों के मुताबिक, मोदी व ट्रंप के बीच रक्षा, ऊर्जा व ट्रेड क्षेत्र के सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अवैध प्रवासियों को भेजने के तरीके, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, रक्षा डील, रेसीप्रोकल टैरिफ और तेल व गैस आपूर्ति आदि शामिल हैं। वाशिंगटन नई दिल्ली को अत्याधुनिक एफ-35 लड़ाकू विमान देगा। इंडो-यूएस आपसी ट्रेड को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर सालाना पर पहुंचाने के समझौते पर सहमत हुए हैं। दोनों मुल्क शुल्क दर में कमी लाने और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने के लिए आपसी वार्ता करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पीएम की इस यात्रा का कूटनीतिक व सामरिक महत्व है। सबसे पुराने व सबसे बड़े लोकतंत्र की जुगलबंदी दोनों मुल्कों के हित में है। भारत ने संतुलन बनाते हुए अमेरिका के साथ-साथ रूस, चीन, यूरोप के साथ संतोषप्रद संबंध बनाए रखा है। भारत और अमेरिका के बीच रूस व यूक्रेन जंग, आतंकवाद के मुद्दों पर भी बात हुई है। भारत ने एक बार फिर से शांति के साथ रहने की अपनी बात दोहराई है। ट्रंप जैसे अस्थिर व्यक्तित्व के नेतृत्व में अमेरिकी हित के बीच में मेक इन इंडिया ब्रांड को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से विश्व में ट्रेड वार बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क से प्रभावित होकर अमेरिकी नीतियों को आकार दे रहे हैं। इससे अमेरिका एक स्लोबल इंक की तरह व्यवहार करते दिख रहा है, जबकि अमेरिका की प्रतिष्ठा वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने की रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व पेरिस जलवायु करार से बाहर आना, अमेरिकी सरकारी खर्चे में कटौती के लिए कदम उठाना आदि के चलते अमेरिका के हित को ही दीर्घावधि में नुकसान पहुंचेगा। भारत जैसे विकासशील देशों को अपने बाजार विश्व व्यापार नियमों का पालन करते हुए भी सोच समझकर ही खोलना होगा। भारत किसी देश के हित के लिए अपने सुरक्षित बाजार को डंपिंग यार्ड में कभी भी तब्दील नहीं करेगा। आपसी व्यापार संबंध पूरी तरह से 'कॉम्पैक्ट' (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य तथा प्रौद्योगिकी के लिए अवसर उत्पन्न करने) आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अमेरिका जवाबी शुल्क लगाने में भारत को छूट नहीं देगा, यह राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है। ट्रंप ने सभी इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद भारतीय इस्पात उत्पादकों को अपने उत्पादों के निर्यात में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत को अमेरिका के सामने डटे रहना होगा, अपनी नाराजगी कड़ाई से जतानी होगी, अपने हितों को आगे रखना होगा और ट्रंप प्रशासन के किसी भी दबाव से बाहर रहना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में भारत के लिए अवसरों की कमी नहीं है।

विश्लेषण
प्रो. नीलम महाजन सिंह

बदलाव की उम्मीद में 'भ्रष्ट सत्ता' का अंत

> यूं तो फ्रीबिज के हमाम में सब खोटे हैं, लेकिन ईमानदार व भ्रष्टाचारमुक्त शासन का वादा करके राजनीति का आगाज करने वालों ने अपनी शुरुआत ही मुफ्त के वादों से की थी, यह सरासर राजनीतिक बेईमानी थी। देश की इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसे सत्ता पाने के लिए लंबे समय तक सड़कों पर संघर्ष नही करना पड़ा, आंदोलन के स्टेज से सीधे दिल्ली के तख्त तक पहुंची। अनुभवहीनता शासन में दिखी। आप ने सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता चुना, कौन सुप्रीम, इसे तय करने में ही वक्त गंवाया, राष्ट्रीय राजधानी को और बेहतर बनाने के लिए फोकस होकर प्रयास नहीं किया। जनहित की राजनीति की उम्मीद बंध गई थी। बारह साल में यह उम्मीद टूट गई।

लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक और सकारात्मक है। इससे राजनीति की जीवंतता का एहसास होता है। निरंकुशता का खतरा टलता है। हर राज्य में, देश में, एक अंतराल पर सत्ता बदलती रहनी चाहिए। दिल्ली इस बदलाव की बड़ी गवाह है। जब से सत्ता का केंद्र दिल्ली बनी, तब से इसने न जाने कितने बदलाव देखे। हालिया बदलाव ने भी संदेश दिया है कि सत्ता जनता ही तय करती है, उसे बरगलाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की करारी शिकस्त किसी भी दल के लिए बड़ा सबक है कि जनता झूठ, फरेब, कुतर्क, बड़बोलेपन, निम्नस्तर की भाषा, फ्रीबिज की हफीम पसंद नहीं करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव से पहले रेवड़ियों की घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। यूं तो फ्रीबिज के हमाम में सब खोटे हैं, लेकिन ईमानदार व भ्रष्टाचारमुक्त शासन का वादा करके राजनीति का आगाज करने वालों ने अपनी शुरुआत ही मुफ्त के वादों से की थी, यह सरासर राजनीतिक बेईमानी थी। देश की इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसे सत्ता पाने के लिए लंबे समय तक सड़कों पर संघर्ष नही करना पड़ा, आंदोलन के स्टेज से सीधे दिल्ली के तख्त तक पहुंची। अनुभवहीनता शासन में दिखी। आप ने सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता चुना, कौन सुप्रीम, इसे तय करने में ही वक्त गंवाया, राष्ट्रीय राजधानी को और बेहतर बनाने के लिए फोकस होकर प्रयास नहीं किया। यूं तो देश में सभी दलों की हालत एक सी है, लेकिन अण्णा हजारे के आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी से जनता को ईमानदार, भ्रष्टाचारमुक्त जनहित की राजनीति की उम्मीद बंध गई थी। बारह साल में यह उम्मीद टूट गई। अब शायद ही जनता कभी अण्णा जैसा व्यापक आंदोलन भविष्य में देखे और किसी भी नई किस्म की राजनीति के वादे पर विश्वास करे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार उसकी राजनीतिक यात्रा की असल शुरुआत होगी, लोग देखेंगे कि आप विपक्ष की भूमिका कैसे निभाती है, कितनी संयमित रहती है, कितनी रचनात्मक रहती है, जनता के मुद्दों से कितना सरोकार रखती है। दल से जुड़े लोग कितने समय तक टिके रहते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल विपक्ष में रहकर राजनेता बन पाते हैं या नहीं? आगे की राजनीति पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का भविष्य निर्भर करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बने मोमेंटम का राजनीतिक लाभ लेना बुद्धिमत्ता थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर कर सत्ता गंवाना राजनीतिक आत्महत्या की तरह है। बदलाव की राजनीति सत्ता की राजनीति में परिवर्तित हो गई। आम आदमी पार्टी से देश के करोड़ों प्रगतिशील लोगों को उम्मीदें थीं। यह उम्मीद ही थी कि लोगों ने पार्टी बनाने में अपनी गाढ़ी कमाई से करोड़ों दान कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा में उन सभी उम्मीदों को तोड़ दिया। मास की राजनीति करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई पैमाना नहीं होता कि जनता आपकी पार्टी या आपके बारे में क्या राय रख रही है, इसलिए अधिकांश नेता व दल अनाप शनाप हरकतें करते रहते हैं। कभी चांद तो कभी चंदा मामा की बात करने लगते हैं। जनता को हल्के में लेने लगते हैं, उनकी असल जरूरतों को कम करके आंकने लगते हैं और रेवड़ियों पर भरोसा

करने लगते हैं। आम आदमी पार्टी को सुशासन से अधिक भरोसा मुफ्त पानी व बिजली पर था, जनता को कभी कुछ मुफ्त में नहीं चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। राजनीति जनता को सक्षम व समर्थ बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि उसे परजीवी-पराश्रित बनाने के लिए। नए तरह की राजनीति का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी भी सत्ता पाने के लिए व बने रहने के लिए दूसरे दलों की तरह ही झूठ व तिकड़म की राजनीति करते दिखी। एक 'सफलर मैन से शीशमहल की यात्रा' में तब्दील हुई अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आखिरकार उसी जनता ने आईना दिखा दिया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी को 'आप-दा' मुक्त करने का आह्वान किया था। जनता ने पीएम मोदी व भाजपा पर भरोसा किया। दिल्ली को 'आप-दा' मुक्त कर दिया। आम आदमी पार्टी ध्वस्त हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की आंधी में दिल्ली को कूड़ा दान बनाने वाली झाड़ू तार-तार होकर तिनके की तरह बिखर गई। खुद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। 48 सीटों में विजय पाकर, नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत हुई है। आप को 22 सीटों पर ही जीत प्राप्त हुई है। कांग्रेस को एकबार फिर शून्य से ही गुजारा करना पड़ा। अब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई गारंटीयों के वादों को दिल्ली की भाजपा सरकार को लागू करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्लीवासियों ने 61% वोट डाले हैं। सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए थे। पैसे, शराब व सामान आदि बांटने से लेकर एक-दूसरे को धमकियां व गाली-गलौज आम बात रही। सार्वजनिक जीवन में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लगभग सभी सर्वेक्षणों ने पोल विश्लेषण के परिणाम, भाजपा के हक में दिए थे। दिल्ली के लोगों के लिए मुख्य मुद्दे, भारत के अन्य राज्यों से अलग हैं। पीएम ने सुशासन, विकास का मॉडल देने का वादा किया है। भाजपा की जीत के कुछ विशेष कारण हैं। दिल्ली के नागरिकों को चार चीजों की जरूरत है, यानी पीने का साफ पानी, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त वातावरण, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मध्यम वर्ग को केवल मुफ्त शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 'उचित फीस' पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी जरूरी है। दिल्ली में हर कोई 'बीपीएल कार्ड धारक' नहीं है। दिल्ली वासियों के लिए किफायती बिजली के बिल जरूरी हैं। हम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक 50% छूट की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लाभ का लक्ष्य मध्यम वर्ग होना चाहिए। कांग्रेस अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठित नहीं कर पाई व उसका प्रचार लक्ष्यहीन रहा। कांग्रेस अपने अभियान की रणनीति नहीं बना पाई। आप के बहुत से कार्यकर्ताओं ने उत्साह से काम नहीं किया। भाजपा का ध्यान आम आदमी तक पहुंचने पर केंद्रित था। अब डबल इंजन की सरकार बन रही है। बड़ी बात है कि भाजपा अब तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। केन्द्र सरकार व भाजपा की दिल्ली सरकार एकजुट होकर दिल्ली की जनता को सभी प्रकार से समृद्ध करेंगी। घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को कार्यान्वित कर, दिल्ली की जनता की सेवा करने से, राजधानी दिल्ली को अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की ओर अग्रसर रहना होगा। 'जिन हाथों में शक्ति भरी है राजतिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सिर उतार लेने की', पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने लोक सभा में अपने भाषण में यही परिस्थिति का आकलन किया था।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, विधायिका, दूरदर्शन सलाहकार व पत्रपत्रिकाएं हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

दो टूक
रोहित कौशिक

कॉमेडी में अश्लीलता का तड़का अनुचित

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं। रणवीर ने माता-पिता व परिवार को लेकर अश्लील कमेंट किया था। इस कमेंट पर काफी विवाद हो रहा है। यूट्यूबर रणवीर, कॉमेडियन समय रैना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा और शो के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। रणवीर अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में फिल्मी हस्तियों और चर्चित हस्तियों से चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं। अब यूट्यूब ने वह वीडियो हटा दिया है। रणवीर ने अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली है लेकिन रणवीर पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रणवीर ने शो में शामिल प्रतिभागी से पूछा था कि क्या आप अपने माता-पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या एक बार शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए रोकेंगे। कॉमेडी के नाम पर इस तरह के प्रश्न पूछना क्या वास्तव में जरूरी है। सवाल यह है कि ऐसे प्रश्नों से क्या हासिल हो जाएगा ? क्या माता- पिता के यौन सम्बन्धों को मजाक का विषय बनाया जा सकता हैं ? हालांकि पहले से ही यौन सम्बन्धों पर मजाक होते रहे हैं। पहले छिपकर यौन सम्बन्धों पर मजाक होते थे लेकिन अब यौन सम्बन्धों पर मजाक करना एक फैशन मान लिया गया है। सेक्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सभी जीव-जंतु इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना जीवन चक्र चलाते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को आधार के तौर पर देखा जाना चाहिए? एक प्राकृतिक प्रक्रिया को मजाक बनाकर कहीं हम अपनी कुंठा तो नहीं दिखाते हैं ? इसी कुंठा के कारण हम कई नई चीजों को जन्म दे देते हैं। दरअसल यूट्यूब पर घटिया व्यंग्य और घटिया मजाक के अनेक शो चल रहे हैं। सच्चे अर्थों में तो इन्हें व्यंग्य भी नहीं कहा जा सकता। द्विअर्थी संवाद और सेक्स से सम्बंधित बातों का छौंक लगाकर इन्हें व्यंग्य और हास्य का नाम दिया जाता है। शर्मनाक तो यह है कि ऐसे शो को पसंद करने वाले लोग भी लाखों में हैं। इसका अर्थ यह है कि यह समाज ही ऐसे शो को पसंद करता है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पसंद करने के कारण ही ये शो चल भी रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर शर्मनाक और घटिया हरकतों की इजाजत दी जा सकती है? शायद नहीं। इस दौर में सिर्फ एक रणवीर नहीं बल्कि सैकड़ों रणवीर इलाहाबादिया पैदा हो गए हैं। टैलेंट के नाम पर फूहड़ता को बढ़ावा दिया जा रहा है। टैलेंट के नाम पर गालियां देना आम हो गया है। जैसे इसे इस जमाने का फैशन मान लिया गया हो। शायद यह कभी सोचा भी नहीं गया होगा कि एक दिन गालियां देना भी फैशन हो जाएगा। सवाल यह है कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग घटिया हरकतों और घटिया टिप्पणियों को अपना अधिकार कैसे समझ लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या कुछ भी बोल देना हमारा अधिकार होना चाहिए ? हमें अपने अधिकार तो बहुत जल्दी याद आने लगते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जाहिर है कि यदि हम अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखें तो ऐसी हरकतें सामने आ ही नहीं सकती हैं। दरअसल इस दौर में जिस तरह से नैतिकता को फालतू चीज मान लिया है उससे स्थिति बद से बदतर ही हुई है। यह ठीक है कि हर इंसान के लिए नैतिकता की परिभाषा अलग-अलग हो सकती है लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर इतना विवेक तो होना ही चाहिए कि हम स्वयं अपनी एक सीमा रेखा खींच सकें। इस दौर में बोलड दिखने की ऐसी प्रतिस्पर्धा हो रही है कि जिसमें हमारे आधारभूत संस्कार ही पीछे हो गए हैं। संस्कार नाम की चीज को पिछड़ा हुआ माना जाने लगा है। तभी तो एक शो में अपने माता-पिता के सेक्स को भी अपने मनोरंजन की बात बना दिया जाता है। क्या रणवीर के माता-पिता ने उसे यही संस्कार दिए होंगे। क्या इस दौर में माता-पिता की भी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे अपने बच्चों को संस्कारों का भी पाठ पढ़ाएं और इसे प्रगतिशीलता के मार्ग में अवरोधक न माना जाए। सवाल उठता है कि क्या रणवीर के माता-पिता उसकी इस बोल्ड छवि को स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए इस दौर में भी संस्कारों को पुरानी चीज नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह के शो में अपना स्तर इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि सारी शर्म ही खत्म हो जाए। मर्यादा में रहकर ही संवाद किया जाना चाहिए। ऐसे संवादों में मानवीय रिश्तों की गरिमा का ध्यान भी रखा जाना चाहिए।

(लेखक उत्तरांचल पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शांति से सभी दुखों को खत्म किया जा सकता है

संकलित
दर्शन

हम स्वयं शांति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु या स्थान शांति दे सकता है, यह एक काल्पनिक विचार है। हम स्वयं शांति से रह सकते हैं और दूसरों को भी शांतिपूर्वक रख सकते हैं। शांति एक मानवीय गुण ही है ही, लेकिन यह आत्मिक शक्ति है। शांति सभी सुखों की मूल है। इससे सभी वैभव एवं ऐश्वर्य की पूर्ति संभव है। शांति द्वारा सभी दुखों का शमन किया जा सकता है। इससे हर रोग का निदान होता है। शांति का माध्यम सभी समस्याओं का समाधान तैयार करता है। शांति ही देश का निर्माण करती है, वहीं अशांति से देश का पतन आरंभ होता है। शांति और अशांति के बीच समाज, समुदाय, वर्ग, कौम, जाति और संस्थाएं गतिहीन हो जाती हैं। देश की उन्नति, विकास और पुनर्निर्माण के लिए शांति का वातावरण अनिवार्य है। शांति एक शब्द मात्र नहीं है। शांति को मन मंदिर में बसाने वाले लोग देव तुल्य होते हैं। इसलिए स्वयं भी शांति के प्रहरी बनिए और दूसरों को भी शांति दूत बनाइए। यही संसार के मंगल का भेद है। शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। परिवार में शांति एक वट वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया में आनंद की अनुभूति पाई जा सकती है। अशांति कालांतर में अग्नि के समान जीवन के हर अंग को भस्म कर देती है। मानवता का मूल इसी शांति के गर्भ में स्थिर है। यदि जीवन को सुख और वैभव से संपन्न करना हो तो निश्चित ही शांति की पूजा करनी होगी। देश में जन सामान्य को शांति के सूत्र अपनाने चाहिए।

तुलसीदास जी द्वारा विप्रचंद ब्राह्मण पर कृपा

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गयी और उस हत्या के प्रायश्चित के लिये वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था: राम राम ! मै हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिये। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्टदेव का आर्तसुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपनी पंक्ति में बैठकर प्रसाद खिलाया जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितो ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना वे ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया? गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिये। भगवन्नाम के प्रताप से ही वह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको कैसे होगा विश्वास यह उपाय कहिये? इसपर ब्राह्मणों ने कहा: यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा लें तो हम लोग इसे अपनी जाति, पंगति में ले सकते हैं अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे जहाँ शर्त रखी गयी थी। श्री गोस्वामी जी ने नन्दीश्वर से कहा: हे नंदीश्वर ! यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिये। नन्दीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया।

अंतर्मन

आज की पाती

स्टार्टअप और कौशल विकास बेरोजगारी का हल

आज से लगभग आठ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने स्टार्टअप योजना को अमल में लाया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक व्यवस्था को दीर्घ, यानी उद्योगों को और मजबूत बनाना है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ-साथ महिला उद्यमियों को सहिकाही भी मिलती है। सरकार इस योजना के अधीन उद्योगों को टैक्स में भी छूट देती है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। देश के उद्योग जितने मजबूत होंगे उतने ही रोजगार उपलब्ध होंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी।

- पंकज मेहता, रामतरी

करंट अफेयर

मोदी का ट्रंप को 'मागा' की तर्ज पर 'मीगा' का मंत्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चर्चित कथन 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) की तर्ज पर 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' (मीगा) का मंत्र दिया और कहा कि ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर समृद्धि के लिए ''मेगा'' साझेदारी बनाते हैं तथा द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त सम्मेलन के दौरान कीं। दोनों नेताओं ने यहां रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने को लेकर मुख्य रूप से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदर्श वाक्य, 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (अमेरिका को फिर से महान बनाएं) यानी 'मागा' से सब परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की राह पर 'विकसित भारत 2047' के संकल्प के साथ तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''अगर मैं अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' (भारत को फिर से महान बनाएं) यानी 'मीगा' है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं, यानी मागा और मीगा मिलकर समृद्धि के लिए ''मेगा'' साझेदारी बनती है तथा यह ''मेगा'' भावना हमारे लक्ष्यों को नया आकार और दायरा प्रदान करती है।''

ऑफ बीट

क्या एआई हमें मंदबुद्धि बना रहा है? शोध में आशंका

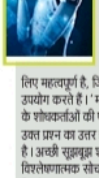

हममें से ज्यादातर लोग एक हद तक ही सोच पाते हैं। बिना कलम और वागज या कैल्कुलेटर के 16,951 को 67 से भाग देने की कोशिश करें। पिछले हफ्ते बनाई गई सूची या अपने फोन पर उपलब्ध फेहरिस्त के बिना हफ्ते भर की खरीदारी करने की कोशिश करें। अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इन उपकरणों पर निर्भर रहकर हम खुद को अधिक बुद्धिमान बना रहे हैं या मूर्ख? हम अपनी कार्यकुशलता बढ़ने के बावजूद क्या एक प्रजाति के रूप में अज्ञानता के और करीब जाने लगे हैं? यह प्रश्न विशेष रूप से ओपनएआई कंपनी के स्वामित्व वाला एक एआई चैटबॉट 'चैटजीपीटी' जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के संबंध में विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका प्रत्येक सप्ताह 30 करोड़ लोग लेखन के समय उपयोग करते हैं। 'माइक्रोसॉफ्ट' और अमेरिका के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा हाल ही में लिखे गए एक शोधपत्र के अनुसार, उत्तर प्रश्न का उत्तर हां हो सकता है। लेकिन बात इससे कहीं आगे पहुंच चुकी है। अच्छी सूझबूझ शोधकर्ताओं ने मूल्यांकन किया कि उपयोगकर्ता अपनी विश्लेषणात्मक सोच पर एआई के प्रभाव को कैसे समझते हैं। आम तौर पर, विश्लेषणात्मक सोच का संबंध अच्छी तरह से सोचने से होता है।

ट्रेंड

एक्सप्रेस-वे का मुआयना

उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान आज 8000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे लखनऊ-बलरामपुर बीआईसी एक्सप्रेस-वे का सर्वेक्षण आई रोहित अवस्थी व टीम मौजूदे के साथ मुआयना किया।
-नितिन गडकरी, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री

पावन तीर्थ स्नान

144 साल बाद हो रहे तीर्थराज प्रयाग के महाकुम्भ के भव्य आयोजन की व्यवस्था सुरक्षाकर्मी योजी आदित्यनाथ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। एक हिंदू के नाते मैं भी उसमें पावन तीर्थ स्नान करने आया हूँ।
-देवेन्द्र फडनवीस, सीएम, महाराष्ट्र

विनम्र श्रद्धांजलि

पुलवामा आतंकी हमले के शहीद हमारे वीर जवानों को शत-शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत उनका सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा।
-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

महाकुम्भ में आशीर्वाद

पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकर्मों के नाश और इस जीवन में सच्ची सुखित की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। कुम्भ मेला धारा, शक्ति और दिव्यता सनातनी के बीच सत्यों के आदर्शों को प्रतिष्ठित करता है। महा कुम्भ में आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर पाकर अत्यन्त गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
-विवेक ओबेराय, अभिनेता

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

कल्पमेधा

सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं, जहां वे जाना चाहते हैं। महान नेता वहां ले जाते हैं, जहां लोग जाना नहीं चाहते, फिर भी जाने की आशा रखते हैं।

- रोजलिन कार्टर

सहयोग का संबंध

प्रधानमंत्री की इस बार की अमेरिका यात्रा कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है। जबसे डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, वे कई मामलों में काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। खासकर प्रवासियों और व्यापार संबंधों को लेकर। पदभार संभालने के साथ ही जिस तरह उन्होंने भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों की पहली खेप बेड़ियों में जकड़ कर वापस भेज दी, उससे कई तरह की चिंताएं जताई जाने लगी थीं। हालांकि प्रधानमंत्री इस बार राजकीय यात्रा पर नहीं गए थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ पूरी गरमजोशी दिखाई। इस मुलाकात में कई तरह के भ्रम भी दूर हुए। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ट्रंप जिस तरह कुछ देशों के साथ व्यापार पर अतिरिक्त शुल्क थोप रहे हैं और अमेरिकी हितों को तरजीह दे रहे हैं, उसमें भारत के साथ भी व्यापार प्रभावित हो सकता है। मगर ट्रंप ने इस कयास को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो देश जितना शुल्क लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा, न कम न ज्यादा। इसका साथ ही उन्होंने भारत सरकार के इस फैसले की तारीफ की कि उसने अनावश्यक शुल्क हटाना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय बाजार में अमेरिका की पहुंच कुछ और बढ़ेगी।

दोनों देशों ने प्रतिरक्षा, तेल-गैस, नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग और प्रतिरक्षा खरीद मामलों ने महत्त्वपूर्ण समझौते किए। अमेरिका भारत को एफ-35 युद्धक विमान बेचने का इच्छुक है। भारत ने इस पर सहमति दे दी है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, पर भारत मानता है कि इस विमान की खरीद से उसकी सामरिक शक्ति बढ़ेगी। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि वह भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और हर सहयोग उपलब्ध कराएगा। वह भारत की तेल और गैस संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। दरअसल, भारत की चिंता कच्चे तेल की अधिक रहती है। रूस-यूक्रेन और इजराइल-फिलस्तीन संघर्ष के बीच आपूर्ति शृंखला बाधित हुई, तो कच्चे तेल के मामले में भारत ने रूस से सहयोग लेना शुरू कर दिया। अब अमेरिका से इस क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, तो निश्चय ही उस पर दबाव कुछ कम होगा।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका ने सकारात्मक रुख दिखाया है, उससे दोनों के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। अवैध आप्रवासन को लेकर अमेरिका की चिंता पर भारत ने कहा कि वह अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है, बेशक उन्हें ससम्मान वापस भेजा जाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उन मानव तस्करों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने का वादा किया, जो भारत से लोगों को बरगला या बहला कर दूसरे देशों में ले जाते हैं। निश्चय ही यह अमेरिका के फैसले के प्रति सकारात्मक रुख है। सबसे अधिक चिंता व्यापार पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंता जताई जा रही थी, मगर उस चिंता को दूर करते हुए दोनों देशों ने भरोसा दिलाया है कि वे 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करेंगे। इससे न केवल दोनों देशों का व्यापार घाटा कम होगा, बल्कि दोनों का बाजार कुछ और विस्तृत होगा। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में जिस गतिरोध की आशंका जताई जा रही थी, वह समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा की यह बड़ी उपलब्धि है।

वार्ता की नींव

लंबे समय से जातीय हिंसा के दौर से गुजर रहे मणिपुर में अंततः राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। शायद केंद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पिछले डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उन पर दबाव तब बना, जब राजग की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पर नैतिक दबाव बना, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मगर यह दुखद है कि तब तक मणिपुर के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को गहरी क्षति पहुंच चुकी थी। इस्तीफे के बाद बीरेन सिंह के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने से भी कई विधायक नाराज थे। वहीं नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए सहमति न बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर यह अनुभव रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके केंद्र को मणिपुर में पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार का गठन करना चाहिए। वैसे भी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पर्याप्त बचा है। वह अभी भंग नहीं की गई है।

पिछले ग्यारह साल में यह पहली बार है जब केंद्र की राजग सरकार ने भाजपा शासित पूर्ण बहुमत वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। मणिपुर में अभी विधानसभा फिलहाल निलंबित है। यानी अब राज्यपाल वहां सभी प्रशासनिक कामकाज संभालेंगे। कोई दो मत नहीं कि इससे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी। सवाल है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? बीरेन सिंह पर इससे पहले पक्षपात के कई आरोप कुकी संगठनों ने लगाए थे। मगर उनकी एक न सुनी गई। ऐसा कहा जा रहा कि इन संगठनों ने शांति वार्ता के लिए मुख्यमंत्री को हटाने की शर्त रखी थी। इस बीच भाजपा के विधायक भी उनसे नाराज हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा कर इसी असंतोष को थामने की कोशिश की है। वहीं बीरेन सिंह के हटने से राज्य में शांति बहाली के लिए वार्ता की उम्मीद बढ़ गई हैं।

हवाई दुर्घटनाओं का बढ़ता दायरा

दुर्घटनाओं से दुनिया भर के विमानन उद्योग और इसमें कार्यरत कर्मचारियों की दायित्वहीनता सामने आती है। ऐसी स्थिति में देश-दुनिया की विमानन सेवाओं और उनके प्रबंधन के प्रति कई शंकाएं उभरती हैं।

विकेश कुमार बडोला

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के समीप पिछले महीने हवाई अड्डे पर उतर रहे यात्री विमान से एक हेलिकाप्टर के टकराने के कारण विमान में सवार सभी चौंसठ लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद विमान दो-तीन टुकड़ों में टूट कर पास ही पोटोमैक नदी में जा गिरा। नदी में बर्फीला पानी जमा था। टक्कर के बाद अगर कुछ यात्रियों के जीवित बचने की संभावना रही भी होगी, तो ठंडे बर्फीले पानी में उनके डूबने के कारण खत्म हो गई। अमेरिका के विगत पचीस वर्ष के इतिहास में यह सबसे भीषण विमान दुर्घटना है। कंसास के विचिटा से आ रहे विमान के उतरने का समय पूर्वनिर्धारित था। उस समय विमान में अमेरिकी और रूसी नागरिक सवार थे। अमेरिकी एअरलाइंस के मुख्य कार्यकारी के अनुसार उन्हें कोई जानकारी नहीं कि सैन्य हेलिकाप्टर विमान के मार्ग में क्यों आया।

पिछले एक माह के दौरान दुनिया में यह तीसरी विमान दुर्घटना है। दुर्घटनाओं से दुनिया भर के विमानन उद्योग और इसमें कार्यरत कर्मचारियों की दायित्वहीनता सामने आती है। ऐसी स्थिति में देश-दुनिया के विमानन सेवाओं और उनके प्रबंधन के प्रति कई शंकाएं उभरती हैं। अमेरिका में अभी की और एक माह पूर्व दक्षिण कोरिया की, दोनों घटनाएं हवाई अड्डे पर विमानों के उतरने के दौरान घटी हैं। ऐसी घटनाएं अप्रत्याशित हैं। इन परिस्थितियों में दो ही आशंकाएं हो सकती हैं। या तो इन हादसों के पीछे कोई साजिश थी या फिर विमानों के उतरने के दौरान विमान के संबंधित कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया।

इससे पहले 29 दिसंबर, 2024 को दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे। मुआन हवाई अड्डे पर उतरते हुए उसमें आग लगी और देखते ही देखते 179 लोगों की मौत हो गई। उस घटना के चार दिन पहले 25 दिसंबर को अजरबैजान एअरलाइंस का एक विमान कजाखस्तान के अक्ती हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में सवार 69 में से 38 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। इसी दौरान कनाडा का एक विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना के प्रत्यक्ष चलचित्र, लोगों के शव और क्षतिग्रस्त विमान के अंश उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा सकती है। आज तक ऐसे विमान और इनके यात्रियों का कुछ पता नहीं चल सका है। यह आधुनिकता, प्रगति और विज्ञान पर सवाल है।

अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 28 जून, 1856 से लेकर के 14 जुलाई, 1897 तक कुल पांच वायु वाहन (यान या हाइड्रोजन गुब्बारा) दुर्घटनाग्रस्त या अदृश्य हुए थे। इसके बाद वर्ष 1901 से 1919 तक कुल 13 वाहनों की दुर्घटना हुई। इनमें ग्यारह लोग रहस्यमय ढंग से अदृश्य हुए। इसी सदी में 1920 और 1939 के बीच हुई 49 विमान दुर्घटनाओं में मरे ज्यादातर का पता नहीं चल पाया था। जैसे-जैसे दुनिया में वैज्ञानिक, औद्योगिक, यांत्रिक और प्रौद्योगिकी में उन्नति होती रही, उसी गति से वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होते या अदृश्य होते रहे। वर्ष 1940 और 1959 की अवधि में 75 विमान आकाश में गायब हो गए। वर्ष 2000 से 2019 के बीच कुल 18 घटनाओं में 295 लोगों की जानें गईं। इस अवधि में आठ मार्च 2014 को मलेशिया एअरलाइंस के बोइंग 777-200 ईआर की दुर्घटना भी शामिल है। वर्ष 2019 तक यह सबसे बड़ी विमान दुर्घटना थी। इसमें 239 लोग सवार थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला।

> **देश-दुनिया की विमानन कंपनियों और विमान तथा विमान से संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों को व्यापक स्तर पर यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वे रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले विमानों का प्रामाणिक कारण खोजें। विमान हादसों के कारण का पता लगाएं। ऐसे कारणों पर स्थायी रोक लगाने के उद्देश्य से वैमानिकी अभियंत्रण से लेकर विमानन प्रबंधन पर पुनर्विचार हो। इसके लिए विमानन उद्योग की आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधि का दैनिक रख-रखाव और निगरानी तो आवश्यक है ही, साथ ही विमानों के कल-पुर्जे बनाने वाली देशी-विदेशी कंपनियों के लिए भी कठोर नियम-कानून बनें ताकि विमानों के कल-पुर्जे पूरी तरह त्रुटिहीन, बाधारहित एवं हर प्राकृतिक व कृत्रिम समस्या से सुरक्षित हों।**

इस घटना के बारे में ये प्रामाणिक तथ्य है कि यह विमान आस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। हालांकि घटना के बहुत दिनों बाद विमान के कुछ अवशेष अवश्य प्राप्त हुए थे, लेकिन विमान अब भी अदृश्य है। इसके बाद दो अप्रैल 2022 को फ्रांस से उड़ा एक विमान अत्यधिक घने बादलों में गायब हो गया। उसमें दो लोग सवार थे।

जहां तक दो बड़ी विमान दुर्घटनाओं की बात है, तो उनमें मलेशियाई बोइंग और दक्षिण कोरिया के यात्री विमान के साथ हुई घटनाएं सबसे बड़ी और भयावह हैं। इनमें क्रमशः 239 और 179 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। पूंजीपतियों के स्वामित्व वाले अनेक निजी विमान भी यहां-वहां समुद्र के ऊपर, किसी दुर्गम पहाड़ या सघन वनों के ऊपर आकाश में रहस्यमय परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। भारतीय और विदेशी वायुसेनाओं के भी कई विमान आसमान में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। यही नहीं आकाश में समुद्र से ऊपर एक निश्चित दूरी पर उड़ने वाले अनेक विमान अत्यंत रहस्यमयी परिस्थितियों में अदृश्य हो चुके हैं। ऐसे रहस्यों का डेढ़-दो सदियां बीतने के बाद भी आज तक उद्घाटन नहीं हो सका है। आधुनिक एवं नवीनतम आधुनिक उपकरणों के साथ वर्षों तक ऐसे गायब विमानों को ढूंढने के अनेक अभियान भी चलाए गए। अनेक देशों ने पारस्परिक खोज अभियान भी चलाए, मगर अंततः सब विफल रहे। आज जब लगभग पूरा विश्व आकाश-मार्ग से परिवहन का अग्रणी माध्यम बना हुआ है, तो विमानों के गायब होने और दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाएं आकाशीय परिवहन के प्रति शंकाएं बढ़ाती हैं। इन परिस्थितियों में विमान यात्रा दिनोंदिन असुरक्षित होती जा रही है।

देश-दुनिया की विमानन कंपनियों और विमान एवं विमान से संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों को व्यापक स्तर पर यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वे रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले विमानों का प्रामाणिक कारण खोजें। विमान हादसों के कारण का पता लगाएं। ऐसे कारणों पर स्थायी रोक लगाने के उद्देश्य से वैमानिकी अभियंत्रण से लेकर विमानन प्रबंधन पर पुनर्विचार हो। इसके लिए विमानन उद्योग की आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधि का दैनिक रख-रखाव और निगरानी तो आवश्यक है ही, साथ ही विमानों के कल-पुर्जे बनाने वाली देशी-विदेशी कंपनियों के लिए भी कठोर नियम-कानून बनें ताकि विमानों के कल-पुर्जे पूरी तरह त्रुटिहीन, बाधारहित एवं हर प्राकृतिक और कृत्रिम समस्या से सुरक्षित हों। विमानन सामग्री के विनिर्माण में लगी हुई कंपनियों के कर्मचारियों और प्रबंधन पर वैमानिकी परिवहन को सुरक्षित बनाए रखने का सबसे बड़ा दायित्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारों और उड्डयन मंत्रालयों को विमान सामग्री के विनिर्माण में जुटी कंपनियों के साथ संवाद और कार्य मूल्यांकन को नियमित बनाए रखना होगा।

विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने और दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों की मौत दुखद है। इससे भी अधिक कष्ट तब होता है, जब पता चलता है कि विमान सहित उसमें सवार कई सौ लोग रहस्यमय ढंग से गायब हैं। विडंबना यह कि विमान जहां से गायब हुआ था, उस भूगोल बिंदु से लेकर हर संभव दिशा में वर्षों तक देशी-विदेशी सहयोग से आधुनिक साजो-सामान के साथ खोज अभियान चलाने के बाद भी न तो विमान का और न ही उसमें सवार यात्रियों का पता चल पाता है। वैमानिकी परिवहन में यह बहुत प्रतिकूल स्थिति है। इस पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। सुरक्षित विमान यात्रा दुनिया की हर सरकार का दायित्व है। विमान

बिखरता चूल्हा, सिमटता आंगन

अशोक कुमार

भारतीय सामाजिक परिवेश का वास्तविक स्वरूप एवं संरचना गांवों में रचता-बसता रहा है। संयुक्त परिवार को ग्रामीण संस्कृति के पारंपरिक स्वरूप में देखा-समझा जाता था। उसमें परिवार रिश्तों की गर्माहट के साथ मजबूती से एक सूत्र में बंधा रहता था। चूंकि देश की आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, इसलिए मानव जीवन का पहिया बहुत हद तक आपसी दुख-सुख के चक्र से आत्मिक समन्वय लिए गतिमान है। समाजशास्त्रियों का भी कथन है कि परंपरागत रूप से संयुक्त परिवारों की आपसी समझ के कारण वैमनस्य की गंभीर समस्या का अनुभव नहीं किया जाता था। घर में बच्चे अपने माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची और दादा-दादी से बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे। पूरे परिवार को समेट कर, सहेज कर चलाने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की हुआ करती थी। यों यह दायित्व आज भी वही निभा रहे हैं।

संयुक्त परिवार के दौर में घर के सदस्यों के काम अलग-अलग बंटे होते थे। घर के सभी सदस्यों का एक साथ भोजन पकना और खाना बिल्कुल सामान्य ढंग से संचालित हुआ करता था। सभी एक साथ भोजन करते थे। इससे संतुष्टि मिलती थी और आपस में स्नेह बढ़ता था। इसी दौरान दिन भर के अपने अनुभव और दुख-सुख भी साझा हो जाया करते थे। सार यह कि इससे परिवार में एका के साथ उसकी शक्ति भी बनी रहती थी। तब परिवार चुनौतियों का सामना मिल कर कर लेता था।

औद्योगिक क्रांति के पहले भारतीय परिवारों का स्वरूप संयुक्त था, लेकिन उद्योगीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और पश्चिमी जीवन दर्शन के प्रभाव से परिवारों की संरचना में तेजी से बदलाव होने लगे। इन परिवर्तनों ने न सिर्फ परिवार के ढांचे को असंतुलित कर दिया, बल्कि सदस्यों के निजी पारस्परिक संबंधों, मेल-मिलाप की प्रक्रिया, परिवार के अनुशासन और व्यवहार प्रणालियों को भंग करने के लिए भी सर्वाधिक रूप में उत्तरदायी हुए। परिवार एक छोटी इकाई के रूप में नजर आने लगे। चूल्हे अलग होने लगे, खेत बंटने लगे और आंगन के आकार सिमटने लगे। एकल परिवार की धारणा में परिवारों के बीच निजी स्वतंत्रता की चाह ने अपनी जगह बना ली और आपसी आनंद की लहरों में डूबने की नौबत आ गई।

काल के प्रवाह में आज एक चूल्हे ने छह चूल्हे को आकार भले दे दिया, लेकिन कभी एक साथ बैठ कर सीमित व्यंजन के भोजन से जो संतुष्टि मिलती थी, आज व्यंजनों की अधिकता ने भी उसके पहले के स्वाद को कम जरूर कर दिया है। घर के सदस्यों के लिए पके भोजन के अंश से ही कभी-कभी पड़ोसी या खुद के घर में अचानक आए अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर पलायन की विवशता ने भी हमारे घर-आंगन के आकार और रौनक को कम कर रखा है। अनेक घरों में तो ताले लग गए, जो साल-दो साल में ही खुलते हैं। बंद ताले की चाबियां अब गुम हो रही हैं, क्योंकि गृह स्वामी यह तय नहीं कर पाते कि बंद घरों में उन्हें कब लौटना है। जिस आंगन में हमेशा चहल-पहल हुआ करती थी, खासकर किसी समारोह में मौसी, बुआ की उपस्थिति हर नेग और विधान को जीवंत बनाए रखती थीं, वहीं गांवों से विस्थापित परिवारों के विवाह समारोह अब नगर के होटलों, विवाह भवनों, रिजार्ट और सामुदायिक भवनों में आयोजित होने से उनके बंद घर-आंगन में अब गौरैया भी दाना चुगने नहीं आती।

भाइयों के बीच बंटवारे ने घर के कुएं को भी विभक्त कर दिया, साथ ही खेत भी टुकड़ों में बंट गए। इससे खेतों के क्षेत्रफल में भी कमी आ गई। इन हालात ने जब समाज की सबसे लघु इकाई घर-आंगन की परंपरागत शक्ति का क्षरण किया है, तो स्वाभाविक रूप में इसके प्रभाव ने पूरे गांव के विरासतीय संपदा में भी सेंधमारी कर दी है। यह स्थिति भारतीय परिवारों के लिए आज एक विषम समस्या है, जिसकी जड़ में परिवार के लोगों के व्यवहार में असंतुलन के कारण कलह, संघर्ष, अविश्वास और अलगाव का मिश्रण है। आज परिवार में व्यक्ति का जीवन जब व्यस्तता, भौतिक सुख और आत्मकेंद्रित होने की ओर उन्मुख है, तो पीढ़ी की परंपराएं और मर्यादाएं उसके गले नहीं उतर सकतीं।

दुनिया मेरे आगे

> **परिवार के सिमटते आंगन का एक मुख्य कारण आर्थिक तनाव भी है, क्योंकि महंगाई की मार के बावजूद आवश्यकता की सूची दिन-प्रतिदिन लंबी हो रही है। यह पश्चिम के व्यक्तिवादी तात्कालिक सुखद चिंतन का ही परिणाम है कि आज बीमारी, बेरोजगारी, कुपोषण, बुढ़ापा या अन्य किसी संकट की स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार में अकेला और असहाय महसूस करने लगा है।**

दैनिक जीवन के आचरण के प्रतिबिंब साथी हैं कि अब परिवार एक संस्था की मान्यता से अपने को दूर कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, यहां तक कि जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'आउटसोर्स' पर निर्भर हो गए हैं। परिवार के सिमटते आंगन का एक मुख्य कारण आर्थिक तनाव भी है, क्योंकि महंगाई की मार के बावजूद आवश्यकता की सूची दिन-प्रतिदिन लंबी हो रही है। यह पश्चिम के व्यक्तिवादी तात्कालिक सुखद चिंतन का ही परिणाम है कि आज बीमारी, बेरोजगारी, कुपोषण, बुढ़ापा या अन्य किसी संकट की स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार में अकेला और असहाय महसूस करने लगा है। भविष्य में यह अकेलापन और बढ़ने वाला है।

परिवार पर आए इस अभूतपूर्व संकट पर पूरा नियंत्रण करना तो संभव नहीं दिखता, लेकिन बढ़ते विघटन के घनत्व को मजबूत इच्छाशक्ति से कम जरूर किया जा सकता है। अधिकांश चूल्हे भले बंट गए और आंगन की आत्मीयता घट गई, लेकिन संवेदनाओं की जमा पूंजी में जो कमी हो रही है, उसके एक हिस्से को भी बचा कर रखना जरूरी है। संतोष का विषय है कि देश के अनेक क्षेत्रों में अभी भी एक चूल्हे पर एक से अधिक परिवार के सदस्यों का भोजन पक रहा है। शायद ऐसे प्रेरक अंश ही विभाजित चूल्हे के ईंधन में भावनात्मक वृद्धि करते हुए सिमटते आंगन में स्नेहिल सुधा बिखेर सकेंगे। एक चूल्हे से ही परिवार में प्रेम की आंच बढ़ेगी।

कृत्रिम मेधा पर पहल

संपादकीय 'उम्मीदों की मेधा' (12 फरवरी) पढ़ा। इससे समझा जा सकता है कि चीन अलग-थलग पड़ने के बावजूद तकनीकी क्षेत्र में कितना मजबूत है, लेकिन जिस तरह भारत से उम्मीदें जगाई गई हैं, वह भी उत्साहजनक है। प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त कर दिया है कि कृत्रिम मेधा से नौकरियां जाती नहीं, बस प्रकृति बदलती है। नए अवसर सृजित होंगे। एआइ को लेकर हमारे यहां पहले ही काम शुरू हो चुका है। इस पर रणनीति बनाई जा रही है। पेरिस में एआइ पर आयोजित सम्मेलन में भारत ने इसकी अहमियत और इसके सुरक्षित विकास पर जोर दिया है। हालांकि डेटा गोपनीयता में भारत अग्रणी देशों में माना जा रहा है। चीन का डीपसीक ऐप दुनिया के लिए अचंभा है, लेकिन इसकी सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने भी इस मामले में विश्वास और पारदर्शिता का सवाल उठाया है। हमारे यहां प्रतिभाओं का अकूत भंडार है और विश्व बाजार में भारत चीन का बराबर मुकाबला कर सकता है, मगर एआइ में अग्रणी बनने के लिए सरकार की ठोस पहल जरूरी है। इसके लिए युवाओं को सबसे पहले एआइ से जोड़ना होगा।

- अमृतलाल मारू 'रवि' इंदौर

बढ़ती कामचोरी

पिछले कुछ सालों में फसलों की बुआई और कटाई के लिए अब मजदूर नहीं मिलते। अभी हाल ही में काम के लिए राजमिस्त्री की आवश्यकता थी। करीब 15-20 दिन लगे ढूंढने में। उस वक्त देखा कि कई लोग हैं जो खाली बैठे हैं, पर वे काम करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि उनको मजदूरी कम मिलती है। साढ़े सात सौ रुपए प्रति व्यक्ति मजदूरी अब गांव में भी मिलती है, जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर से ज्यादा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वाजिब है। आजकल चुनावी वायदे, घोषणाएं, मुफ्त की रेवड़ी और महिला सशक्तीकरण की आड़ में पैसे बांटने की परंपरा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं एक परजीवी समाज का निर्माण कर रही हैं, इसमें कोई दो-राय नहीं है। हर कोई अदालत की इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत होगा, क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होगा।

- अंकित कुमार, आइआइएमसी

अमेरिका का विस्तारवाद

विस्तार प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में होता है, वह दिन-प्रतिदिन अपने क्षेत्र, संपत्ति और प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। ठीक यही बात एक देश पर भी लागू होती है। रूस से लेकर इजराइल और चीन आदि अनेक ऐसे देश हैं, जो क्षेत्र विस्तार को लेकर आए दिन विवाद खड़े करते रहते हैं। परंतु अमेरिका के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस क्षेत्र विस्तार की नीति की हद ही पार कर दी। वे तो कनाडा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको की खाड़ी तथा पनामा नहर तक अपना विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही वे अपनी मंशा जाहिर करने लगे थे। कई बयानों से उनके निजी विचार तो सामने आ ही रहे हैं। वर्तमान समय में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, परंतु उनके इस बयान पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि ग्रीनलैंड पर आक्रमण हुआ, तो वह यूरोपीय संघ पर आक्रमण माना जाएगा। देखना यह है कि अन्य यूरोपीय देश फ्रांस का समर्थन करते हैं या नहीं?

- अभय राज, प्रयागराज

साइबर ठगी

पिछले कुछ समय से देश में साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके कारण लोगों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। देखते ही देखते लोगों के बैंक खाते से रुपए गायब हो जाते हैं। इसी पर नियंत्रण के लिए आरबीआइ ने सभी बैंकों के लिए अलग से डोमेन लाने का फैसला किया है। इसके लिए जल्दी ही 'बैंक डाट इन' नाम से डोमेन शुरू करने की बात कही जा रही है। अप्रैल से शुरू किए जाने वाले डोमेन के उपयोग करने से ग्राहकों को बैंक के मेल और 'मैसेज' को पहचानने में सुविधा होगी। ये असली और फर्जी मेल एवं संदेश पहचान सकेंगे। आरबीआइ की ओर से साइबर अपराध रोकने की दिशा में की जा रही यह पहल निश्चित ही कारगर साबित होगी और आने वाले समय में साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा। साइबर ठगों को काबू में करने के लिए अब चौतरफा शिकंजा कसने की जरूरत है।

- संजय डागा, हातोद जिला, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

आयकर विधेयक

करदाता-हितैषी कदम

संसद में निर्मला सीतारमण द्वारा लाए आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य 1961 कानून के स्थान पर ज्यादा करदाता-हितैषी ढांचा बनाना है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने संसद में गुरुवार को आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक आयकर कानून, 1961 का स्थान लेगा जो पिछले छः दशकों में अनेक संशोधनों के कारण जटिल हो गया है। यह विधेयक सरलीकरण, स्पष्टता तथा करदाताओं के लिए क्रियान्वयन में सुगमता सुनिश्चित करने के साथ कर व्यवस्था का मूल ढांचा बनाए रखता है। 622 पेज में फैले इस विधेयक में 536 धाराएँ, 23 अध्याय तथा 16 अनुसूचियां हैं जिससे यह 880 पेज में फैले 1961 के कानून की तुलना में काफी संक्षिप्त है। इनमें एक प्रमुख परिवर्तन 'पिछले वर्ष' को हटाना तथा 'आंकलन वर्ष' के स्थान पर 'कर वर्ष' रखना है जिससे कर फाइलिंग के संबंध में भ्रम दूर हुआ है। स्पष्टता और बढ़ाने के लिए 'नाटविथड्रॉइंग' जैसे भ्रामक शब्दों के स्थान पर 'इररिस्पेक्टिव' शब्द रखे गए हैं। नए विधेयक में प्रमुख गणनाओं, जैसे टीडीएस, अनुमानित कराधान, वेतन कराधान एवं खराब कर्जों के लिए छूट जैसी प्रमुख गणनाओं के लिए फार्मूले व सारणियां दी गई हैं। जटिल व्याख्याओं और प्राविधानों को हटा कर कानून को ज्यादा समझ तथा प्रयोगकर्ता-हितैषी बनाया गया है। एक औपचारिक 'करदाता चार्टर' शामिल कर कर प्रशासन में पारदर्शिता व न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकार और

दायित्व रेखांकित किए गए हैं। टीडीएस संबंधी सभी प्राविधानों को एक अकेली धारा में समाहित कर सरल सारिणीय फर्मेट दिए गए हैं जिससे जटिलता कम होती है तथा क्रियान्वयन बेहतर होता है। इसके साथ ही विधेयक में पिछले 60 साल में प्रमुख अदालती फैसलों को समाहित कर विवादों को कम कर विधिक निश्चितता प्रदान की गई है। कर्मचारियों के स्टाक विकल्पों के लिए कर व्यवहार विकल्पों में सुधार कर ज्यादा पारदर्शी कराधान ढांचा पेश किया गया है जो स्टाक विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों से न्यायोचित व अनुमान योग्य टैक्स व्यवहार करता है। कर छूटों को स्पष्ट करते हुए कुल आय से अधिक वाली आमदनी को अब पूरे कानून में फैलाने के बजाय खास अनुसूचियों में रखा गया है। इन परिवर्तनों से अनेक लाभों की उम्मीद है जिनमें सरल क्रियान्वयन, सरल कराधान ढांचा, कम मुकदमेबाजी, सरल टीडीएस ढांचा तथा स्टाक विकल्पों वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर अनुमान शामिल हैं। लेकिन इन लाभों के बावजूद विधेयक के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं।

करदाताओं और बिजनेसों को नई परिभाषाओं और प्राविधानों को लागू करने के लिए ज्यादा समय चाहिए। 'पिछले वर्ष' को हटाने और 'आंकलन वर्ष' रखने से परिवर्तन के दौरान अस्थाई भ्रम पैदा हो सकता है। इसके साथ ही सारिणियों व सरल टीडीएस धाराओं को आयकर रिटर्न फर्मों, साफ्टवेयरों और रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं में शामिल करना होगा। आयकर विधेयक, 2025 ज्यादा पारदर्शी, सक्षम तथा करदाता-हितैषी व्यवस्था की ओर एक कदम है। जहां यह नए टैक्स नहीं शुरू करता है, वहीं भाषा के सरलीकरण, भ्रम दूर करने तथा न्यायिक पूर्व उदाहरणों को समाहित करने से क्रियान्वयन का खर्च तथा कर विवाद घटेंगे। यदि कानून का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो यह विश्वासक कर प्रशासन की क्षमता में वृद्धि करेगा तथा करदाताओं में बेहतर स्वैच्छिक क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करेगा। वित्त विभाग की संसदीय स्थाई समिति में चर्चा के बाद संसद में पेश किया जाएगा। संसद द्वारा पास होने के बाद इस विधेयक को संभवतः 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा। उसी समय यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में यह नया कानून पुराने कानून की तुलना में कैसा काम करता है।

नियामकीय बाधाओं में कमी

नियामकीय बाधायें घटाने के लिए लाई 'जन विश्वास 2.0' जैसी पहलों के साथ ही लाल फीताशाही व रिश्वत जैसी विभीषिकायें समाप्त करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

ए एस मित्तल
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भ्रष्टाचार से मुकाबले के निरंतर प्रयासों के बावजूद भारत में बिजनेसों की प्रगति में बड़ी बाधायें बनी हुई हैं। हालिया 'इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे 2024' में एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की गई है। 66 प्रतिशत बिजनेस उद्यमों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है, जबकि 54 प्रतिशत ने कहा कि उनको सरकारी प्रक्रियायें तेज करने, परमिट लेने, क्रियान्वयन सुनिश्चित करने या डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया गया। यह समस्या श्रम विभाग, जीएसटी, आयकर, प्रदूषण, प्राविडेंट फंड, संपत्ति पंजीकरण, औषधि एवं स्वास्थ्य विभागों में ज्यादा गंभीर है। इसके आर्थिक प्रभावों से इनकार नहीं किया जा सकता है।

ईवाई-पिक्की के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि पांच में से चार उत्तरदाताओं का विश्वास है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई में भ्रष्टाचार बड़ी बाधा है। इससे भारत के क्रियान्वयन ढांचे में तत्काल सुधार की आवश्यकता उजागर होती है ताकि पारदर्शी, न्यायोचित और अनुमान योग्य नियामक परिवेश बनाया जा सके। हालांकि, सरकार ने दो साल पहले नियामक सुधार शुरू किए थे, पर इनकी प्रगति धीमी है। जन विश्वास कानून, 2023 इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जिसने जेल जाने संबंधी 180 प्राविधानों को अपराध के दायरे से हटा कर बिजनेसों और उद्यमियों की अनेक क्रियान्वयन बाधायें दूर की हैं।

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण के 2025 बजट में 'जन विश्वास 2.0' की घोषणा से 100 और प्राविधानों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है। हालांकि, यह कदम स्वागत योग्य है, पर यह केवल सतही कदम है क्योंकि अभी भी जेल की सजा वाले 20,000 से अधिक प्राविधान वैसे ही बने हुए हैं। भारतीय बिजनेसों के लिए क्रियान्वयन एक जटिल चुनौती है, लेकिन भ्रष्टाचार से मिल कर यह अलंघ्य बाधा बन जाती है। नियामक अधिकारी अक्सर क्रियान्वयन प्राविधानों का प्रयोग कर रिश्वत वसूल करते हैं। अनेक बिजनेसों का मानना है कि नियामक संस्तुतियां प्राप्त करने के लिए अब भी अनाधिकारिक भुगतान करने पड़ते हैं, भले ही सभी आवश्यक नियम पूरे किए गए हों। व्यवस्था की बड़ी गड़बड़ी इंस्पेक्टरों को मिले विवेकाधीन अधिकार हैं जो बिना किसी जवाबदेही के जेल भेजने या फैक्ट्री बंद कराने की धमकी देते हैं।

एक और बड़ा मुद्दा बार-बार क्रियान्वयन अपडेट देना है जो अक्षमता और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। केवल पिछले वर्ष 9,420 क्रियान्वयन अपडेट आईं, यानी औसतन रोज 36 परिवर्तन किए गए। असाधारण रूप से अधिक इन परिवर्तनों का अब या तो नियामकीय अक्षमता है अथवा यह जानबूझ कर व्यवस्था को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का प्रयास है। असाधारण गति से नियमों को अपडेट करने की आवश्यकता वाली नौकरशाही या तो दूरगामी सोच में अक्षम है या ऐसा परिवेश बनाने का प्रयास करती है जहां रिश्वत देना अपरिहार्य हो जाए। हालांकि, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण-एफएसएसएआई का हालिया निर्देश इस अव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस जनवरी से प्रभावी खाद्य लेबिल परिवर्तन नियमों की घोषणा साल में केवल एक बार की जाएगी। इस प्रकार यह अनुमान योग्य नियामकीय परिवर्तनों का माडल है।

ऐसे ही परिवर्तन सभी नियामकीय संस्थाओं में किए जाने चाहिए। क्रियान्वयन संबंधी जेल भेजने की धाराओं का जन्म श्रम कानूनों से होता है जो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। हालांकि, भारत ने 29 उपनिवेश कालीन श्रम कानूनों के स्थान पर चार आधुनिक श्रम संहितायें तैयार की हैं, पर अभी क्रियान्वयन की प्रतीक्षा करते हुए वे अधर में लटकी हैं। इस महत्वपूर्ण कदम को लंबे समय से 'स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े श्रम सुधार' कहा जा रहा है, पर वे अब भी अनिश्चित हैं। राज्य सरकारों को तेजी से काम करते हुए इन सुधारों का क्रियान्वयन करना चाहिए। भारत में एक फैक्ट्री लगाने के लिए 40 से अधिक सरकारी विभागों को सैकड़ों स्व-प्रमाणित व नोटरी दस्तावेज देने होते हैं। यह आदिमकालीन व्यवस्था भ्रष्टाचार और अक्षमता को जन्म देती है।

इस प्रक्रिया के स्थान पर डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति के लिए एक 'बिजनेस आईडेंटीफायर' की जरूरत होनी चाहिए जिससे उसे 'डिजी लाकर' के माध्यम से पुष्ट दस्तावेज पेश कर नियामकों तक पहुंच का अवसर मिले। ऐसी व्यवस्था से महीनों लगने वाला समय कुछ दिनों में बदल जाएगा तथा यह हवाईअड्डा सुरक्षा में भारत की 'डिजी यात्रा' का समरूप बनेगा। भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रस्ट्रक्चर-डीपीआई ने प्रशासन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं, पर बिजनेस संबंधी नियम अभी बिखरे हुए हैं। उद्यमियों को अभी विभिन्न केन्द्र व राज्य अधिकारियों द्वारा जारी कम से कम 23 पहचान नंबरों से गुजरना पड़ता है जिनमें पैन, जीएसटिन और सिन के साथ ही पेशेवर टैक्स नंबर व फैक्ट्री लाइसेंस नंबर शामिल हैं।

प्रत्येक पहचान की अपनी समयसीमा होती है जिसे समय-समय पर नवीनीकरण के साथ भुगतान करना होता है। इससे अक्षमता और भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इससे निपटने के लिए एकीकृत 'एक राष्ट्र, एक बिजनेस पहचान' व्यवस्था से क्रियान्वयन में नाटकीय परिवर्तन आएंगे, नौकरशाही टकराव कम होगा तथा भ्रष्ट व्यवहारों के अवसर घटेंगे। इस पहल की दिशा में एक छोटा बजटीय आबंटन नियामक आदान-प्रदान को सहज बना कर बिजनेस स्थल के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा सकता है।

निवेश और प्रतिभा की वैश्विक प्रतियोगिता तेज हो रही है। अमेरिका में प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं तथा प्रस्तावित डिपार्टमेंट आफगवर्नमेंट इफेसियेंसी-डाज बिजनेस कार्यवाहियों को सुगम बना सकता है। यदि दुनिया में 27 ट्रिलियन डालर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ज्यादा बिजनेस-हितैषी बन सकती है तो विवेशक 4 ट्रिलियन डालर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को क्यों चुनेंगे जहां लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो? अमेरिका की बढ़ी क्षमता वैश्विक पूंजी को आकर्षित करेगी और भारत को निवेश तथा उद्यमी प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ सकता है जो 'ज्ञानवान अर्थव्यवस्था' बनने के लिए बहुत जरूरी है। सुस्ती का समय अब बीत गया है क्योंकि कल जो अवसर था, आज वह आवश्यकता बन गया है।

आर्थिक गतिशीलता बनाने के लिए भारत को नौकरशाही बाधायें दूर करनी चाहिए, अनुमान योग्य क्रियान्वयन परिवेश बनाना चाहिए तथा भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए। हालांकि, इसके लिए 'जन विश्वास 2.0' के माध्यम से सुगठित ढांचागत व्यवस्था का प्रयास किया गया है, पर केवल यही कदम भारत में बिजनेस सुगमता बढ़ाने तथा भारत का आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काफी नहीं है। सरकार को वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने तथा भारतीय उद्यमियों को अनावश्यक रूप से नियामकीय टकराव से डर के बिना खोज, विस्तार व रोजगार सृजन करने के अवसर देने चाहिए। भारत इस समय महत्वपूर्ण मोड़ पर है।

देखना होगा कि नियामकीय सुधारों के लिए गठित उच्चाधिकार समिति साहसी क्रियान्वयन सुधार करती है या सुस्ती प्रदर्शित करती है। इस समय आधुनिक होने या विश्व आर्थिक दौड़ में पीछे रह जाने के बीच कोई और विकल्प नहीं है।

भारत की कृत्रिम बुद्धि राजनीति

> दिल्ली में चौथे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की भारत की योजना एआई नवाचार में नेतृत्व के लिए इसके रणनीतिक प्रयास को रेखांकित करती है।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस और वाशिंगटन की हालिया यात्राएं, जहां उन्होंने विकसित दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली नेताओं के साथ मुलाकात की, बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है। इन उच्च स्तरीय द्विपक्षीय चर्चाओं का केंद्रीय विषय तेजी से खंडित हो रहे विश्व में उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग के इर्द-गिर्द घूमता रहा। भारत ने मेजबान देश फ्रांस के साथ पेरिस में एआई एक्शन समिट के सह-अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समर्पित तीसरा वैश्विक आयोजन था, जिसकी तुलना प्रौद्योगिकी के कुंभ मेले से की जा रही है—जिसमें नीति निर्माता, कॉर्पोरेट नेता, विशेषज्ञ और विश्व के नेता एक साथ आते हैं।

शिखर सम्मेलन का प्राथमिक फोकस एआई की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाने पर था, एक ऐसी तकनीक जिसकी तुलना पहिये के आविष्कार और आग पर महारत जैसी अभूतपूर्व मानवीय प्रगति से की गई है। इस बीच, चीन ने एक तेजतर्रार जनरेटिव एआई टूल डीपसीक पेश किया, जो एआई शोध और विकास में अरबों डॉलर का निवेश करने वाली अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों के लगभग एकाधिकारवादी प्रभुत्व के लिए एक गंभीर चुनौती है।

वैश्विक एआई शासन की जटिलताओं को और बढ़ाते हुए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन के फ्रेमवर्क पर अंतरिम अंतिम नियम के रूप में जाना जाने वाला एक कार्यकारी आदेश पारित किया। इस आदेश ने एआई विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर निर्यात

प्रतिबंध लगा दिए, जो अमेरिकी हितों के प्रतिकूल माने जाने वाले देशों - मुख्य रूप से चीन - को लक्षित करते हैं, लेकिन भारत जैसे करीबी सहयोगियों को भी प्रभावित करते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी हितधारकों ने तब से नए अमेरिकी प्रशासन से पहले से स्थापित विनियामक फ्रीज ऑर्डर के साथ स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने एआई डिफ्यूजन नियम को तब तक के लिए निलंबित करने का आह्वान किया है जब तक कि आगे की समीक्षा और हितधारक परामर्श यह सुनिश्चित न कर लें कि विनियम राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हितों दोनों के साथ संरेखित हैं। उद्योग की अपील के बावजूद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक अपने पूर्ववर्ती द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश को पलट नहीं दिया है। हालांकि, उनके प्रशासन ने 23 जनवरी को एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया, जो दृष्टिकोण में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर, राष्ट्रपति ट्रम्प ने एआई नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि देश ऐतिहासिक रूप से अपनी मजबूत मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थानों और उद्यमशीलता की प्रेरणा के कारण एआई नवाचार के मामले में सबसे आगे रहा है।

उनके निर्देश में उन बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया जो अमेरिकी एआई प्रगति में बाधा डाल सकती थीं, कुछ मौजूदा एआई नीतियों को रद्द कर दिया और एआई में अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत किया। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि एआई प्रभुत्व को बनाए रखना मानव उन्नति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। वैश्विक एआई शासन, नवाचार और विकास में एक प्रमुख भूमिका का लक्ष्य रखते हुए, भारत ने अपना एक महत्वाकांक्षी एआई मिशन निर्धारित किया है। हालांकि, यह विजन उच्च-स्तरीय सेमीकंडक्टर चिप्स और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) पर बहुत अधिक निर्भर है, जो वर्तमान में अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्मों द्वारा नियंत्रित हैं पेरिस में मोदी की भागीदारी, दिल्ली में चौथे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की भारत की घोषणा, और राष्ट्रपति ट्रम्प और अन्य विश्व नेताओं के साथ उनकी चर्चा वैश्विक एआई प्रगति के मामले में भारत को सबसे आगे रखने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का संकेत देती है।

ये कूटनीतिक प्रयास तेजी से विकसित हो रहे एआई परिदृश्य को नेविगेट करने और इस परिवर्तनकारी तकनीक के भविष्य को आकार देने में भारत की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने में एक आवश्यक कदम है।

आप की बात

भारत-फ्रांस रिश्ते

भारत और फ्रांस दोनों ही जितने पुराने मित्र है उतनें ही संबंध भी मजबूत और बहुआयामी हैं। हाल ही की प्रधानमंत्री की यात्रा ने इन संबंधों को और मजबूती प्रदान की है।दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृत्रिम मेधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है जो रणनीतिक साझेदारी कि हिस्सा है।फ्रांस शुरू से ही भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का पक्षधर रहा है और समय-समय पर वह वैश्विक मंच पर भारत का समर्थन करता आया है। फ्रांस का भारत को वैश्विक शक्ति बनने की क्षमता को समर्थन संबंधों की प्रगाढ़ता का उदाहरण है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार का 19 अरब डॉलर तक पहुंचना और फ्रांस से 2000-24 के बीच 10 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आना? व्यापारिक सुझबूझ का परिचय है। जलवायु संकट से निपटने के लिए दोनों देशों का इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की साझेदारी विश्व हितार्थ है। परमाणु संयंत्रों के संयुक्त विकास और सुरक्षित कृत्रिम मेधा के लिए हुए समझौते बहुआयामी हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग न केवल आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में लाभदायक है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शक्ति संतुलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत-फ्रांस की बढ़ती नजदीकी वैश्विक राजनीति में एक सशक्त संदेश है।

- **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पीएम मोदी का अमेरिका दौरा

प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से ट्रंप की भारत नीति को लेकर जो आशंका थी वह काफी हद तक दूर हुई है। जैसी कि आशा की जा रही थी वैसी ही मजबूत केमिस्ट्री इन दोनो नेताओ के बीच देखने को मिली। इस दो दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस यात्रा के दौरान हुई बैठकों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई भारत और अमेरिका ने रक्षा, ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में अपने सहयोग को व्यापक करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने व्यापार घाटा कम करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति जताई। क्वाड सुरक्षा साझेदारी को फिर से सक्रिय किया, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। यह सहयोग इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।

- **विमलेश पगारिया**, बदनावर, मप्र

ट्रंप की मान गए...

हालांकि ट्रम्प के चीन-सीमा विवाद के सुझाव को भारत ने ठुकरा दिया. लेकिन व्यापार समझौते पर ट्रम्प-मोदी वार्ता काफी सफल रही. करीब 43 लाख करोड़ के व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. ट्रम्प ने मोदी की तारीफ़ की और कहा कि मोदी वाक् पटुता में मुझसे भी अधिक जानकार हैं. वैसे ट्रम्प-मोदी के बीच जो भी वार्ता हुई उसमें दोनों देशों के विवादित मामलों से दूर ही रही और सकारात्मक मुद्दों पर ही उनके बीच बातचीत सफल रही. इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ही देश किसी विवाद में न पड़कर विकास और शांति को अधिक महत्व देना चाहते हैं साथ ही दोनों की दोस्ती को बेहतर बनाये रखना चाहते हैं. अवैध प्रवासियों और टेरिफ पर वे तटस्थ रहे. अडानी मामले पर उसे निजी मामला करार देते हुए उससे ही दूरी बनाये ही रही मोदीजी ने. उनकी 2 घंटे की बातचीत काफी सकारात्मक और अपने-अपने राष्ट्रहितों के मद्देनजर रही. ये एक बेहतर कूटनीति ही कही जा सकती है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच. इससे अमेरिका और भारत के बीच सम्बन्ध मजबूत होंगे और भविष्य में भी एक-दूसरे के बीच सहयोगात्मक रुख बना रहेगा. क्योंकि दोनों का उद्देश्य युद्ध नहीं शान्ति से समाधान के रास्ते अपनाना है. जैसा कि दोनों बारम्बार कह चुके हैं।

- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

बंद हो रेवड़ी संस्कृति

राजनीतिक दलों को रेवड़ी बांटने वाली संस्कृति पर फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी के अंतर्गत उचित ही कहा है कि रेवड़ियां लोगों को अकर्मण्यता की ओर धकेल रही हैं। चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए राजनीतिक दल रेवड़ियां बांट कर वोट हासिल करने का भरपूर प्रयास करते हैं। रेवड़ी संस्कृति बंद होनी ही चाहिए। रेवड़ियां व्यक्ति को आलसी और अकर्मण्य बना देती हैं। देश में लोग काम करने और काम ढूंढने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में पैसा और राशन मिल रहा है। आज के दौर में राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं को लालच देकर मुफ्त का ऑफर दे रहे हैं। कई राज्यों में बिजली बिलों में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त हैं। दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल की नई रेवड़ी पद्धति के बाद अन्य दल की भी रेवड़ियां बांटने की जरूरत आ पड़ी थी। समझने की आवश्यकता है कि मुफ्त की घोषणाओं से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। बदले में उसकी भरपाई टैक्स बढ़ा कर टैक्सपेयर से वसूला जाता है।

- **अंकित सोनी**, मनावर, मप्र

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

सम्पादकीय

भारत और फ्रांस के बीच सम्मान और विश्वास की परस्पर दोस्ती, भरोसेमंद के साथ ही रणनीतिक सहयोगी

भारत फ्रांस के करीबी साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास का रिश्ता रहा है। चीन के बरक्स भारत की क्षमता बढ़ाने में सहयोग का मसला हो या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा, फ्रांस ने हर बड़े मौके पर भारत का साथ दिया है। दुनिया में तेजी से उभरती ताकत के रूप में भारत की संभावनाओं को फ्रांस पहले ही भांप चुका है। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर पनडुब्बी बनाने में सहयोग कर उसने साबित कर दिया कि वह भारत का न केवल भरोसेमंद बल्कि सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की परस्पर निकटता का प्रमाण कई बार मिल चुका है। इस बार दोनों देशों ने आधुनिक परमाणु संयंत्रों को संयुक्त रूप से विकसित करने का संकल्प किया है। फ्रांस के मारसेई में एक आशय पत्र पर दस्तखत के बाद दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के लिए परमाणु ऊर्जा अहम है। इस लिहाज से देखें, तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण कदम है। फ्रांस न केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देता रहा है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी निभाते हुए आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में भी सहयोग करता रहा है। नतीजा यह कि वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच कारोबार उन्नीस अरब डालर तक पहुंच गया था। इससे पहले वर्ष 2000 से 2024 के मध्य फ्रांस से कोई दस अरब डालर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। इस बार की प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान भी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर दोनों देशों ने जोर दिया है। इससे व्यापार संबंध और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। इसके अलावा दोनों देश जलवायु संकट से निपटने की दिशा में भी एक मंच पर काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत और फ्रांस ने 'इंटरनेशनल सोलर अलायंस' का गठन किया, जिसमें सौ से अधिक देश शामिल किए गए थे। भारत-फ्रांस के शीर्ष नेताओं ने असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में जिस तरह इस बार परस्पर सहयोग की गंभीरता से समीक्षा की है, इससे लगता है कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जता कर साफ कर दिया है कि उनके संबंध बहुआयामी हैं। इस तरह दोनों ने दोस्ती को एक नया आयाम ही दिया है। उम्मीद यह भी है कि कृत्रिम मेधा से लेकर प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में सहयोग और मजबूत होगा। दस अहम समझौते के बाद फ्रांस एक बार फिर सच्चे दोस्त के रूप में सामने आया है।

इन समझौतों के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में असैन्य सहयोग भी मील का पत्थर साबित होगा। कृत्रिम मेधा और नवाचार की दिशा में भारत और फ्रांस ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। सुरक्षित और विश्वसनीय कृत्रिम मेधा के विकास के लिए दोनों देश अब साझा रूप से काम करेंगे। यह विकसित प्रौद्योगिकी वैश्विक हितों के लिए काम करेगी। कूल मिला कर देखें, तो भारत और फ्रांस के बीच प्रगाढ़ होते संबंध चीन और अमेरिका को संदेश देने का भी प्रयास है।

आज का इतिहास

बढ़ता राजस्थान

15 फ़रवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- महान् खगोलशास्त्री गैलीलियो का जन्म 1564 में हुआ।
- फ्रांस के खिलाफ़ डचों से इंग्लैंड नरेश चार्ल्स द्वितीय ने 1677 में गठबंधन किया।
- आस्ट्रेलिया और प्रसिया के बीच 1763 में शांति संधि हुई।
- अमेरिका में सेंट लुईस शहर की स्थापना 1764 में हुई।
- फ्रांस ने 1798 में रोम पर कब्ज़ा कर उसे गणराज्य घोषित किया।
- पुरँको, प्रसियन संधि के बाद प्रसिया ने 1806 में ब्रिटिश जहाज़ों के लिए अपने बंदरगाह बंद किये।
- 15 फरवरी, 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टैडीबियर को मॉरिस मिख्टॉम द्वारा बाजार में उतारा गया।
- ब्रिटेन की लेबर पार्टी की 1906 में स्थापना हुई।
- अमेरिका में अनुबंध एयर मेल सेवा की 1926 में शुरूआत।
- सिंगापुर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
- बर्लिन पर ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने 1944 में बमबारी की।
- बेल्जियम में 1961 में हुए बोइंग 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से लगभग 50 लोगों की जान गयी।
- मैपल (एक प्रकार का छायादार वृक्ष) के पत्ते को 1965 में कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला।
- भारत में 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए।
- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में की गई।
- श्रीलंका की राजधानी का कोलम्बो से जनवर्धनपुर को 1982 में स्थानांतरण।
- तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने 1989 में अफगानिस्तान से वापसी की थी।
- ईराक ने 1991 में कुवैत से हटने की घोषणा की।
- परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1999 में मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा।
- मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक बी.आर चोपड़ा को 2000 में दादासाहब फालके पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 15 फरवरी 2001 में इस्लाम में हिंसा भड़क उठी इसके साथ ही इसी दिन इस्त्रायल ने पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी सील की।
- अफ़ग़ानिस्तान में हज यात्रियों की भीड़ ने 2002 में पर्यटन मंत्री अब्दुल रहमान को पीट-पीटकर मार डाला।
- एरियन 4 राकेट से 2003 में दूरसंचार उपग्रह 'इंटलसैट' अंतरिक्ष में छोड़ा गया।
- ईरान की राजधानी तेहरान में 2005 में नमाजियों से खचाखच भरी एक मस्जिद में आग लगने से लगभग 60 लोगों की जान गयी।
- गुजरात के जूनागढ़ स्थित स्वामीनारायण मन्दिर के पुजारी सहित चार लोगों को 2005 में सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया।
- 15 फरवरी,साल 2006 पाकिस्तान की कैबिनेट की तरफ से दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र समझौता (साफ्टा) को स्वीकार किया गया।
- हिन्द महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का 2008 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न।

विशेष आलेख

नौनिहालों के सपनों पर हावी होते कोचिंग सेंटर

भारत में कोचिंग सुविधाओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। ये केंद्र छात्रों को स्कूल स्तर की परीक्षाओं के साथ-साथ जेईई, नीट और यूपीएससी की तैयारी में मदद करते हैं। हालाँकि, इस उद्योग की विस्फोटक वृद्धि से कई चिंताएँ भी पैदा हो रही हैं। लगभग 58, 000 करोड़ के बाज़ार मूल्य के साथ, भारत का फलता-फूलता कोचिंग क्षेत्र अब पूरे देश से करोड़ों छात्रों को आकर्षित करता है। पारंपरिक शिक्षा में अंतर को पाटने के लिए, ये निजी संस्थान विशेष परीक्षा की तैयारी प्रदान करते हैं। हालाँकि, चिंताएँ हैं कि उनका बाज़ार-संचालित दृष्टिकोण औपचारिक शिक्षा के मानकों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और शैक्षणिक माँगों को बढ़ाकर छात्रों की पढ़ाई पर भारी बोझ डालता है। कोचिंग सेंटरों के विस्फोटक विकास के कारण भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली और छात्रों के कल्याण सम्बंधित चिंताएँ जताई गई हैं।

प्रियंका सौरभ

छात्रा का भलाइ आर औपचारिक शिक्षा में कोचिंग सेंटरों का प्रभाव कम हो गया है। छात्र अपनी अकादमिक पढ़ाई से पहले कोचिंग सत्रों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे व्यापक शिक्षा प्रदान करने में स्कूलों की भूमिका कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, बहुत से छात्र केवल उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल ट्यूशन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। कोचिंग सेंटर में लंबे समय तक पढ़कर कड़ी प्रतिस्पर्धा करने वाले छात्र तनाव, चिंता और बर्नआउट का अनुभव करते हैं। कोटा के छात्रों की आत्महत्या की रिपोर्ट कोचिंग सेंटर के माहौल से होने वाले गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान को दर्शाती है। कोचिंग सेंटर अकादमिक फोकस और तैयारी की रणनीतियों पर हावी हैं, जिससे छात्रों की अपनी शिक्षा में रुचि खत्म हो जाती है। कोचिंग सेशन में भाग लेने के लिए, कई सीबीएसई स्कूलों में छात्र महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक वर्षों के दौरान नियमित कक्षाएँ छोड़ देते हैं। उच्च कोचिंग लागत आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को उच्च-गुणवत्ता की तैयारी तक पहुँचने से रोककर शैक्षिक अवसरों में अंतर को और बढ़ा देती है। प्रीमियम जेईई तैयारी कार्यक्रमों की लागत लाखों तक है, जो उन लोगों को अलग करती है जो कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते हैं।

कोचिंग उद्योग कई कारकों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है। कोचिंग की आवश्यकता उच्च-दाँव वाली प्रवेश परीक्षाओं, जैसे कि जेईई और एनईईटी पर ज़ोर देने से प्रेरित है। आईआईटी सीटों की सीमित संख्या के कारण, छात्र चयनित होने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेते हैं। माता-पिता और छात्रों के अनुसार, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग सेंटर आवश्यक हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन में सुधार होगा, इसलिए कई माता-पिता कोचिंग फीस पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं की उन्नत तैयारी का अभाव अक्सर एक कमी छोड़ देता है जिसे कोचिंग सेंटर भर देते हैं। राज्य बोर्ड राज्य बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान पर ज़ोर देते हैं, जबकि कोचिंग सेंटर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष तैयारी प्रदान करते हैं। कोचिंग सेंटर में शामिल होने के लिए छात्रों पर साथियों और अभिभावकों के दबाव के परिणामस्वरूप कोचिंग संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। पूरा परिवार कोटा और हैदराबाद जैसी जगहों पर कोचिंग के अवसरों के लिए जा रहा है। कोचिंग सेंटर रैंक-केंद्रित विज्ञापनों और सफलता की कहानियों के साथ छात्रों को आकर्षित करते हैं। अपने विज्ञापनों में, कोचिंग सेंटर अपने सर्वश्रेष्ठ छात्रों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि सफलता सुनिश्चित है।

इसका सामान्य रूप से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। कोचिंग सेंटरों द्वारा पाठ्यक्रम से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ज़ोर दिए जाने के परिणामस्वरूप छात्र अपनी नियमित शैक्षणिक पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं। कक्षा 11 और 12 के दौरान, छात्र पूरे दिन के जेईई या नीट कोचिंग सत्र में भाग लेने के लिए अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं। औपचारिक शिक्षा की वैधता कम हो जाती है क्योंकि छात्र अपना ध्यान कोचिंग सेंटरों की ओर मोड़ते हैं, जिससे शिक्षक की प्रेरणा कम हो जाती है। छात्र केवल कोचिंग सामग्री का उपयोग करते हैं और शहरी क्षेत्रों के स्कूल कक्षा में कम भागीदारी की रिपोर्ट करते हैं। परीक्षाओं में सफल होने के लिए रटने को प्रोत्साहित करके, कोचिंग सेंटर स्कूलों में सिखाई जाने वाली आलोचनात्मक सोच और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग कौशल को कमज़ोर कर देते हैं। प्रवेश परीक्षा अध्ययन मार्गदर्शिकाएँ अक्सर वैचारिक विश्लेषण की तुलना में नियमित समस्याओं को हल करने पर अधिक ज़ोर देती हैं। खेल, कला और पाठ्येतर गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं क्योंकि छात्र कोचिंग कक्षाओं में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। छात्र अक्सर इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करते समय स्कूल द्वारा प्रायोजित एथलेटिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से चूक जाते हैं। परीक्षा-केंद्रित संसाधनों तक पहुँच उच्च कोचिंग लागतों द्वारा सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप एक दोहरी प्रणाली है जहाँ केवल गरीब ही मुख्यधारा की शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। सरकारी स्कूली बच्चे अल्प शैक्षिक संसाधनों पर निर्भर हैं, जबकि अमीर छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों में जाते हैं।

स्कूलों में पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, निजी कोचिंग सुविधाओं पर निर्भरता कम करने के लिए स्कूलों में कोचिंग सत्र और उन्नत शिक्षण मॉड्यूल शुरू करें। ऑनलाइन संसाधनों को प्रोत्साहित करें जो परीक्षण लेने की लागत और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए अधिक किफायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। सभी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नपटल और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। विशेष कोचिंग की आवश्यकता को कम करने के लिए ज्ञान-भारी परीक्षाओं की तुलना में योग्यता-आधारित आकलन को प्राथमिकता दें। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विषय-वस्तु के ज्ञान की तुलना में योग्यता और आलोचनात्मक सोच को प्राथमिकता देता है। स्कूल के शिक्षकों को उन्नत निर्देश और सलाह देने के लिए आवश्यक संसाधन देने के लिए शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करें। देश भर के शिक्षकों के पेशेवर कौशल को बढ़ाना निष्ठा जैसे सरकारी कार्यक्रमों का लक्ष्य है।

आयकर कानून के सरल होने विवाद घटेंगे

ललित गर्ग

मौजूदा आयकर कानून की तुलना में नया आयकर कानून शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफी छोटा है, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं। एक्ट के अलग-अलग चैप्टर भी 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं, नए कानून में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि लोग आसानी से आयकर के नियम समझ सकें और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए। यह बिल आयकर प्रावधानों को सरल और आसान बनाने के बड़े मकसद से जुड़ा है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों में दिख सकता है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को 64 साल पुराने आयकर कानून-1961 के सरलीकरण और इसमें चले आ रहे बेवजह के प्रविधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स बिल-2025 पेश कर दिया। 622 पन्नों के इस विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं। जबकि आयकर कानून-1961 में 1647 पन्ने और 819 धाराएं रही है। इस विधेयक में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर करदाताओं के लिए इसे आसान और पारदर्शी बनाया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट, सहज, सरल और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। निश्चित ही नये आयकर कानून से टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता के नए दौर की शुरुआत होगी, यह आयकर कानून का नया सूरज है, जो जटिलताओं एवं पेचिदगियों की जगह सरलता एवं सहजता की रोशनी बनेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रारंभ से ही कम-से-कम कानूनों एवं सरल-व्यवस्था के हिमायती रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में आर्थिक क्रांति का शंखनाद अनेक मोर्चे पर हो रहा है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बदली है बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल चुकी है। 1961 में बने आयकर कानून में बदलती जरूरत के मुताबिक नए-नए संशोधन होते रहे, जिससे इसकी जटिलता बढ़ती चली गई। यह जटिलता न केवल करदाताओं को उलझन में डालती थी बल्कि कानूनी प्रावधानों की कई तरह से व्याख्या अनेक उलझने एवं विवाद खड़ा करती रही है। इन जटिल होती परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि अपने देश में टैक्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ते गये। इन लगातार बढ़ते विवादों के कारण ही इसे दुनिया की टैक्स विवादों की राजधानी कहा जाने लगा। खासकर पिछले करीब डेढ दशक में यह ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। नौबत ऐसी आ गई कि 2023-24 तक टैक्स संबंधी मुकदमों में विवादित रकम बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसका करीब 87 प्रतिशत हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा है। संभावनाएं हैं एवं सराहनीय भी है कि नये कानून के लागू होने से विवाद भी कम होंगे एवं जनता भी राहत की सांस लेगी। निश्चित ही यह कदम स्वागतयोग्य है। इस कानून को लाकर मोदी सरकार और विशेषतः वित्तमंत्री ने अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन किया है। आयकर कानून-1961 की जटिलताओं के कारण विवादों का अंबार लगा रहा है। जबकि आयकर विभाग को इन विवादों से कोई फायदा भी नहीं होता है क्योंकि इनमें जीत का उसका रेकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) की ओर से 34 देशों में टैक्स विवादों पर हुई एक स्टडी के मुताबिक 2015 में भारत में टैक्स विभाग को महज 11.5 प्रतिशत मामलों में ही जीत मिली थी। ओईसीडी देशों का औसत इस मामले में 65 प्रतिशत है। अवश्य ही यह स्थिति भारत के लिये चिन्ताजनक रही है।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार है ओमप्रकाश गिलोत्रा। जिनका जन्म 25 अप्रेल सन 1960 को हुआ। ग्रामीण परिवेश से रहे लेकिन एज्यूकेशन एलएलबी तक कर खुद का फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया। ओमजी पुराने समय में अलवर में फोटोग्राफी व्यसाय को आगे बढ़ाने के मसीहा माने जाते हैं। बात उस दौर की कर रहे हैं जब फोटोग्राफी का अपना अलग क्रेज हुआ करता था। अपनी सुनहरी यादों को कागज में सिमटाए वो जीवन बड़ा की शानदार और अद्भुत था। उस शानदार जीवन के मांझी के रूप में ओमप्रकाश गिलोत्रा को जाना जाता है। संघर्ष के दिन और अलवर की सबसे पहली क्यूएसएस कलर लैब लगाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। लेकिन पुरूषार्थी तो पुरूषार्थी समाज का गहना ही है। इसलिए पीछे मुड़ कर देखा नहीं ओर आगे चलते रहे। फोटो पेपर पर बनाए जाने का काम पहले जयपुर या दिल्ली जाया करता था लेकिन सबसे पहली लैब न्यूलाईट कलर लैब अलवर में ओम जी गिलोत्रा ने लगाई उसके बाद सैकड़ों की संख्या में नए बेरोजगार युवाओं ने फोटोग्राफी जैसे व्यपार को अपनाया और अपना जीवन यापन किया। ओम जी बहुत व्यवहारशील व्यक्तिव के धनी हैं। अपने मजबूत इरादों और इमानदार छवि के कारण आज भी साफ और स्वच्छ छवि के रूप में जाने जाते हैं। कर्मठता क्या होती है ये इनकी जीवन शैली से सीखा जा सकता है। बीमार होने के बाद भी गजब का आत्मविश्वास है इस शख्स में। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

ओमप्रकाश गिलोत्रा
निदेशक, न्यू लाईट कलर लैब

रूपक शर्मा

2025_045

बढ़ता राजस्थान

Suduko

7	6	8	2	3	5	1		
			6				3	
	1			9	4	6		
8		9	1		2			3
		6	5	4			8	1
4		1	9			7	6	2
9	8	2			6		7	4
6		7		5		2	1	8
1	4		7		8	3	9	6

Ans_2025_044

9	6	2	1	5	3	4	8	7
4	5	8	9	2	7	1	3	6
3	7	1	8	6	4	5	9	2
8	3	6	4	7	1	9	2	5
1	2	9	3	8	5	6	7	4
5	4	7	2	9	6	3	1	8
2	8	4	5	1	9	7	6	3
7	9	5	6	3	2	8	4	1
6	1	3	7	4	8	2	5	9

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई विशिष्ट लक्षणों को लुप्त करेगा। कल आप उस लक्षण पाएंगे कि आपके जीवन के दिनों तीसरे घेरे में, जहां आपके लिए कुछ होगे और दूसरी तरफ, आपको मित्र बाधों से लाभदायक लाभ प्रतिष्ठा हाल ना दिनों हमारे साथ में और जहाँ हुई को कुछ कमी लाभदायक ऊर्जा को पाएंगे होंगे, बीच प्रतिष्ठित लोगों में रहें, जहां रह लाभदायक हमें लाभ और बाधाओं से लाभ प्राप्त करेंगे

मेष

आज आप धार्मिक काम में व्यस्त रहने वाले हैं। कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। आपकी किस्मत चमकने की पूरी संभावना है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है।

वृष

आपको शारीरिक और मानसिक सुस्ती का अनुभव होगा। मानसिक भय भी रहेगा। मां की तबीयत की चिंता आपको रहेगी। नींद पूरी नहीं होने और समय पर भोजन नहीं मिलने से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है।

मिथुन

किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिल सकता है। आपको शेयर-सट्टे के काम में आज नहीं पड़ना चाहिए। संभव हो तो यात्रा-प्रवास टालें। विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आपकी आर्थिक योजना अच्छी तरह पूरी होंगी।

कर्क

आज का दिन थोड़ा परेशानी से भरा है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खान-पान में ध्यान नहीं रखने से बीमारी के पीछे खर्च होगा। मन में नेगेटिविटी को न आने दें। पारिवारिक सदस्यों के साथ संभलकर रहना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहेगा।

सिंह

आप प्रिय पात्रों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। भागीदारों के साथ बातचीत में भी वृद्धि होगी। आप अत्यंत सुंदर पोशाक, आभूषण और भोजन का आनंद ले सकेंगे। नए वाहन खरीदने की योजना बनेगी।

कन्या

आपके घर में सुख-शांति बनी रहेगी। अच्छे अवसर आएंगे। काम में सफलता और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होगी। किसी जरूरी जगह पर खर्च की संभावना है। नौकरी में आपकी प्रगति होगी। दैनिक काम में परिस्थिति आपके अनुकूल होने से आप स्वस्थ रहेंगे।

तुला

आज आपको सावधानीपूर्वक दिन व्यतीत करना चाहिए। सर्दी-बुखार होने से आपकी तबीयत खराब होने की आशंका है। प्रिय व्यक्तियों से दूर जाना पड़ सकता है। किसी का भला करने में आपका स्वयं का नुकसान कर सकते हैं।

वृश्चिक

आप गलत जगह पैसे का निवेश न करें, विशेषज्ञ की सलाह से काम करें। आपके परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों और मित्रों के साथ आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे।

धनु

चिंता कम करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करें। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी निकटता आपको आनंदित करेगी। अपने वैवाहिक जीवन में अधिक आत्मीयता का अनुभव करेंगे।

मकर

आपको ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे। अपने सहकर्मियों एवं अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। संतान की तकलीफ चिंता का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है।

कुंभ

आपका तन-मन स्वस्थ और आनंद में रहेगा। ऑफिस में लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। अधिकारी भी आपके काम की सराहना करेंगे। प्रोत्साहन देंगे। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

मीन

आपके व्यापार-धंधे में वृद्धि होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। धंधे में संपर्क बढ़ेगा और इससे लाभ होगा। संतान और पत्नी की तरफ से अच्छे समाचार मिलने से आनंद का अनुभव करेंगे। आप सफलता प्राप्त करेंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हरीपुरा रोड खाटाश्याम,जिलाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-नन्दना पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक मो.नं.9414823448 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-झाला मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734। ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 311

यात्रा का दबाव

नवीनतम घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों में एक चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि खाद्य वस्तुओं के अलावा होने वाले औसत मासिक व्यय में सबसे अधिक हिस्सेदारी परिवहन की है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार का औसत मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एमपीसीई) 7.6 फीसदी और शहरों में 8.5 फीसदी रहा। एक स्तर पर ये आंकड़े बढ़ते आवागमन और शहरों के विस्तार को बताते हैं जिसके कारण लोगों को कामकाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

हालांकि ईंधन पर बढ़ते खर्च की लागत निस्संदेह इस लागत में बड़ी हिस्सेदार है लेकिन अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन ढांचा भी परिवारों पर लागत का बोझ बढ़ाता है। इसका परिणाम यह है कि यात्रियों को काम पर जाने के लिए महंगे निजी उपायों के भरोसे रहना होता है। जो लोग अधिक संपन्न हैं, वे अपनी कारों से आवागमन करते हैं जिससे शहरों में यातायात और प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और तेजी से विकसित होता आईटी का गढ़ बेंगलूरु इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे कमजोर शहरी परिवहन नियोजन समस्याएं पैदा कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में समस्या अधिक है क्योंकि वहां सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह नदारद है। ऐसे कई इलाकों में ट्रैक्टरों का 50 फीसदी इस्तेमाल निजी आवागमन के काम में किया जाता है। देश में सहज, किफायती और सुरक्षित परिवहन में निवेश बहुत जरूरी होता जा रहा है। अगर ऐसा होगा तभी कंपनियां न केवल कर्मचारियों को आकर्षित कर पाएंगी बल्कि इससे भी अहम कामकाज में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा होगा। उदाहरण के लिए मुंबई और कोलकाता जैसे पुराने शहरों में व्यापक ट्रेन नेटवर्क है जिसके कारण फैक्टरी और घरेलू कर्मचारी दूरदराज से काम पर आ पाते हैं।

कोलकाता के उलट मुंबई में लोकल ट्रेनों में उच्च अधिकारी भी उतने ही नजर आते हैं जितने कि फैक्टरी कर्मचारी। आंशिक रूप से आरंभ दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) पहले ही बेहतर संपर्क के लाभ दर्शा रहा है। इसके बावजूद केवल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर ही चिह्नित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश एनसीआर के आसपास संपर्क मुहैया कराते हैं। बस संपर्क भी शहरी आवागमन पर बहुत अधिक असर डाल सकता है लेकिन इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया और देश में निजी-सार्वजनिक मिलाकर 21 लाख बसें हैं जो 14 करोड़ से अधिक लोगों को सेवा देती हैं। हालांकि इस संख्या का एक तिहाई पैदल सफर करना पसंद करता है। राज्य परिवहन निगम जो गरीबों को सुविधा मुहैया कराने के लिए सब्सिडी पर यात्रा सुविधा देते हैं, उनके पास बहुत कम बसें हैं। दिल्ली में किए गए बस रैपिड ट्रांजिट के प्रयोग को जबरदस्त नाकामी हाथ लगी। आज केवल 10 शहरों में बीआरटी है और सात अन्य शहरों में यह प्रस्तावित है।

अब तक तो भारी पूंजी वाली, समय खपाऊ और यातायात बाधित करने वाली मेट्रो परियोजनाएं ही अधिकांश शहरी परिवहन नियोजकों की पसंद बनी हुई हैं। भारत में 17 शहरों में मेट्रो सेवा चल रही है लेकिन यह अपेक्षाकृत आकर्षक और आरामदेह परिवहन विकल्प भी सीमित दायरे में ही है। लंदन की ऐतिहासिक अंडरग्राउंड मेट्रो सेवा को वर्तमान नेटवर्क जैसा विस्तार पाने में 162 साल लगे। मेट्रो का किराया भी दूरी के मुताबिक 8 रुपये से 50 रुपये के बीच है। यह आम आदमी के लिए ज्यादा है। जब तक शहरी परिवहन योजना को कम लागत वाला नहीं बनाया जाता तब तक देश के परिवारों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा काम पर जाने और काम से आने में व्यय करना होगा।

विनय सिन्हा

नए बजट में सरकारी उपक्रमों पर अस्पष्टता

वर्ष 2025-26 के बजट में पीएसयू से ज्यादा लाभांश पाने की उम्मीद तो लगाई गई है मगर उनमें पहले से कम इक्विटी लगाई जानी है। विस्तार से बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रति केंद्र सरकार का रुख बदल गया है? इस माह के आरंभ में पेश किए गए 2025-26 के बजट में ऐसा ही संकेत मिलता है। पीएसयू के प्रति रुख बदला है या पहले जैसा ही है, यह समझने के लिए इस बजट के आंकड़ों को पिछले कुछ साल के आंकड़ों के साथ मिलाकर देखना सही होगा।

शुरुआत करते हैं 2019-20 से, जो नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल था और जिसके गुजरते ही अर्थव्यवस्था को कोविड का झटका लगा था। वित्तीय प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार के अधीन पीएसयू के लिए यह अच्छा साल नहीं था। सरकारी कंपनियों से केंद्र सरकार को मिलने वाला लाभांश 19 फीसदी कमी के साथ केवल 35,000 करोड़ रुपये रह गया था। इसलिए 2019-20 में जब उनका पूंजीगत व्यय भी 2 फीसदी ही बढ़कर 8.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच पाया तो हैरत नहीं हुई। इसकी एक वजह यह भी थी कि पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिए आंतरिक तथा बजट के अलावा संसाधन जुटाने की उनकी क्षमता कम रही और केवल 5 फीसदी बढ़कर 6.4 लाख करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाई।

उस समय पीएसयू के पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार का योगदान भी कम कर दिया गया था। पीएसयू के कुल व्यय में उसके द्वारा जुटाए गए आंतरिक तथा बजट से इतर संसाधन होते हैं और इक्विटी तथा कर्ज की शक्ल में सरकारी सहायता भी होती है। इन उपक्रमों के पूंजीगत व्यय में सरकार की बजट सहायता 7 फीसदी घटकर 2.1 लाख करोड़ रुपये रह गई। कुल पूंजीगत व्यय में सरकारी इक्विटी और ऋण की हिस्सेदारी भी कम होकर 25 फीसदी रह गई। इसके साथ ही 2019-20 में सरकारी उपक्रमों में विनिवेश की सरकार की योजना भी सुस्त हो गई और विनिवेश से कुल राजस्व 47 फीसदी घटकर 50,000 करोड़ रुपये रह गया।

उसके बाद पांच सालों में यानी 2024-25 तक भी रुख उत्साह बढ़ाने वाला तो नहीं रहा। सरकारी उपक्रमों का पूंजीगत व्यय 2 फीसदी से भी कम की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ा और उनके अपने संसाधन करीब 10 फीसदी तक कम हो गए। कोविड महामारी ने बेशक पीएसयू की माली हालत बिल्कुल बिगाड़ दी। किंतु इन कंपनियों और इनमें बहुलांश हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के रिश्ते काफी बदल गए।

इन पांच साल में वित्तीय स्थितियां प्रतिकूल होने पर भी पीएसयू से सरकार को मिलने वाला लाभांश 9.5 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ा। बदले में सरकार ने भी इन कंपनियों की पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिए अपने योगदान में 21 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि की। पीएसयू के पूंजीगत व्यय में सरकार की बजट सहायता 2024-25 में बढ़कर 59 फीसदी पर पहुंच गई, जो पांच साल पहले 25 फीसदी ही थी। परंतु सरकार और पीएसयू के रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव विनिवेश के क्षेत्र में आया, जिसमें पांच साल में 8 फीसदी कमी आई। दूसरे शब्दों में पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री बहुत सुस्त हो गई।

पिछले पांच साल उनसे पहले के पांच साल के काफी अलग रहे। 2014-15 से 2019-20 तक यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पीएसयू अपने पूंजीगत व्यय के लिए अधिक इंतजाम (सालाना 23 फीसदी चक्रवृद्धि) कर रहे थे और आंतरिक तथा बजट से इतर संसाधन जुटाने में भी 26 फीसदी चक्रवृद्धि हो रही थी। वे सरकार को सालाना 2 फीसदी चक्रवृद्धि के साथ कम लाभांश दे रहे थे। मगर केंद्र को इनमें विनिवेश से अधिक राजस्व (सालाना 9 फीसदी चक्रवृद्धि) मिल रहा था। इतना अधिक राजस्व तह मिल रहा था, जब सरकार पीएसयू को अधिक इक्विटी और कर्ज (सालाना 26 फीसदी चक्रवृद्धि) दे रही थी।

फिर बीते पांच साल में रुख बदल क्यों गया? विर्डबना देखिए कि विनिवेश की रफ्तार तब सुस्त हुई, जब 2021 में सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की घोषणा कर दी थी। इस नीति के तहत पीएसयू का निजीकरण और हिस्सेदारी बिक्री ऐसे होने थे कि बीमार एवं अव्यावहारिक इकाइयां बंद कर दी जाएं तथा सरकारी उपक्रम कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ही बचे रह जाएं। साथ ही सरकार उन पीएसयू से बाहर आ जाए, जो उन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं। 2021-22 के बजट में निजीकरण के लिए कई सरकारी उपक्रम गिनाए भी गए थे मगर एयर इंडिया, नीलाचल इस्पात और फेरो स्क्रैप निगम को छोड़कर किसी को निजी हाथों में नहीं सौंपा गया और विनिवेश पर भी कदम जल्द वापस ले लिए गए। जिन पीएसयू का निजीकरण होना था उनमें से कुछ को संकट से बचाने के लिए सरकार को दोबारा निवेश तक करना पड़ा।

अब पीएसयू को मूल्यवान बताने वाली सरकारी दलील में भी दम नहीं लगता। बीते पांच साल में न तो पीएसयू की लाभांश देने की क्षमता बढ़ी है और न ही पूंजीगत व्यय की योजनाओं के वास्ते आंतरिक या बजट से इतर रकम जुटाने की उनकी क्षमता बेहतर हुई है। बल्कि पिछले पांच साल में सरकार की बजट सहायता पर उनकी निर्भरता बढ़ती गई है। सरकारी स्वामित्व वाली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) जैसे उदाहरण बताते हैं कि उनका कर्ज खत्म करने के लिए अगर बैंक चोट झेलने को राजी हों तब भी केंद्र सरकार का प्रदर्शन बिगड़ेगा। अब अगर पीएसयू में इक्विटी बढ़ाने के बावजूद केंद्र को उनसे मिलने वाला लाभांश और विनिवेश से राजस्व नहीं बढ़ रहा तो पीएसयू में बने ही क्यों रहा जाए?

इस पहेली को 2025-26 के बजट में नहीं सुलझाया गया है। इसमें दिए आंकड़े कहते हैं कि पीएसयू पर केंद्र सरकार का रुख पहले की तरह ही है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि वह पीएसयू से अधिक लाभांश कमाएगी, लेकिन विनिवेश राजस्व में मामूली इजाफे का ही अनुमान है, जिसमें संपत्ति बिक्री के बजाय उनके मुद्रीकरण से कमाई पर ज्यादा भरोसा किया गया है।

पिछले कई सालों का सिलसिला तोड़ते हुए इस साल पीएसयू के पूंजीगत व्यय में इक्विटी और कर्ज के जरिये केंद्र का योगदान कम हो जाएगा। पीएसयू को उम्मीद है कि अपने पूंजीगत खर्च के लिए वे आंतरिक तथा बजट से बाहर संसाधन खुद ही जुटा लेंगी और सरकार की बजट सहायता का सहारा कम तकेंगी। 2025-26 के बजट में पीएसयू के बारे में शायद यही इकलौता परिवर्तन है।

परंतु क्या पीएसयू के रणनीतिक विनिवेश के लिए घोषित नीति पर अधिक जोर दिए जाने का कोई संकेत नजर आता है? शायद नहीं। तस्वीर पहले जैसी ही है और अगर पूंजी बाजार में पिछले कुछ महीनों की तरह उठापटक चलती रही तो किसी भी बदलाव की उम्मीद मत कीजिए।

दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के लिए सहज नहीं राह

मजा आ गया...! दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगभग 30 साल बाद सत्ता में लौटते देख पार्टी के एक पदाधिकारी ने चहकते हुए कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। मगर उस पदाधिकारी ने यह भी कहा कि धमाकेदार जीत के बाद भी नए मुख्यमंत्री की राह आसान नहीं होगी। उनका इशारा दिल्ली में जीत के बाद उभरने वाले नए सत्ता समीकरणों की तरफ था।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली के उप-राज्यपाल के अधिकारों का दायरा कई तरह से लगातार बढ़ता गया है। वर्ष 2023 में एक अध्यादेश (जो बाद में संसद में पारित किया गया) के जरिये राष्ट्रीय राजधानी नागरिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव शामिल हैं। यह प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के बारे में तथा अनुशासन से जुड़े मामलों में उप राज्यपाल को सुझाव दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण या तैनाती का अधिकार नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने 5 अगस्त, 2024 को कहा कि निगम प्रशासन की विशेष जानकारी रखने वाले 10 लोगों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नियुक्त करने का उप राज्यपाल (एलजी) का अधिकार उनके कार्यालय से जुड़ा संवैधानिक कर्तव्य है। न्यायालय ने कहा था कि वह इस विषय पर मंत्रिपरिषद के सहयोग एवं उसकी सलाह पर निर्भर नहीं हैं। यह मामला दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा था। तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने यह कहकर उनकी नियुक्तियों का विरोध किया था कि केवल कानून-व्यवस्था, पुलिस और जमीन ही केंद्र के सीधे नियंत्रण में हैं और उप राज्यपाल बाकी सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष न्यायालय ने आम आदमी पार्टी का यह तर्क नहीं माना। न्यायालय ने इसके लिए केंद्र-दिल्ली सरकार के संबंधों को निर्धारित करने वाले कानूनों और अतीत में आए उन आदेशों का हवाला दिया जिनमें निर्वाचित सरकार और नियुक्त प्रशासकों के बीच संतुलन स्थापित करने का जिक्र था।

कुछ हफ्ते बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उप राज्यपाल को संसद से पारित और दिल्ली सरकार पर लागू होने वाले किसी भी कानून के तहत कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या सांविधिक निकाय स्थापित करने का अधिकार दे दिया। आप ने इस आदेश के विरोध की कोशिश भी नहीं की क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 239 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन अधिनियम, 1991 की धारा 45डी के तहत केंद्र को यह फैसला लेने का पूरा अधिकार है।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

जब आप की सरकार थी तब भाजपा को राजधानी दिल्ली पर सख्ती से नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस हो रही थी मगर अब उसकी अपनी सरकार और मुख्यमंत्री होंगे तब भी क्या उसके लिए ये अधिकार जरूरी रहेंगे? इस सवाल पर बहस होती रहेगी मगर इससे भी जरूरी सवाल यह है कि इतने सारे अधिकारों के स्वामी होकर भी क्या उप राज्यपाल दिल्ली के शासन-प्रशासन में अब नरम रुख अख्तियार करेंगे?

दिल्ली और केंद्र के रिश्तों का एक और पहलू है, जिस पर नजर होनी चाहिए। दिल्ली प्रशासन से जुड़े अधिकतर मामले गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं। अगले कुछ सप्ताहों में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा, जिसके बाद बहुत कुछ नए भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के बीच के समीकरण पर निर्भर रहेगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष भाजपा ने ही किया था और मदन लाल खुराना ने इसका नेतृत्व किया था। जब आप सरकार की शक्तियां कम कर दी गईं तो भाजपा में ज्यादातर लोग यह सोचकर खुश थे कि दिल्ली संभालने के मामले में आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मगर भाजपा की पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के समय दिल्ली जैसी थी अब कई मामलों में उससे बदतर हो गई है। भाजपा के अध्यक्ष यह बात समझेंगे और उनके मन में सहानुभूति भी होगी। मगर क्या उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा होगा कि वह गृह मंत्री और उप राज्यपाल को समझा पाएं कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार अब राष्ट्रीय राजधानी के हित में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है?

एमसीडी फिलहाल आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में है। केंद्र के पास दो विकल्प हैं। पहला, वह एमसीडी भंग करे और नए चुनाव कराए और दूसरा, आयुक्तों के जरिये निगम चलाए। इससे सत्ता एक ही जगह केंद्रित हो जाएगी और आप सोचेंगे कि यही होना है तो एमसीडी के चुनाव कराए ही क्यों जाते हैं।

भाजपा को इस बात का पूरा एहसास है कि आप की पकड़ बिल्कुल खत्म नहीं हुई है और कांग्रेस का भी थोड़ा-बहुत आधार है। आप 14 सीटों पर जितने वोटों से हारी है, उससे ज्यादा वोट उन सीटों पर कांग्रेस को मिले हैं। कम से कम एक सीट पर मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) ने संघर्ष त्रिकोणीय बना दिया, जिससे मतों का बंटवारा हुआ और जिसका फायदा भाजपा (मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट) को हुआ। मान लेते हैं कि यह सब राजनीतिक समीकरण के बजाय महज गणित है। मगर केंद्र सरकार के समक्ष भाजपा कमजोर दिखेगी तो आप बिना समय गंवाए उससे मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर देगी। यूं भी सत्ता में रहने के बजाय विपक्ष में रहना आम आदमी पार्टी को अधिक सहज लगता है। इसकी संभावना तो नहीं है कि दिल्ली को चलाने के तौर-तरीकों में भाजपा कोई ठोस प्रशासनिक बदलाव लाएगी। लेकिन उसका शासन लोगों को कैसा नजर आए, यह उसे जरूर देखना और बदलना होगा अन्यथा मदनलाल खुराना के सभी त्याग व्यर्थ चले जाएंगे।

आपका पक्ष

मुफ्त योजनाओं के बजाय रोजगार सृजन हो

उच्चतम न्यायालय ने हाल में कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं की घोषणा के कारण परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। यह वाजिब चिंता है जिसकी बानगी है हालिया दिल्ली चुनाव जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की होड़ मची थी। रोजगार सृजन न कर पाने संबंधित अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए नकदी हस्तांतरण करना क्या सही है। भूख से नहीं मरने देने वाली यह हमदर्दी पूर्ण राजनीतिक योजना अगर सही है तो फिर एक बड़ी आबादी को इस तरह से मुफ्तखोर और अकर्मण्य बनने से रोकना होगा। सरकारों द्वारा मुफ्त योजनाएं और नकदी हस्तांतरण जैसी योजना को लागू करना घर बेचकर तीर्थ करने के समान है। अब तो मुफ्त योजनाओं को लाभार्थी वर्ग अपना अधिकार मानने लगा है। यह बात सही है कि मुफ्त योजनाएं वास्तविक जरूरतमंद के लिए संजीवनी है लेकिन वास्तविक की पहचान आसान नहीं तभी इन योजनाओं में सेंधमारी कर अपात्र लोगों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को लेकर चल रही है। ऐसे में खैरात पर जीवन जीने को प्रोत्साहित करने वाली राजनीति भविष्य में उस लक्ष्य से दूर ले जाएगी। किसी भी सरकार की कामयाबी तभी मानी जाएगी जब वहां के नागरिकों का देश के विकास में योगदान हो। ऐसे में जहां सरकार से अपेक्षा है कि वह व्यक्ति को कर्मशील बनाए रखने का प्रयास करे वहीं जनता से अपेक्षा है कि वह कमाकर खाए और स्वाभिमान से जीए तभी स्वयं व्यक्ति से लेकर देश का सर्वांगीण विकास होगा।

डॉ विकास पंडित, बड़वानी

उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं पर चिंता व्यक्त की थी

कर कानून में संशोधन से आसान बनेगी कर प्रणाली

केंद्र सरकार द्वारा आयकर व्यवस्था में सुधार के लिए 63 वर्ष पुराने आयकर कानून में संशोधन संबंधी विधेयक लोक सभा में पेश किया जाना एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार को आयकर कानून के संशोधन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी वर्ग को परेशानी न हो। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में कर प्रणाली का बड़ा योगदान होता है। लेकिन कर व्यवस्था में जन-भागीदारी बढ़ाने और कर के प्रति जन-जन को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास भी किए जाने चाहिए। देश में आयकर को लेकर बहुत सी भ्रांतियां और गलतफहमियां है। इस कारण बहुत से लोग अपना बनता आयकर देने से कतराते हैं। आयकरदाताओं को आयकर स्लैब में छूट मिलने की आस होती है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर सरकार आम बजट में आयकरदाताओं को भारी राहत देती है तो क्या हर आयकरदाता अपना आयकर सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए भी उतना उत्सुक होगा जितना कि सरकार से कर की राहत चाहता है। कर से सरकारी कोष भरने की परंपरा प्राचीन काल से राजाओं के समय से ही चली आ रही है। यह अलग बात है कि इस प्रक्रिया में अंतर आ गया है। कर एकत्र करने की प्रक्रिया को अगर और आसान बना दिया जाए तो आमजन भी कर देने के प्रति रुचि दिखाएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बेंगलूरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर तथा अन्य लोग उपस्थित थे।